डीआरडीओः सामने वजूद का संकट
दरभंगाः राज को ट्रस्टियों ने किया तबाह
फ्लूः ठीक क्यों नहीं हो रहा यह जुकाम
28 फरवरी, 2024
50 रुपए
इंडिया टुडे
पाकिस्तान
कांटों का ताज
खंडित जनादेश के बाद शहबाज शरीफ फिर बने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री. अब उनका मुकाबला, ढहती अर्थव्यवस्था, भीषण महंगाई, इमरान खान के अराजक समर्थकों और हमेशा से दबदबे वाली सेना से
RNI NO. 45823/1986 REGISTRATION NO. DL(DS)-02/MP/2022-23-24, DL(ND)-11/6042/2024-25-26; LICENSED TO POST WPP NO U(C)-31/2024-26; FARIDABAD/46/2023-25 www.indiatodayhindi.com
OC
अग्रिम सप्ताह के लिए प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित; एलपीसी दिल्ली-आरएमएस-दिल्ली-110006 से प्रत्येक शनिवार और सोमवार को प्रेषित; कुल पन्नों की संख्या 92 (आवरण सहित) वर्ष 38; अंक: 13

प्रधान संपादक की कलम से

पाकिस्तान का इतिहास बोन्साइ लोकतंत्र का रहा है. फौजी हुकूमत के बीच यदा-कदा चुनावों के हिचकोले खाता. हालांकि कभी-कभार बोन्साइ में भी अप्रत्याशित तौर पर अखुए निकलने से वह अपने बागबान (पढ़ें फौज) को भी चकित कर सकता है. हैरतअंगेज चुनाव नतीजों के साथ 11 फरवरी को यही हुआ. स्वघोषित पुनर्जागरण के करिश्माई लेकिन गुमराह नायक इमरान खान ने सारी नाउम्मीदी को धता बताते हुए मैच तकरीबन जीत ही लिया. पाकिस्तान के मामले में इन दिनों इस नाउम्मीदी का मतलब है फौज के मुखिया जनरल असीम मुनीर, तमाम सियासी तकदीरों के निर्णायक.

दिलेर और तेजतर्रार पूर्व क्रिकेट कप्तान को उसी फौज के साथ टकराव के बाद अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटा दिया गया था, जिसने 2018 में उन्हें सहारा देकर इस गद्दी तक पहुंचाया था. वे अगस्त 2023 से गिरफ्तार हैं और एक के बाद एक तीन मामलों में जुर्म साबित होने के बाद सजा काट रहे हैं, जो 14 साल चलेगी. उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) को चुनाव लड़ने से बाकायदा रोका गया—उसका चुनाव चिह्न क्रिकेट बैट जब्त कर लिया गया. फिर भी इमरान जेल के भीतर से अपने दुश्मनों को मुंह चिढ़ाने में कामयाब रहे. निर्दलीय चुनाव लड़ने को मजबूर पीटीआइ के लोगों ने नेशनल एसेंबली की 266 में से 93 सीटें जीत लीं. हालांकि वे बहुमत के लिए जरूरी 134 सीटों से काफी पीछे रह गए, पर उनकी सीट हिस्सेदारी तमाम पार्टियों में सबसे ज्यादा है. नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) ने महज 75 सीटें जीतीं. बिलावल भुट्टो की अगुआई वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) 54 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर रही.

इस बीच अपने तीसरे कार्यकाल के आखिरी साल 2017 में प्रधानमंत्री की कुर्सी से बेदखल कर दिए गए नवाज को चार साल के निर्वासन सहित बीते छह साल का ज्यादातर वक्त शर्म और जलालत में बिताने के बाद बहाल कर दिया गया. उनके साबित अपराधों और कदाचारों को, फौज के आला अफसरों के साथ उनकी अदावतों और झगड़ों को इसलिए माफ कर दिया गया ताकि फौजी निजाम इमरान को सियासी मात दे सके.

खंडित जनादेश के इस भूत ने साथ-साथ हुए विधानसभाओं के चुनावों को भी जद में ले लिया. पीटीआइ ने उसमें भी नैतिक जीत हासिल की. खैबर पख्तूनख्वा में 115 सामान्य सीटों में से 84 जीतकर उसने न केवल जबरदस्त बहुमत पाया बल्कि सरहदी सूबे के प्रशासन पर नियंत्रण की कतार में आ गई. पीएमएल-एन के लिए शर्मनाक था कि पीटीआइ ने उसके आंगन पंजाब में वोट बांटकर 297 सामान्य सीटों में से पीएमएल-एन की 137 सीटों के बरअक्स 116 सीटें जीत लीं, जिससे दोनों ही नियंत्रण की स्थिति में न रहे. मगर पीएमएल-एन की सीटें इतनी तो हैं ही कि वह गठबंधन का तानाबाना बुन कर सियासी तौर पर पाकिस्तान के सबसे ताकतवर प्रांत में हुकूमत कर सके. पाकिस्तान की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी पीपीपी ने 130 में से 84 सीटें जीतकर सिंध प्रांत के अपने मजबूत गढ़ पर कब्जा बरकरार रखा. बलूचिस्तान में वोट रहस्यमय ढंग से तितरफा बंट गए.

कुल मिलाकर गहरे तक बंटा हुआ सियासी सिनैरियो बौनी शख्सियतों से भरा था. इससे फौज के लिए एक-दूसरे पर निर्भर पार्टियों को गठबंधन में आने के लिए राजी करके सारी प्रक्रिया पर अपने प्रभुत्व की मोहर लगाना आसान हो गया. नतीजा यह कि पीएमएल-एन और पीपीपी ने हाथ मिला लिए, उसी तरह जैसे उन्होंने 2022 में इमरान को सत्ता से बेदखल करने के फौरन बाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) बनाकर किया था. समझौता वार्ताओं के मुश्किल दौर के बाद नवाज शरीफ ने इस मांग के आगे घुटने टेक दिए कि उनके भाई शहबाज को प्रधानमंत्री बनाया जाए, जबकि उनकी बेटी मरियम को पंजाब की मुख्यमंत्री बनने का इनाम दिया गया. वतन लौटने के बाद नवाज के कई लक्ष्यों में से एक बेटी को पार्टी की नेता के रूप में उत्तराधिकार सौंपना था. खंडित जनादेश को देखते हुए उनके पीछे हटने के कदम को इस तरह देखा गया कि शहबाज के लिए हालात मुश्किल होने की स्थिति में वे खुद को रिजर्व में रख रहे हैं. फौज के साथ शहबाज के संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं. मुनीर भी उनके साथ काम करते हुए सहज हैं.

बिलावल की अगुआई वाली पीपीपी ने भी अपने पत्ते बहुत एहतियात से खेले. उसने राष्ट्रपति, नेशनल एसेंबली के स्पीकर, सीनेट के सद्र और चारों प्रांतों के गवर्नर सहित सभी अहम संवैधानिक पद उसे दिए जाने की मांग की. पार्टी मंत्रिमंडल में पद मांगे बगैर पीडीएम 2.0 गठबंधन को बाहर से ही समर्थन का मंसूबा भी बना रही है. इरादा यह है कि नई सरकार को मिलने वाली किसी भी अलोकप्रियता से वह अपने को दूर रखे और अगर हालात बिगड़ते हैं तो अपने सत्ता में आने का मौका बनाए रखे.

बिलावल को पता है कि शहबाज के सिर पर कांटों का ताज है. पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बस एक धागे से लटकी है: वृद्धि गोते लगा रही है, महंगाई करीब 40 फीसद, बाहरी कर्ज पिछले साल जीडीपी का 36.5 फीसद था और जून तक बढ़कर 24 अरब डॉलर पर पहुंच जाएगा. इसलिए आइएमएफ, जिसका बेलआउट पैकेज मार्च में आने वाला है, और चीन तथा सऊदी अरब सरीखे दूसरे दानी मदद का हाथ बढ़ाने से पहले अपने हिस्से की कीमत वसूलेंगे. शरीफ परिवार के लिए यह अग्निपरीक्षा होगी. जेल में होते हुए भी इमरान का साया मंडरा रहा है. फौज पिछली गर्मियों में पीटीआइ की भीड़ के हाथों उसके खिलाफ किए गए अराजक 'विद्रोह' को न भूली है, न ही उन्हें माफ किया है. अब तो उनके पास उस नाफरमानी का लोकतांत्रिक रिप्ले भी है जिसमें पीटीआइ ने डिजिटल गुरिल्ला तरकीबों से मीडिया के ब्लैकआउट को मात दे दी और जिसमें एआइ से रचे गए इमरान भी थे. ऐसे प्रत्याशित अनुष्ठानों की पूरी संभावना है जिनके जरिए फौज इमरान के संसदीय दबदबे को बेअसर करने की खातिर उनके समर्थित निर्दलीयों को नए 'सम्राट की पार्टी' के पक्ष में अपनी वफादारियां बदलने के लिए उकसाएगी.

29 मार्च, 2023

मगर ध्यान रहे, 'प्रतिष्ठान' खुद को हर जगह प्रतिष्ठापित रखने में माहिर है. इस हफ्ते हमारी आवरण कथा कराची के पत्रकार हसन जैदी ने लिखी है. इस नए सियासी ड्रामे को देखते हुए बस एक तथ्य दिमाग में रखिए: आजादी के बाद पाकिस्तान का एक भी प्रधानमंत्री पांच साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया. इस बीच भारत और पाकिस्तान के रिश्ते 2019 में नए रसातल में पहुंच गए. भारत ने अनुच्छेद 370 क्या खत्म किया कि पाकिस्तान ने गुस्से में भारत के इस्लामाबाद स्थित उच्चायुक्त को निकाल दिया और व्यापार, परिवहन तथा संस्कृति से जुड़े सारे ताल्लुक तोड़ लिए. तभी से पाकिस्तान रिश्ते बहाल करने के लिए मूल मुद्दे के तौर पर कश्मीर को सुलझाने पर अड़ा है. भारत का नजरिया यह है कि वह पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने का इच्छुक है, पर दिल्ली को बातचीत की मेज पर लाने के लिए पाकिस्तान को सीमा-पार आतंकवाद के इस्तेमाल की अपनी मूल नीति से बाज आना होगा. दिक्कत हमेशा यह रही है कि भारत के प्रति दुश्मनी ही पाकिस्तानी फौज का सबब और मकसद है. अलबत्ता इस्लामाबाद का हर नया निजाम बदलाव की उम्मीद भरी सुनहरी किरण लेकर आता है, लिहाजा भारत इंतजार करना चाहेगा.

(अरुण पुरी)

www.indiatodayhindi.com

चेयरमैन और प्रधान संपादकः अरुण पुरी
वाइस चेयरपर्सन और कार्यकारी प्रधान संपादकः कली पुरी
ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसरः दिनेश भाटिया
ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टरः राज चेंगप्पा
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसरः मनोज शर्मा
एडिटरः सौरभ द्विवेदी
डिप्टी एडिटरः मोहम्मद वक़ास
सीनियर एसोसिएट एडिटरः शिवकेश मिश्र, प्रतीक्षा
एसोसिएट एडिटरः पवन वर्मा
असिस्टेंट एडिटरः मनीष दीक्षित, सुमित सिंह
वरिष्ठ विशेष संवाददाताः हिमांशु शेखर
राज्य ब्यूरोः आशीष मिश्र (लखनऊ), पुष्यमित्र (पटना), आनंद चौधरी (जयपुर), देवेश तिवारी (रायपुर), एम.जी. अरुण (मुंबई), राहुल नरोन्हा (भोपाल), अमरनाथ के. मेनन (हैदराबाद)
ग्रुप क्रिएटिव एडिटरः नीलांजन दास
एसोसिएट आर्ट डायरेक्टरः चंद्रमोहन ज्योति
असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टरः असित रॉय
ग्रुप फोटो एडिटरः बंदीप सिंह
फोटो डिपार्टमेंटः चंद्रदीप कुमार, राजवंत रावत मंदार सुरेश देवधर (मुंबई)
डिप्टी विजुअल रिसर्च एडिटरः प्रभाकर तिवारी
प्रिंसिपल फोटो रिसर्चरः सलोनी वैद
प्रोडक्शन चीफः अभिनव पुगला
सीनियर एसोसिएट पब्लिशर (इंपैक्ट): सुपर्णा कुमार
इंपैक्ट टीम
सीनियर जनरल मैनेजरः मयूर रस्तोगी (नॉर्थ ऐंड ईस्ट), जीतेंद्र लाड (वेस्ट)
जनरल मैनेजरः सैयद नवीद (चेन्नै), अरुप चौधरी (बेंगलूरू)
ग्रुप चीफ मार्केटिंग ऑफिसरः विवेक मल्होत्रा
सेल्स एवं ऑपरेशन
सीनियर जनरल मैनेजरः दीपक भट्ट (नेशनल सेल्स)
जनरल मैनेजरः विपिन बग्गा (ऑपरेशंस)
डिप्टी जनरल मैनेजरः राजीव गांधी (नॉर्थ)
डिप्टी रीजनल सेल्स मैनेजरः योगेश गोधनलाल गौतम (वेस्ट)
डिप्टी रीजनल सेल्स मैनेजरः एस. परमशिवम (साउथ)

वर्षः 38; अंकः 13; 22-28, फरवरी 2024; प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित

● **संपादकीय कॉर्पोरेट कार्यालयः** लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, इंडिया टुडे ग्रुप मीडियाप्लेक्स, एफसी-8, सेक्टर 16-ए, फिल्म सिटी, नोएडा-201301, फोनः 0120-4807100;
● **ग्राहकी चंदा भेजें:** इंडिया टुडे (हिंदी), पो. बॉक्स 114, नई दिल्ली-110001
● **ग्राहक सेवाः** कस्टमर केयर, इंडिया टुडे ग्रुप, सी-9, सेक्टर-10, नोएडा (उत्तर प्रदेश)-201301, ई-मेलः wecare@intoday.com फोन/व्हाट्सऐपः +91 8597 778778 (सोमवार से शुक्रवार, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक)
● **सर्कुलेशन कार्यालयः** लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, सी-9, सेक्टर-10, नोएडा (उत्तर प्रदेश)-201301
● **इंपैक्ट कार्यालयः** 1201, 12वां तल, टावर 2ए, वन इंडियाबुल्स सेंटर, (जुपिटर मिल्स) एस.बी. मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम)-मुंबई-400013. फोनः 022-69193355 फैक्सः 022-66063226
● **क्षेत्रीय विज्ञापन कार्यालयः** ए1-ए2, एनके सेंटर, विनुज्य निकुंज, उद्योग विहार, फेज-5, गुड़गांव, हरियाणा, फोनः 0124-4948400;
● 201-204 रिचमंड टावर्स, द्वितीय मंजिल, 12 रिचमंड रोड, बंगलुरू-560 025 फोनः 2212448, 226233, टेलेक्सः 0845-2217 INTO IN. फैक्सः 080-2218335.
● रजिस्टर्ड कार्यालयः एफ-26, फर्स्ट फ्लोर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

● **लिविंग मीडिया इंडिया लि. के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक मनोज शर्मा द्वारा एफ-26, फर्स्ट फ्लोर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और थॉमसन प्रेस इंडिया लि., 18-35, माइलस्टोन, दिल्ली-मथुरा रोड, फरीदाबाद-121 007 (हरियाणा) में मुद्रित. संपादकः राज चेंगप्पा**

28

एपी

आवरण : नीलांजन दास

सब बेअसर
शंभू बॉर्डर पर 13 फरवरी को आंसू गैस का सामना करते किसान

एएनआइ

किसान आंदोलन

अन्नदाता फिर आक्रोश में

अनिलेश एस. महाजन

पंजाब-हरियाणा की सीमा के पास पटियाला के शंभू में भारी-भरकम ट्रैक्टर बड़ी संख्या में जमा हैं. ऊंची आवाज में बजते गीतों में दिल्ली (केंद्र) को नतीजे भुगतने की चेतावनी दी जा रही है और जट सिख समुदाय की बहादुरी का बखान किया जा रहा है. गरजते हुए यह काफिला 13 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी को घेरने निकला था. विरोध कर रहे किसानों का दावा है कि वे अपने साथ महीनों तक का राशन और डीजल लेकर चल रहे हैं. ठीक उसी समय आकाश से आंसू गैस के गोलों की बारिश होने लगी, जिनको बैरिकेड की रक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों ने ड्रोन से दागा था.

यह सारी सीनरी 13 महीने पहले (सितंबर 2020 से नवंबर 2021) के राष्ट्रीय राजधानी के घेराव की याद दिला रही थी. फर्क इतना ही था कि किसान अभी दिल्ली के दरवाजे तक नहीं पहुंचे थे. उस वक्त के घेराव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीछे हटने और कृषि क्षेत्र के बड़े सुधारों को वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा था. आम चुनाव कुछ ही महीने दूर हैं और लंबे विरोध की धमकी ने सत्तारूढ़ भाजपा को खासी फिक्र में डाल दिया है. आम आदमी पार्टी नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की मध्यस्थता में किसान संगठनों की केंद्रीय मंत्रियों पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा

के साथ अभी तक दो दौर की बातचीत हो चुकी है पर बेनतीजा रही है.

हालांकि इस बार भाजपा की अगुआई वाली केंद्र सरकार ने विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों से निबटने को बेहतर तैयारी की है. उसने उनको शंभू और खनौरी सीमा पर रोक दिया है और ट्रैक्टर ट्रॉलियों को दिल्ली पहुंचने से रोक रही है. दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा से सटी सीमा को सील कर दिया है. इस बीच, चंडीगढ़ में मामला हाइ कोर्ट पहुंच गया है जहां याचिकाकर्ताओं ने किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए लगाई गई सभी बाधाएं हटाने की मांग की है.

इस सबसे ऐसे समय मजा खराब हुआ है जब प्रधानमंत्री और भाजपा ने यह सोचा था कि उन्होंने उत्तर में कृषक समुदाय का समर्थन जुटा लिया है. हाल में भाजपा सरकार ने किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया जिससे इस दिग्गज किसान नेता के पोते जयंत चौधरी और उनके राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) को एनडीए में लाने में मदद मिली (लक्ष्य उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट मतदाता हैं जहां रालोद प्रमुख पार्टी है). किसानों का विरोध अगर बढ़ा तो इस गठजोड़ पर भी असर डाल सकता है. इन विरोधों का राजनैतिक असर पंजाब में पहले ही हो चुका है और राज्य में गठजोड़ के लिए अकाली दल के साथ भाजपा की बातचीत पटरी से उतर गई है. हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी के साथ भी रिश्तों में तनाव आ सकता है. जेजेपी पहले से ही भाजपा से नाराज है क्योंकि भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा में सीटों के तालमेल पर बातचीत करने से इनकार कर दिया है.

भाजपा को घेरने के लिए विपक्ष ने भी मौका नहीं गंवाया. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तुरंत ही किसानों का समर्थन किया जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसानों से मिलने के लिए अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा बीच में ही रोक दी. आप भी मैदान में कूद गई और उसने दिल्ली के बाहरी इलाके बवाना के स्टेडियम को प्रदर्शनकारियों के लिए अस्थायी जेल में बदलने के केंद्र के अनुरोध को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वे लोग देश के अन्नदाता हैं और उनसे ऐसा घटिया व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए.

भाजपा की चुनौतियां कई गुना ज्यादा हैं क्योंकि पार्टी ने पिछले दो साल में पंजाब में जिन भी जट सिख नेताओं को तोड़ अपने साथ जोड़ा, वे इन किसान नेताओं से जुड़ नहीं पाए हैं. इस बार मोर्चा संभाल रहे किसान नेताओं में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सर्वन सिंह पंधेर, भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू)-दोआबा के मनजीत सिंह राय, बीकेयू (एकता सिधुपुर) के जगजीत सिंह दल्लेवाल और लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी के बलदेव सिंह सिरसा शामिल हैं जो किसान संगठनों में दूसरी कतार के नेता हैं. इन विरोधों का अभी पूरे पंजाब में असर नहीं हुआ है पर अगर टकराव बरकरार रहा तो कुछ लोगों का मानना है कि गुस्सा हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक में फैल सकता है. अभी तक इन राज्यों के किसान संगठनों ने आंदोलन को सिर्फ नैतिक समर्थन दिया है.

बातचीत भी मुश्किल है क्योंकि किसान संगठनों की कुछ मांगें ऐसी हैं जिनका कोई आसान हल नहीं है और उनमें राज्य भी शामिल हैं. मसलन, 60 साल से ऊपर के किसानों और कृषि मजदूरों को हर महीने 10,000 रु. पेंशन देने की मांग. हाल के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भाजपा ने भूमिहीन कृषि मजदूरों को हर साल 10,000 रु. देने का वादा किया था. लेकिन यह पैसा राज्य के खजाने से दिया जाना है. मांगों की सूची खासी लंबी है (देखें बॉक्स). मुख्य मांग सभी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए कानूनी गारंटी की है, जिसकी गणना 2004 में स्वामीनाथन आयोग के सुझाए फॉर्मूले के हिसाब से की जानी चाहिए. इसमें जमीन का किराया जैसी पूंजी लागत (सी 2) को भी जोड़ने की बात है जबकि मोदी सरकार ने कमतर फॉर्मूला (ए 2+एफ एल) अपनाया है, जिसमें परिवार के श्रम सहित सभी तरह की लागत शामिल है. (एक चुनौती यह है कि हर राज्य में दरें अलग-अलग हैं). किसान संगठन सभी कर्जों की पूरी तरह माफी, किसी भी तरह की कृषि भूमि के अधिग्रहण के लिए बढ़ा हुआ मुआवजा, वन संरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2023 की वापसी की मांग कर रहे हैं. एक मांग जो गैर वाजिब लगती है, वह है कि भारत विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) से अलग हो जाए. इसके अलावा 2021 की लखीमपुर खीरी घटना में मारे गए किसानों के लिए न्याय की मांग भी शामिल है.

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कहते हैं, "विरोध कर रहे किसानों को समझना चाहिए कि अगर वे नई मांगें जोड़ते रहे तो इससे गतिरोध बढ़ेगा और समाधान में समय लगेगा. अगर आप डब्ल्यूटीओ से भारत के अलग होने की बात कर रहे हैं और स्वतंत्र व्यापार समझौतों को खत्म करने की बात करते हैं, अगर आप स्मार्ट मीटर लगाने से रोकना चाहते हैं, पराली जलाने के मसले को बाहर रखने की मांग कर रहे हैं या जलवायु मुद्दे से कृषि को बाहर रखने की बात है, तो ये सब फैसले एकतरफा तरीके से नहीं लिए जा सकते. इनमें कई चीजें दांव पर लगी हैं." सत्तारूढ़ भाजपा को अभी भी इस मसले को राजनैतिक और नीतिगत तरीके से संभलकर हल करना होगा. और उन्हें यह काम जल्दी ही करना पड़ेगा.

मुख्य मांगें

- सभी फसलों के लिए कानूनी गारंटी (एमएसपी) 2021 के विरोध प्रदर्शन की वापसी के समय मुख्य शर्त थी
- 2021 में लखीमपुर खीरी घटना में मारे गए किसानों को न्याय और मुआवजा. वहां एक केंद्रीय मंत्री के बेटे ने कथित तौर पर चार किसानों को कुचल दिया था
- 2021 के विरोध के दौरान किसानों पर दर्ज सभी मामलों की वापसी और मृतकों के परिवारों को मुआवजा
- सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए अधिग्रहीत भूमि के लिए बढ़ा मुआवजा, भूस्वामियों के परिवारों के लिए 10 फीसद आवासीय भूखंड
- 60 साल से ऊपर के किसानों को 10,000 रु. महीने पेंशन
- डब्ल्यूटीओ से भारत बाहर निकले, सभी मुक्त व्यापार समझौते खारिज हों
- विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द करने की मांग क्योंकि बिजली क्षेत्र का लगातार निजीकरण किया जा रहा

बातचीत में पेच फंस गया है क्योंकि किसान संगठन जो मांग कर रहे हैं उनमें से कुछ का जवाब तलाशना इतना आसान नहीं है

आक्रोश
लद्दाख में लोगों का विरोध प्रदर्शन

एएनआइ

लद्दाख

लद्दाख में आंच

मोअज्जम मोहम्मद, श्रीनगर में

करगिल में पिछले साल अक्तूबर में हुए लद्दाख स्वायत्तशासी पर्वतीय विकास परिषद के चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) और कांग्रेस गठजोड़ की जोरदार जीत ने यह संकेत दिया था कि स्थानीय भावनाओं में भारी बदलाव आया है. एकदम स्थानीय स्तर के चुनाव में इस जीत को केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ गुस्से पर मुहर के तौर पर देखा गया, खासतौर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद. यह हार उस समय हुई जब भगवा पार्टी इस इलाके में अपना आधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है और जिसे कई विकास कार्य कराने का श्रेय है. इनमें लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी करना भी शामिल है.

करीब छह महीने बाद यह क्षेत्र लोकसभा चुनाव से पहले फिर से असंतोष का सामना कर रहा है. 3 फरवरी को जमा देने वाली सर्दी के दिन लेह में एनडीएस स्टेडियम से लेकर पोलो ग्राउंड की सुनसान सड़कों पर विशाल विरोध प्रदर्शन निकाला गया, जिसमें शामिल लोगों ने अपनी मांगों को नए सिरे से उठाया. दूरदराज के गांवों से आए लोग भी इसमें शामिल हुए और लेह पूरी तरह बंद रहा. उनकी मांगें पांच मसलों को लेकर हैं—राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा, स्थानीय युवाओं की भर्ती और नौकरियों में आरक्षण, लोक सेवा आयोग का गठन और राज्य से संसदीय सीटों की संख्या एक से बढ़ाकर दो करना.

लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक एलायंस के नेतृत्व में इस विरोध प्रदर्शन को भाजपा को छोड़कर अन्य सभी दलों का समर्थन मिला. ऐतिहासिक रूप से देखें तो लद्दाख के दो जिलों-बौद्ध बहुल लेह और मुस्लिम बहुल करगिल का ज्यादातर मसलों पर राजनैतिक और विचारधारा के तौर पर अलग-अलग नजरिया है. फिर भी दोनों जिलों के सभी धार्मिक और राजनैतिक दलों ने साथ जुटकर एक गठजोड़ बनाया और अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए शपथ ली.

शिक्षाविद् और इनोवेटर सोनम वांगचुक, जो 3 फरवरी के लेह मार्च के अगुआ लोगों में शामिल थे, भी लद्दाख के साथ अपने वादे पूरे न करने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर आरोप लगाने से नहीं हिचकते. मेगसायसाय पुरस्कार से सम्मानित वांगचुक शुरू में केंद्र शासित दर्जे का उत्साह के साथ समर्थन कर रहे थे, पर अब कहते हैं, ''हमको विरोध प्रदर्शन के लिए मजबूर किया गया क्योंकि लद्दाख एपेक्स बॉडी की मांगों के प्रति केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोई जवाब नहीं दिया. इस बीच भाजपा के स्थानीय नेता अफवाह फैला रहे थे कि इस मांग को न के बराबर समर्थन प्राप्त है. हमने प्रदर्शन यह दिखाने के लिए किया कि लद्दाख में हर कोई हमारा समर्थन कर रहा है. मौजूदा व्यवस्था में हम असहाय हैं क्योंकि हमारे भाग्य का फैसला उपराज्यपाल की ओर से किया जाता है.''

लद्दाख के पुराने स्वरूप में करगिल और लेह जम्मू-कश्मीर विधानसभा के लिए दो विधायक चुनकर भेजते थे. जम्मू-कश्मीर के विभाजन और उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट देने के बाद लद्दाख का कोई विधायक प्रतिनिधित्व नहीं है. वांगचुक ने घोषणा की है कि अगर दिल्ली में 19 फरवरी की अगली बैठक में केंद्र सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो वे आमरण अनशन करेंगे. पूर्व भाजपा सांसद और लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष थपस्तान चेवांग के नेतृत्व वाली लद्दाख एपेक्स बॉडी लद्दाख के लिए बनी उच्च अधिकार प्राप्त समिति के सदस्यों के साथ बैठक में शामिल होगी. समिति का नेतृत्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय के पास है.

वांगचुक कहते हैं कि बिगड़ता पर्यावरण भी उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. वांगचुक, जिनके जीवन पर आधारित पात्र की भूमिका *थ्री इडियट्स* फिल्म में आमिर खान ने निभाई थी, कहते हैं, ''हमारी पारिस्थितिकी बहुत ही नाजुक है. ग्लेशियर हाइवे के पास पीछे हट रहे हैं और अगर यहां पर उद्योगों को परिचालन की इजाजत दी गई तो तबाही मच जाएगी. हमारे सभी जल संसाधन सूख जाएंगे.'' वे कहते हैं, ''हम अपनी पहचान और पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा के लिए छठी अनुसूची चाहते हैं. कई उद्योग, होटल और बहुराष्ट्रीय कंपनियां लद्दाख में कारोबार करने के लिए दरवाजे पर खड़ी हैं. इससे पहले उपराज्यपाल ने जब औद्योगिक नीति की घोषणा की तो हमारे विरोध के बाद उसे वापस लेना पड़ा. यही कारण है कि हमारे क्षेत्र की रक्षा के लिए अनुसूची बहुत ही महत्वपूर्ण है.''

यह मसला लोकसभा चुनाव में भी बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है और भाजपा की चुनावी संभावना में उलटफेर कर सकता है. विपक्ष भी उसके खिलाफ संयुक्त उम्मीदवार देने की कोशिश कर रहा है

लद्दाख की आबादी में 97 फीसद जनजाति (इनमें बल्ती, बेडा, बोट बोटो, ब्रोक्पा, द्रोक्पा, दार्ड, शिन, चांग्पा, गारा, मोन और पुरिग्पा शामिल) हैं और छठी अनुसूची इनकी जमीन की रक्षा कर सकती है. संवैधानिक प्रावधान है कि जिस क्षेत्र में 50 फीसद या अधिक जनजातियां हैं, वहां स्वायत्तशासी प्रशासनिक जिला परिषद गठित की जा सकती हैं और उसको प्रशासनिक तथा विधायी स्वायत्तता दी जा सकती है. यह इस इलाके की विशिष्ट संस्कृति, जमीन के अधिकारों के साथ कृषि अधिकार, त्वरित विकास के लिए धन का हस्तांतरण और ऐसे अन्य मामलों में रक्षा कवच का काम करेगा. डॉक्टर नंद कुमार साय के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने पिछले साल सितंबर में लद्दाख के लिए छठी अनुसूची की सिफारिश की थी. इस समय मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय इलाकों में 10 स्वायत्तशासी विकास परिषदें मौजूद हैं.

यह मसला लोकसभा चुनाव में भी बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है और भाजपा की चुनावी संभावना में उलटफेर कर सकता है. विपक्ष का गठजोड़ भी भगवा पार्टी के खिलाफ संयुक्त उम्मीदवार देने की कोशिश कर रहा है. इस समय लद्दाख लोकसभा सीट भाजपा के पास है. 2019 के भाजपा के चुनाव घोषणापत्र की ओर इशारा करते हुए वांगचुक कहते हैं कि उन्होंने वादा किया था कि इस क्षेत्र को छठी अनुसूची में शामिल किया जाएगा. उनका कहना है, ''इसका असर सिर्फ चुनाव तक ही नहीं होगा. बल्कि देश के बाकी हिस्सों में भी हो सकता है कि कैसे सत्तारूढ़ पार्टी अपने वादे से पीछे हट गई है.''

राजनैतिक कार्यकर्ता सज्जाद करगिली, जो उच्च अधिकार प्राप्त समिति की पिछली बैठक में शामिल हुए थे, का कहना है कि अभी तक सरकार की प्रतिक्रिया ठंडी रही है. वे क्षेत्र में बेरोजगारी की बढ़ती दर से चिंतित हैं. उन्होंने केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि लद्दाख में 26 फीसद से अधिक स्नातक बेरोजगार हैं. वे कहते हैं, ''फिर भी सरकार ने हमारे मसलों को हल करने के लिए कुछ नहीं किया. रोजगार नहीं होने से हमारे युवा निराश हैं. हमारी मांगें संवैधानिक अधिकारों के तहत हैं. उन्होंने लोक सेवा आयोग का गठन भी नहीं किया और न ही नौकरियों में आरक्षण दिया है.''

भाजपा के स्थानीय नेता इस बात से सहमत हैं कि जमीनी स्तर पर उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, मगर उन्हें यह भी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए पुख्ता उपाय जरूर करेगी. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष फुनचोक स्टेन्जिन कहते हैं, ''सरकार ने नौकरियों के लिए लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया है. इसी तरह केंद्र सरकार किसी न किसी प्रावधान के जरिए हमारी पहचान और पर्यावरण की भी सुरक्षा करेगी, फिर चाहे यह छठी अनुसूची हो या अनुच्छेद 371.'' उनका कहना है, ''हम उम्मीद कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले कुछ न कुछ जरूर किया जाएगा.'' ऐसा लगता है कि लद्दाख के लोग भी इसी पर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आम चुनाव केंद्र सरकार को मजबूर करेंगे और उन्हें कुछ राहत मिल जाएगी. ■

सियासी शतरंज

8 फरवरी को जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यूपीए सरकार के दौरान ''शासन, आर्थिक और राजकोषीय संकटों'' और अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए उठाए गए कदमों पर संसद में व्हाइट पेपर (श्वेत पत्र) पेश कर रही थीं, कुछ ही घंटे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एनडीए सरकार की नाकामियों को उजागर करते हुए एक श्याम पत्र (ब्लैक पेपर) जारी किया और पिछले के 10 साल को ''अन्याय का युग'' बताया. दोनों दस्तावेज से कुछ खास बातें चुनकर, दावों के प्रासंगिक अंश.

विपुल ग्रोवर

(बाएं) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण; कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे

आर्थिक वृद्धि

व्हाइट पेपर

''2014 से भारतीय अर्थव्यवस्था में कई संरचनात्मक सुधार हुए हैं, जिनसे व्यापक अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल्स को मजबूती मिली है. सुधारों के फलस्वरूप भारत 'कमजोर पांच देशों' के समूह से निकलकर एक ही दशक में 'शीर्ष पांच देशों' की श्रेणी में शामिल हो गया, बाहरी मोर्चे की अप्रत्याशित बाधाओं के बावजूद ऐसा हुआ.''
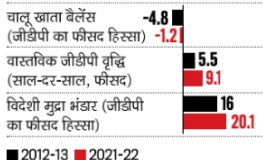
ब्लैक पेपर

(इसमें वृद्धि के आंकड़ों का जिक्र नहीं है, इसके बजाए ''आर्थिक अन्यायों'' पर फोकस किया गया है.) ''मोदी सरकार का कार्यकाल बेरोजगारी की ऊंची दर, नोटबंदी और खामियों वाले जीएसटी जैसे आर्थिक संकटों से भरा हुआ है, जिससे गरीब और अमीर के बीच खाई और बढ़ी है और करोड़ों किसानों और दिहाड़ी मजदूरों का भविष्य तबाह हुआ है.''

रोजगार

व्हाइट पेपर

''यूपीए सरकार की नीतिगत निष्क्रियता और गलत कदमों के कारण बहुमूल्य निजी निवेश रुक गया जिससे विकास और रोजगार का सृजन होता'' (पत्र रोजगार के आंकड़ों और रोजगार सृजन के लिए मोदी सरकार के उठाए कदमों पर खामोश है).

ब्लैक पेपर

''प्रधानमंत्री मोदी हर साल 2 करोड़ रोजगार पैदा करने के अपने वादे में पूरी तरह नाकाम हुए हैं. 2012 में कुल बेरोजगारी एक करोड़ थी लेकिन 2022 में बढ़कर 4 करोड़ हो गई. केंद्र सरकार में स्वीकृत 10 लाख पद खाली पड़े हुए हैं. ''

मुद्रास्फीति

व्हाइट पेपर

''2009 और 2014 के बीच मुद्रास्फीति बेकाबू थी. वित्त वर्ष 09 से वित्त वर्ष 14 के बीच के 6 वर्ष में ऊंचे राजकोषीय घाटे ने संकट में इजाफा किया.पांच साल के दौरान औसत वार्षिक मुद्रास्फीति की दर दोहरे अंक में थी.''
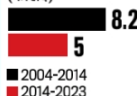
ब्लैक पेपर

''रोजमर्रा की जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं. करोड़ों परिवार पीड़ित हैं, विशेषकर महिलाएं जो अक्सर घरेलू बजट संभालती हैं.''

	2014	2024	उछाल
एलपीजी (रु. प्रति सिलेंडर)	410	903	▲120%
डीजल (रु. प्रति लीटर)	55	90	▲64%
दूध (रु. प्रति लीटर)	35	60	▲71%
सरसों तेल (रु. प्रति किलो)	90	143	▲59%
आटा (रु. प्रति किलो)	22	35	▲59%
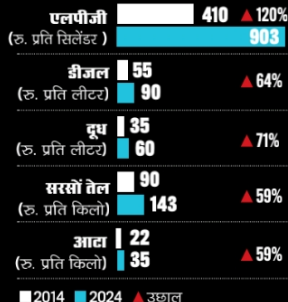
टैक्सेशन

व्हाइट पेपर

"जीएसटी लागू होने से पहले कई तरह के राज्य उपशुल्क, 440 से अधिक कर की दरें, उत्पाद शुल्क और बहुत सारी एजेंसियों की अनुपालन के चलते आंतरिक व्यापार न संगठित था, न ही स्वतंत्र. जीएसटी ने दिसंबर 2017 से मार्च 2023 तक परिवारों को हर महीने करीब 45,000 करोड़ रुपए बचाने में मदद की."

औसत टैक्स-जीडीपी अनुपात

*कोविड-19 महामारी के दौरान कम टैक्स दरों और व्यापक राहत के बावजूद अधिक

ब्लैक पेपर

"जीएसटी एक उपभोग कर है. गरीब अपनी आय का अधिकतर खर्च कर देता है जबकि अमीर अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा बचाता है. फलस्वरूप जीएसटी ने गरीबों को चोट पहुंचाई, अन्य अप्रत्यक्ष करों की तरह."

3% शीर्ष 10 फीसद आबादी की हिस्सेदारी 2021-22 में जीएसटी कलेक्शन में

भ्रष्टाचार

व्हाइट पेपर

"यूपीए सरकार के एक दशक के शासन (या उसकी गैरमौजूदगी) में नीतिगत गड़बड़ियां और गैर पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक संसाधनों (कोयला और दूरसंचार स्पेक्ट्रम) की नीलामी जैसे घोटाले हुए. पूर्व प्रभावी टैक्सेशन और गलत लोगों को सब्सिडी दी गई और पक्षपात करते हुए बैंकों ने अंधाधुंध उधारी दी."

ब्लैक पेपर

"प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में जी20 के सामने आर्थिक अपराधियों के लिए अनुकूल क्षेत्रों को खत्म करने और भ्रष्टाचारियों और उनकी करतूतों को छिपाने वाली अत्यधिक बैंकिंग गोपनीयता को दूर करने के लिए प्रयास करने का वादा किया था. इसके बजाए उन्होंने जांच एजेंसियों को निष्प्रभावी बना दिया और अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में अपने दोस्तों को आगे बढ़ने में मदद की."

नोटबंदी और काला धन

व्हाइट पेपर

"हम काला धन बाहर निकालने के उपायों पर लगातार काम कर रहे हैं और इसे हतोत्साहित कर रहे हैं." (हालांकि नोटबंदी का कोई जिक्र नहीं है)

ब्लैक पेपर

"काला धन बरकरार है, और इसका कोई सबूत नहीं है कि नोटबंदी का इस पर कोई असर हुआ है. देश भी कैशलेस नहीं बन सका है."

चलन में मौजूद मुद्रा (लाख करोड़ रु.)

2016 2023

मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात

व्हाइट पेपर

"हमारी सरकार ने यूपीए सरकार से विरासत में मिली विदेशी अर्थव्यवस्था पर निर्भरता को कम करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं. मैन्युफैक्चरिंग और विदेश व्यापार दोनों ही क्षेत्र में व्यापक उपाय किए गए हैं."

माल निर्यात में वृद्धि (कैलेंडर वर्ष 2014-2022)

भारतीय	41%
वैश्विक	31%

ब्लैक पेपर

"सरकार के पीआर दावों के विपरीत जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 2014 से ही गिर रहा है और 2022 में यह अब तक के निचले स्तर 13 फीसद पर चला गया. रोजगार में इसका हिस्सा 2011-12 में 12.6 फीसद था जो 2021-22 में घटकर 11.6 फीसद रह गया."

320% माल निर्यात में वृद्धि (कैलेंडर वर्ष 2004-2014)

कृषि

व्हाइट पेपर

"यूपीए की कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना से किसानों को कर्ज के प्रवाह में बाधा आई. इसके विपरीत हमारी किसान सम्मान निधि ने किसानों को अपने ऋण चुकाने में सक्षम बनाया. कल्याण योजनाएं सक्षम, कारगर और सशक्त बना रही हैं."

ब्लैक पेपर

"मोदी सरकार ने किसान खुदकुशी के निहित कारणों जैसे कर्ज का बोझ, फसलों के नष्ट हो जाने से निबटने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए हैं... 2024 के बजट में पीएम किसान सम्मान निधि के लिए आवंटन गिरकर 60,000 करोड़ रुपए रह गया जो 2021-22 में 66,825 करोड़ (वास्तविक खर्च) रुपए था."

सामाजिक क्षेत्र

व्हाइट पेपर

"नीति योजना और क्रियान्वयन खराब होने से यूपीए शासन के दौरान सामाजिक क्षेत्र की कई योजनाओं के लिए बड़ी मात्रा में धनराशि खर्च ही नहीं हुई, जिससे ये योजनाएं बेअसर रहीं. कल्याण के जरिए सशक्त बनाना हमारी सरकार का उद्देश्य है."

आवंटित बजट जिसे खर्च नहीं किया गया* ('000 करोड़ रु.)

2004-2014	94
2014-2024	37

*प्रमुख सामाजिक और ग्रामीण क्षेत्र के मंत्रालयों में

ब्लैक पेपर

"बढ़ती लागत के इस दौर में आमदनी गिरने से भूख में ज्यादा इजाफा हुआ है. वैश्विक भूख सूचकांक में 125 देश में भारत की स्थिति 2023 में 111 पर थी. मोदी सरकार के कार्यकाल में महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों का दमन हुआ है."

नोटः सभी चार्ट और आंकड़े दोनों पेपरों में दिए गए डेटा के आधार पर

एएनआइ

पूर्व नौसैनिकों की रिहाई

भारत ने कैसे हासिल की कूटनीतिक कामयाबी

प्रदीप आर. सागर

यह एक ऐसी घर वापसी है जिसका भारत महीनों से इंतजार कर रहा था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने रविवार 11 फरवरी को एक बड़ी कूटनीतिक सफलता हासिल की जब अगस्त 2022 से दोहा में कैद सभी आठ पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारियों को रिहा कर दिया गया. इसके साथ ही उनकी सुरक्षा को लेकर कायम अनिश्चितता खत्म हो गई. कथित तौर पर जासूसी के आरोप में गिरफ्तारी की तरह ही उनकी रिहाई को भी आखिरी क्षणों तक गोपनीय रखा गया. कतर के अधिकारियों ने रविवार तड़के इन सभी आठ लोगों से अपना बैग पैक करने को कहा. पहले, उन्हें भारतीय दूतावास ले जाया गया, और वहां से हवाईअड्डे पहुंचाया गया. फिर उनमें से सात स्पेशल फ्लाइट से सोमवार रात में करीब दो बजे दिल्ली पहुंचे. पूरे घटनाक्रम में उनके परिजनों को भी उनकी घर वापसी की कोई जानकारी नहीं थी. बीते साल दिसंबर में मौत की सजा माफ होने के बाद भी इनमें से कुछ लोगों ने खुली हवा में सांस लेने की उम्मीद छोड़ दी थी. (आठवें पूर्व नौसेना अधिकारी अभी दोहा में हैं और कथित तौर पर औपचारिकताएं पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं.)

मोदी इस मामले को कितनी अहमियत दे रहे थे, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि विदेश मंत्रालय ने संयुक्त अरब अमीरात की दो दिवसीय निर्धारित यात्रा के बाद 14 फरवरी को दोहा जाने के उनके कार्यक्रम की घोषणा अंतिम क्षणों में की. 2014 में पीएम बनने के बाद से मोदी की यह दूसरी कतर यात्रा है. साउथ ब्लॉक के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि कतर से बातचीत कभी आसान नहीं रही, जो अपनी 'मनमानी' और 'गोपनीय' कार्यशैली के लिए जाना जाता है. वैसे, 2021 में एक नेपाली प्रवासी की फांसी को छोड़ दें तो पिछले दो दशकों में इस खाड़ी देश में किसी अन्य को मौत की सजा नहीं दी गई. सूत्रों के मुताबिक, भारतीयों पर इज्राएल के लिए जासूसी करने जैसा गंभीर आरोप था, इसलिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा सकती थी.

वतन वापसी
कतर की ओर से रिहा किए गए आठ में से छह पूर्व नौसैनिक

यही वजह है कि नई दिल्ली ने बहुआयामी रणनीति अपनाई. विदेश मंत्री एस. जयशंकर की अगुआई में खुले तौर पर जारी कूटनीतिक प्रयासों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल के नेतृत्व में पर्दे के पीछे की कवायद भी चलती रही. इस सब पर मोदी ने 'व्यक्तिगत स्तर पर' नजर रखी. माना जा रहा है कि कतर के साथ-साथ संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और कुवैत जैसे पश्चिम एशिया के अन्य प्रमुख खिलाड़ियों के साथ संबंध बढ़ाने के लिए भारत की ओर से किए गए अहम निवेश ने भी इस मामले में अनुकूल नतीजे पाने में बड़ी भूमिका निभाई. पूर्व नौसैनिकों की रिहाई से ठीक हफ्ते भर पहले भारत के पेट्रोनेट एलएनजी और कतर के बीच 78 अरब डॉलर (6.48 लाख करोड़ रुपए) के दीर्घकालिक सौदे को भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है, जिसके तहत कतर से तरलीकृत प्राकृतिक गैस के आयात को 2048 तक यानी अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है. (यह खाड़ी देश भारत की ऊर्जा सुरक्षा में प्रमुख योगदानकर्ता है, और भारत में लगभग आधा एलएनजी यहीं से आयात होती है.)

नई दिल्ली ने बहुआयामी रणनीति अपनाई, जिसमें पीएम की ''व्यक्तिगत निगरानी'' में पर्दे के पीछे के प्रयासों के साथ-साथ प्रत्यक्ष कूटनीति को भी अंजाम दिया गया

भारत के राजनयिक प्रयासों में राजदूत

बढ़ती दोस्ती दिसंबर 2023 में सीओपी28 के दौरान कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

सूत्रों का दावा है कि आखिरकार सफलता तब मिली जब मोदी ने 1 दिसंबर को दुबई में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी सीओपी28 के दौरान कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात की. इसके ठीक दो दिन बाद विपुल को पहली बार आठ पूर्व नौसैनिकों से मिलने के लिए काउंसलर एक्सेस मिली. 28 दिसंबर को कतर की अदालत ने इन भारतीयों की मौत की सजा रद्द कर दी और उन्हें तीन से लेकर 25 साल तक, अलग-अलग अवधि की जेल की सजा सुनाई. अदालत ने सभी आठ लोगों को इस सजा के खिलाफ अपील के लिए 60 दिन का समय भी दिया.

विपुल ने भी बेहद अहम भूमिका निभाई, जिन्हें जून 2023 में दोहा में नियुक्त किया गया था. भारतीय विदेश सेवा के अनुभवी अधिकारी ने पहले से ही मामले पर बारीक निगाह बना रखी थी और नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के खाड़ी प्रभाग में संयुक्त सचिव के तौर पर पूर्व नौसैनिकों के परिवारों से नियमित संपर्क में थे. वे पूर्व में दुबई स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास में तैनात रहे हैं, जिससे इस क्षेत्र के मामलों में उन्हें खास महारत हासिल है.

भारत के प्रयासों को बीते साल 26 अक्तूबर को गहरा झटका लगा, जब इन आठ भारतीयों—कैप्टन नवतेज गिल और सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, अमित नागपाल, एस.के. गुप्ता, बी.के. वर्मा, सुगुनाकर पकाला और नाविक रागेश को कतर की कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस ने मौत की सजा सुनाई. वह भी तब जब डोभाल कतरी अधिकारियों को यह समझाने को दोहा की कई बार यात्रा कर चुके थे कि ये लोग बेगुनाह हैं.

टीम मोदी

- **विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने राजनयिक प्रयासों की अगुआई की और राजदूत विपुल दोहा में अहम भूमिका अदा कर रहे थे**
- **एनएसए अजीत डोभाल ने पर्दे के पीछे बातचीत को अंजाम दिया और कई बार दोहा की यात्रा की**
- **अहम मोड़ तब आया जब दिसंबर में दुबई में पीएम नरेंद्र मोदी कतर के अमीर से मिले**
- **पश्चिमी एशिया के नेताओं के साथ मोदी के अच्छे रिश्ते और उस क्षेत्र में भारत की ओर से किए गए अहम निवेश ने भी अनुकूल नतीजे पाने में बड़ी भूमिका निभाई**

भारतीय रक्षा अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर *इंडिया टुडे* से कहा, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनने से पूर्व इन सभी आठ नौसैनिकों का रिकॉर्ड 'बेदाग' रहा है. कमांडर तिवारी को तो 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया था जो प्रवासी भारतीयों को मिलने वाला सर्वोच्च सम्मान है. रक्षा सूत्र पूरे प्रकरण के पीछे कॉर्पोरेट प्रतिद्वंद्विता को संभावित कारण बताते हैं. ये आठों 2014 में स्थापित रक्षा सेवा कंपनी दहरा ग्लोबल के लिए काम करते थे, जो कतर के अमीर के नौसेना बलों को प्रशिक्षित करती थी. सूत्रों की मानें तो कंपनी की तेज वृद्धि से ईर्ष्या का नतीजा था कि प्रतिद्वंद्वी कंपनियां इसकी साख बिगाड़ने में लग गईं. गिरफ्तारी के तुरंत बाद कंपनी ने दोहा में अपना कामकाज बंद कर दिया. कंपनी के मालिक खमीस अल-अजमी सेवानिवृत्त रॉयल ओमान वायु सेना अधिकारी और कतरी नागरिक थे, जिन्हें नवंबर 2022 में जमानत पर रिहा किया गया.

दिल्ली हवाईअड्डे पर पहुंचकर मीडिया से बातचीत में एक पूर्व नौसेना अधिकारी ने अपनी सुरक्षित वापसी का श्रेय मोदी को दिया. उन्होंने कहा, ''मैं प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि यह मुमकिन नहीं होता अगर उन्होंने हमारी रिहाई के लिए हस्तक्षेप नहीं किया होता...'' यह घटनाक्रम कतर के साथ भारत के रिश्तों के एक नए आयाम पर पहुंचने का प्रतीक भी है, जहां करीब 8,00,000 भारतीय प्रवासी बसे हुए हैं. मोदी का आभार जताना इस रिश्ते को और प्रगाढ़ ही करेगा. ■

मिलिंद शेल्टे

^
नया दल मुंबई में 13 फरवरी को उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस और पार्टी के राज्य प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले की मौजूदगी में भाजपा में शामिल होते चव्हाण

महाराष्ट्र/कांग्रेस

चव्हाण पर भी चढ़ा भगवा रंग

अनिलेश एस. महाजन

इस चुनावी मौसम में गठबंधन टूट रहे हैं और राजनेता भी पार्टी लाइन से इतर जा रहे हैं. महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण कांग्रेस छोड़ने वाले नवीनतम शख्स हैं. वे कई अन्य पूर्व मुख्यमंत्रियों की कतार में शामिल हो गए हैं जिन्होंने बीते दशक में इस बहुत पुरानी पार्टी को छोड़ दिया और

पाला बदलने वाले | बीते दशक में पार्टी छोड़ने वाले कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री

जम्मू और कश्मीर

गुलाम नबी आजाद

कांग्रेस के बादः अपनी खुद की पार्टी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी बनाई

क्यों छोड़ाः राहुल गांधी के नेतृत्व कौशल पर सवाल खड़ा किया और पार्टी की अंदरूनी संस्थानों के 'खत्म' होने पर सवाल उठाया

पंजाब

कैप्टन अमरिंदर सिंह

कांग्रेस के बादः पंजाब लोक कांग्रेस गठित की जो विधानसभा चुनाव में बुरी तरह नाकाम रही. पार्टी का भाजपा में विलय किया. अब वे भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल हैं. उनकी बेटी जय इंदर कौर भाजपा की राज्य महिला विंग की प्रमुख हैं

क्यों छोड़ाः सीएम पद से रुखाई से हटाए जाने की वजह से नाराज थे. इसके लिए राहुल और प्रियंका गांधी को जिम्मेदार बताया

उत्तराखंड

विजय बहुगुणा

कांग्रेस के बादः भाजपा में शामिल. अब उनके बेटे साकेत बहुगुणा उत्तराखंड भाजपा सरकार में मंत्री हैं

क्यों छोड़ाः अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी हरीश रावत को राज्य का सीएम बनाए जाने की वजह से नाराज थे

महाराष्ट्र

नारायण राणे

कांग्रेस के बादः भाजपा में शामिल, अब केंद्रीय मंत्री

क्यों छोड़ाः शिवसेना की ओर से महाराष्ट्र में सीएम थे, लेकिन बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए और फिर 2019 में भाजपा में आ गए

अशोक चव्हाण

कांग्रेस के बादः कांग्रेस छोड़ने के एक दिन बाद ही भाजपा में शामिल

क्यों छोड़ाः स्थानीय नेतृत्व से नाराज थे और आरोप लगाया कि केंद्रीय नेतृत्व चीजों को संभालने में नाकाम रहा

गोवा

दिगंबर कामत

कांग्रेस के बादः भाजपा में शामिल

क्यों छोड़ाः पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर गोवा के मामलों को दरकिनार करने का आरोप लगाया

प्रतापसिंह राणे

कांग्रेस के बादः छह बार सीएम रहे प्रतापसिंह ने राजनीति से संन्यास ले लिया है. बेटे विश्वजीत राणे प्रमोद सावंत की अगुआई वाली भाजपा सरकार में मंत्री हैं. बहू देविया राणे भाजपा विधायक हैं

क्यों छोड़ाः बेटे की ओर से कांग्रेस छोड़ने का दबाव था

लुइजिन्हो फलेरो

कांग्रेस के बादः टीएमसी में शामिल हुए. बाद में उनके राज्यसभा सदस्य बने

क्यों छोड़ाः पार्टी की स्थानीय इकाई को ''कांग्रेस के मूल्यों का क्रूर मजाक'' बताया

कर्नाटक

एस.एम. कृष्णा

कांग्रेस के बादः भाजपा में शामिल और बाद में सार्वजनिक जीवन से दूर हो गए

क्यों छोड़ाः राहुल के काम करने के तरीके की आलोचना की

आंध्र प्रदेश

किरण कुमार रेड्डी

कांग्रेस के बादः भाजपा में शामिल. अब इसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का हिस्सा हैं

क्यों छोड़ाः कांग्रेस नेतृत्व पर राज्य के नेताओं को दरकिनार करने का आरोप लगाया

अरुणाचल प्रदेश

प्रेमा खांडू

कांग्रेस के बादः 2016 में 43 विधायकों के साथ पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल में शामिल; बाद में भाजपा में चले गए

क्यों छोड़ाः भाजपा के 'विकास एजेंडा' का हिस्सा होना चाहते थे
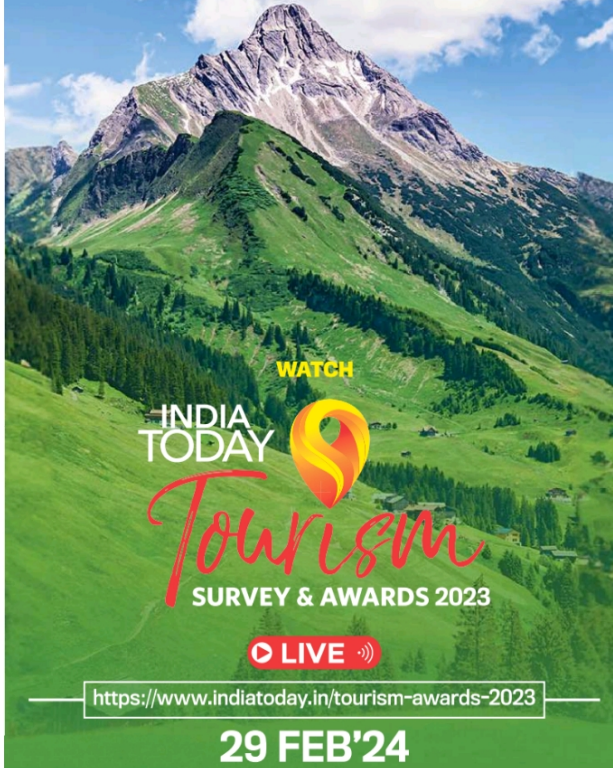
उनमें से कई भगवा खेमे में चले गए.

चव्हाण ने 12 फरवरी को कांग्रेस के सभी पदों और भोकर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया. एक दिन बाद ये 65 वर्षीय मराठा नेता भाजपा में शामिल हो गए, जिससे अटकलें शुरू हो गईं कि उन्हें राज्यसभा के लिए नोमिनेट किया जा सकता है. साल 2019 में चव्हाण अपने गढ़ नांदेड़ लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के प्रतापराव चिखलीकर पाटील से हार गए थे, जो खुद सियासी दलबदल के प्रतीक रहे हैं.

दो बार मुख्यमंत्री और गांधी परिवार के वफादार रहे शंकरराव चव्हाण के वारिस तथा खुद दो बार मुख्यमंत्री रहे अशोक चव्हाण का जाना कांग्रेस के लिए बड़े नुक्सान के रूप में देखा जा रहा है. वह भी ऐसे वक्त में जब पार्टी राज्य में अस्तित्व की चुनौतियों से जूझ रही है. पिछले एक दशक में भाजपा ने कांग्रेस की प्रमुख शख्सियतों और उनके रिश्तेदारों को अपने पाले में करने की रणनीति अपनाई है. इससे न केवल उसने अपने खेमे को मजबूत किया है बल्कि गांधी परिवार के लिए भी अजीब स्थिति पैदा कर दी है. इसके उदाहरण भरे पड़े हैं: पंजाब में पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के भाजपा में शामिल होने के बाद उनकी बेटी को भी राज्य इकाई में जगह दी गई. वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बेटे सौरभ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे और पुष्कर सिंह धामी सरकार में मंत्री हैं. इसी तरह से गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे अपने बेटे विश्वजीत राणे के कहने पर सेवानिवृत्त हो गए और विश्वजीत भाजपा में शामिल होकर अब प्रमोद सावंत कैबिनेट में मंत्री हैं.

कांग्रेस से अलग होने वाले पूर्व मुख्यमंत्री अक्सर पार्टी छोड़ने की वजह ''सलाहकारों'' से घिरे केंद्रीय नेतृत्व (पढ़ें गांधी परिवार) के साथ अलगाव को बताते हैं. उनके अनुसार, वे ''सलाहकार'' केंद्रीय नेतृत्व तक उन्हें पहुंचने नहीं देते. उन्होंने जमीनी स्तर के नेताओं पर निर्भरता की कमी का भी रोना रोया. पिछले साल अप्रैल में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने अपने संस्मरण *आज़ाद* का लोकार्पण किया था. उस किताब में उनके इस दावे ने लोगों का ध्यान खींचा कि राजनेताओं को ''आज की कांग्रेस में बचे रहने के लिए रीढ़विहीन होना होगा.'' भगवा खेमे के भीतर कई कांग्रेसी पूर्व मुख्यमंत्री खुद को सेवानिवृत्ति की ओर बढ़ता देख रहे हैं. ■

भाजपा

जातियों को जोड़कर जीत की जुगत

हिमांशु शेखर

एएनआइ

सीधी पहुंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में उज्ज्वला योजना की एक लाभार्थी के घर पर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते कुछ महीने से कह रहे हैं कि उनके लिए सिर्फ चार जातियां हैं: युवा, गरीब, महिला और किसान. जब से बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण हुआ है और देश भर में जातिगत जनगणना की बात उठी है, तब से मोदी जात-पांत की पारंपरिक राजनीति करने के लिए विपक्षी दलों पर आक्रामक हैं. लेकिन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की लोकसभा चुनाव की रणनीति में जाति आधारित सोशल इंजीनियरिंग की छाप स्पष्ट तौर पर दिख रही है.

लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने अनुसूचित जाति-जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की अलग-अलग जातियों को रिझाने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाने की योजना बनाई है. उसे लगता है कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से वह इन जातियों को अपने साथ जोड़ने में कामयाब होगी और इसका सीधा असर लोकसभा चुनावों में उसकी सीटों पर पड़ेगा.

अनुसूचित जाति के मतदाताओं में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए भाजपा आने वाले दिनों में कई राज्यों में बौद्ध सम्मेलन करने की योजना बना रही है. उत्तर प्रदेश के अलावा पार्टी इन सम्मेलनों का आयोजन पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक और तेलंगाना में करने की योजना तैयार कर रही है. छत्तीसगढ़ को छोड़कर बाकी राज्यों में दलितों की आबादी 15 प्रतिशत या इससे ज्यादा है. इस तरह के सम्मेलन 2017 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चर्चा में आए थे. तब भाजपा ने अखिल भारतीय भिक्खु महासंघ की मदद से उन क्षेत्रों में कई बौद्ध सम्मेलन किए थे, जहां दलित मतदाताओं की संख्या अच्छी-खासी थी. महासंघ ने 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले एक धम्म चक्र यात्रा निकाली थी, जिसे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने हरी झंडी दिखाई थी.

इन कार्यक्रमों को योजनाबद्ध करने में जुटे भाजपा के एक राष्ट्रीय पदाधिकारी बताते हैं, ''अब तक पार्टी अनौपचारिक तौर पर 400 लोकसभा सीटें जीतने की बात कर रही थी. लेकिन अब प्रधानमंत्री ने औपचारिक तौर पर संसद में 370 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य भाजपा के लिए तय कर दिया है. ऐसे में हमें देश के हर क्षेत्र में सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ने के अपने प्रयासों में और तेजी लानी होगी. हमारी कोशिश सिर्फ दलित समाज के लिए ही नहीं बल्कि आदिवासी समाज और अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ अति पिछड़ा वर्ग को भी अपने साथ जोड़ने की है. इसके लिए स्वाभाविक ही है कि पार्टी कई कार्यक्रमों का आयोजन करे.''

अनुसूचित जाति में भी उन जातियों पर भाजपा अधिक जोर देने की रणनीति बना रही हैं, जो अधिक पिछड़ी हैं. उदाहरण के तौर पर तेलंगाना के माडिगा और पंजाब-हरियाणा के वाल्मीकि समाज के लोग. तेलंगाना में अनुसूचित जाति के लोग की आबादी करीब 15 फीसद है, जिनमें आधी संख्या अकेले माडिगा की है. लेकिन इस जाति के लोगों का कहना है कि उन्हें अनुसूचित जाति के लिए दिए जा रहे आरक्षण और अन्य सुविधाओं का उचित लाभ नहीं मिल रहा. तेलंगाना में विधानसभा चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अनुसूचित जाति के उपवर्गीकरण का वादा किया था. भले ही वहां भाजपा जीत नहीं पाई लेकिन विधानसभा में पार्टी को 14 फीसद वोट मिले. इससे पार्टी को लग रहा है कि लोकसभा चुनावों में उसका वोट प्रतिशत और बढ़ सकता है.

इसी वजह से मोदी सरकार ने इस साल जनवरी में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के नेतृत्व में भारत सरकार के सचिवों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया. कैबिनेट सचिव के अलावा इसमें गृह मंत्रालय, विधि मंत्रालय, सामाजिक न्याय व आधिकारिता मंत्रालय, जनजातिय कार्य मंत्रालय और कार्मिक मंत्रालय के सचिव भी शामिल हैं. इस समिति को 1,200 से अधिक अनुसूचित जातियों की सूची में पीछे रह गई जातियों की स्थिति का अध्ययन करने का काम सौंपा गया है. समिति की रिपोर्ट के आधार पर कुछ

अनुसूचित जातियों को 'कोटा विदिन कोटा' यानी आरक्षण के दायरे के अंदर अलग से आरक्षण देने पर भी विचार किया जा सकता है. हालांकि, इसकी उम्मीद कम ही लग रही है कि यह समिति लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले अपनी रिपोर्ट देगी लेकिन भाजपा इस समिति के गठन का प्रचार-प्रसार करते हुए अनुसूचित जातियों के अंदर की पिछड़ी जातियों को अपने पाले में लाने की योजना बना रही है.

विपक्ष की तरफ से जाति जनगणना की मांग का बचाव करने के लिए भाजपा की तरफ से इस समिति के गठन को इस्तेमाल करने की योजना है. हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फिर से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के पाले में आ जाने से विपक्ष की ओर से जातिगत जनगणना की मांग धीमी पड़ी है. नीतीश कुमार के पाला बदलने से न सिर्फ बिहार में कोइरी-कुर्मी समाज की सोशल इंजीनियरिंग को भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए साध पाएगा बल्कि उत्तर प्रदेश में भी कुर्मी समाज के प्रभाव वाली सीटों पर भाजपा को फायदा मिल सकता है.

बिहार के मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर को हाल में भारत रत्न देने की घोषणा को भी भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग से जोड़कर देखा गया. अति पिछड़ा वर्ग को बिहार में अलग से आरक्षण देने वाले कर्पूरी ठाकुर को पूरे राजनैतिक जीवन को पिछड़ों के लिए काम करने से जोड़कर देखा जाता है. अब उन्हें भारत रत्न देकर भाजपा ने पिछड़ी जातियों के बीच अपनी पैठ और मजबूत बनाना चाहती है.

इसी तरह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर मोदी सरकार ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों के बीच अपना आधार बढ़ाया है. इसका फौरी नतीजा राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन के रूप में सामने आया. (इसी अंक में देखें: कमल को कितना सींच पाएगा हैंडपंप)

संसद के बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से चार जातियों—युवा, महिला, गरीब और किसान की बात दोहराई लेकिन साथ ही उन्होंने पिछले दस साल में दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए किए गए कार्यों को भी गिनाया. साथ ही उन्होंने खुद को एक बार फिर से ओबीसी बताया.

भाजपा ने वैसी पिछड़ी जातियों को भी इस लोकसभा चुनाव में लक्षित करने की योजना बनाई है जिनकी संख्या प्रतिशत में कम है लेकिन जो किसी गैर भाजपा के प्रतिबद्ध वोट बैंक के तौर पर नहीं जानी जातीं. इन जातियों को ध्यान में रखकर ही मोदी सरकार ने 17 सितंबर, 2023 को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की थी. इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त, 2023 को लाल किले की प्राचीर से की थी. इस योजना के तहत पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों समेत छोटा-मोटा तकनीकी काम करने वालों को ब्याज मुक्त कर्ज देने से लेकर उनके कौशल विकास में मदद करते हुए अन्य कई सहायता देने का प्रावधान है. इसके राजनैतिक लाभ को लेकर भाजपा इसलिए उत्साहित है कि विश्वकर्मा योजना को शुरू हुए चार महीने से थोड़ा ही अधिक वक्त हुआ है लेकिन इसका लाभ लेने के लिए अब तक 97 लाख से अधिक आवेदन आ चुके हैं.

विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों में बड़ी संख्या उन पिछड़ी जातियों के लोगों की है जो किसी पार्टी के पारंपरिक वोट बैंक नहीं हैं. इनमें बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार, नाई, मोची और मल्लाह के अलावा और भी कई ऐसी जातियां हैं जिनकी पहचान किसी न किसी काम से है. उदाहरण के लिए, गुजरात के जामनगर के आसपास राजमिस्त्री का काम करने वाली एक जाति है कड़िया. इसी तरह से अलग-अलग कामों से जुड़ी कुछ जातियां अलग-अलग राज्यों में है. विश्वकर्मा योजना के जरिए भाजपा इन जातियों को अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रही है. आने वाले दिनों में भाजपा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों के कई सम्मेलन अलग-अलग राज्यों में आयोजित करने वाली है. इनके जरिए पार्टी अति पिछड़ी जातियों के बीच पैठ बनाने की कोशिश करेगी.

लोकसभा चुनाव के साल में भाजपा एक तरफ जहां अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग में भी अति पिछड़ा जातियों को लक्षित कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ ओबीसी की प्रभावी जातियों को भी अपनी सोशल इंजीनियरिंग में पीछे छोड़ने का जोखिम उठाने को तैयार नहीं है. इसमें हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट और महाराष्ट्र में मराठा समाज के लोग शामिल हैं. मराठा आरक्षण की मांग पर जिस तरह से महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने काम किया और इस मांग को स्वीकार करने पर सहमति दी, उसे भाजपा के दबाव से जोड़कर देखा जा रहा है.

प्रभावी जातियों को भाजपा के साथ जोड़ने की रणनीति पर पार्टी के एक पदाधिकारी कहते हैं, "हम जाट और मराठा के लोगों के बीच कई कायक्रम करने वाले हैं. जाट और मराठा समाज में कई ऐसे लोग हैं जो किसी पार्टी की राजनीति में सक्रिय नहीं हैं लेकिन समाज में उनका प्रभाव है. इनमें से कई लोग सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं. संभव है कि ये कार्यक्रम भाजपा के बैनर तले न हों लेकिन हमारी कोशिश है कि इन मंचों से वही बात की जाए जो हम चाहते हैं."

यानी भाजपा ने सभी जातियों को जोड़कर जीत की जुगत लगा रखी है.■

सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला

- अनुसूचित जाति के मतदाताओं में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए भाजपा आने वाले दिनों में कई राज्यों में बौद्ध सम्मेलन करने की योजना बना रही है
- भाजपा ने उन राज्यों पर अधिक जोर देने की योजना बनाई है जहां कम से कम 15 फीसद दलित आबादी हो
- अनुसूचित जातियों में अपेक्षाकृत अधिक पिछड़ी जातियों को साथ जोड़ने के लिए पार्टी उपवर्गीकरण का मुद्दा उठाएगी. उपवर्गीकरण जैसी मांगों पर कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में बनी है एक उच्च स्तरीय समिति
- अधिकांश राज्यों में विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद के कार्यक्रम आयोजित करके अति पिछड़ी जातियों के साथ लाने की बनी रणनीति
- पिछड़ी जातियों के साथ-साथ जाट और मराठा जैसी प्रभावी वर्गों के लिए भी रणनीति तैयार

प्रधानमंत्री युवा, महिला, गरीब और किसान को चार जातियां बताते हैं, लेकिन खुद को ओबीसी बताने से नहीं चूकते

छत्तीसगढ़

युवा वित्त मंत्री का पहला बजट, कितना नया?

देवेश तिवारी

छत्तीसगढ़ की छठवीं विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने चौथी बार सरकार बनाई है. इस नई सरकार में कई परंपराएं टूटीं और इनमें जो सबसे खास रही, वह वित्त मंत्रालय से जुड़ी है. आमतौर पर वित्त विभाग मुख्यमंत्री अपने पास रखते आए हैं. लेकिन इस बार पूर्व आइएएस अफसर और युवा विधायक ओ.पी. चौधरी को वित्त विभाग देकर भाजपा ने नई परंपरा स्थापित की. पहली बार विधायक बने चौधरी अभी महज 42 साल के ही हैं. इस लिहाज से उनके पास काफी बड़ी जिम्मेदारी है. यह भी वजह है कि उनके पहले बजट पर तमाम लोगों की नजर थी.

छत्तीसगढ़ में 9 फरवरी को जब उन्होंने बजट पेश किया तो साफ हो गया कि सरकार और वित्त मंत्री खुद लोकसभा चुनाव के इस साल में एक नया विजन पेश करना चाहते हैं. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए विष्णुदेव साय सरकार की तरफ से करीब एक लाख 47 हजार 500 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है. यह भूपेश बघेल की अगुआई वाली पिछली सरकार के बजट से 22 फीसद ज्यादा है. वित्त मंत्री चौधरी कहते हैं, ''यह छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने का बजट है. यह बजट 'ज्ञान' (जीवाइएएन) यानी गरीब, युवा, अन्नदाता (किसान) और नारी पर फोकस्ड है.'' चौधरी इस बजट को 2047 का 'विजन डॉक्यूमेंट' बताते हुए कहते हैं कि सरकार ने 5 साल में राज्य की जीडीपी को 5 लाख करोड़ रुपए से 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने यानी दोगुना करने का लक्ष्य रखा है.

छत्तीसगढ़ में साय सरकार की सबसे बड़ी चुनौती उन वादों को लोकसभा चुनाव से पहले पूरा करने की है जो भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान किए थे. सत्तारूढ़ पार्टी ने विधानसभा चुनाव के अपने घोषणा पत्र को 'मोदी की गारंटी' बताकर पेश किया था.

इस बार गरीबों की आवास योजना के लिए अनुपूरक के अलावा नए बजट को जोड़कर कुल 8,369 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा, विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर रही 'महतारी वंदन योजना' को शुरू करने की घोषणा की गई. योजना के मुताबिक, छत्तीसगढ़ सरकार 1 मार्च से राज्य की 21 साल से अधिक उम्र की विवाहित, विधवा या तलाकशुदा महिलाओं को एक हजार रुपए प्रति माह देने जा रही है.

केंद्र सरकार की योजनाओं में राज्यांशों की घोषणा के अलावा बजट की एक और खास बात यह रही कि इसमें 'स्टेट कैपिटल रीजन' का विजन पेश किया गया. इसके तहत भिलाई, दुर्ग और रायपुर को मिलाकर राजधानी क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा. फिलहाल इसके लिए बजट में पांच करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. अयोध्या में स्थापित रामलला के दर्शन के लिए राज्य सरकार ने एक नई योजना बनाई है और इसके लिए 35 करोड़ रुपए का प्रावधान है.

छत्तीसगढ़ की 90 फीसद आबादी खेती-बाड़ी पर निर्भर है. यही वजह है कि यहां की सियासत खेती के इर्दगिर्द घूमती है. तीन माह पहले राज्य से विदा हुई सरकार ने किसानों से 2,500 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीद का वादा किया था जो किसानों को लुभाने की बड़ी कोशिश थी. लेकिन भाजपा ने 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ 3,100 रुपए में खरीदने की घोषणा करके कांग्रेस की कोशिश को बेअसर कर दिया था. नई सरकार को यह वादा भी पूरा करना है. शायद यही वजह है कि कृषि बजट में भी 33 फीसद की अच्छी-खासी बढ़ोतरी की गई है. साथ ही बजट में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और खरीद मूल्य के अंतर की राशि और भूमिहीन मजदूरों को राशि देने के लिए प्रावधान रखे गए हैं.

छत्तीसगढ़ में पहली बार विधायक बने ओ.पी. चौधरी के सामने अपने पहले बजट में चुनाव में किए गए वादों को पूरा करने की चुनौती थी

युवा वर्ग को साधने के लिए बजट में नया रायपुर को आइटी हब के रूप में विकसित करने का विजन रखा गया है. इसके अलावा राज्य में 22 नई लाइब्रेरियां बनाई जा रही हैं, जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र 24 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं.

दरअसल राज्य में सरकारी भर्तियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सरकार बड़े मौके देने जा रही है. भाजपा ने चुनाव से पहले दो साल के भीतर एक लाख सरकारी नौकरियों पर भर्ती करने का वादा किया है. जाहिर है कि लोकसभा चुनाव से पहले उसे इस मोर्चे पर भी कुछ करके दिखाना होगा. इसे देखते हुए बजट सत्र के दौरान शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने जानकारी दी कि 25 हजार सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में विकसित किया जाएगा. इसके अलावा साय सरकार ने 33 हजार पदों पर शिक्षकों की सीधी भर्ती करने का निर्णय लिया है. इसमें व्याख्याता के 2,524 पद, शिक्षक के 8,194

उम्मीदों का पिटारा!
छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय के साथ वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी बजट पेश करने जाते हुए

और सहायक शिक्षकों के 22,341 पद शामिल हैं. वहीं, राज्य के पुलिस बल में 1,089 पदों की बढ़ोतरी की जाएगी.

राज्य के इस महत्वाकांक्षी बजट को कांग्रेस ने 'ख्याली पुलाव' बताया है. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि साय सरकार ने बजट का आकार बढ़ा लिया और वह राजस्व बढ़ने की बात कर रही है लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं हो पाएगा. इसके अलावा 'मोदी की गारंटी' पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर उन्होंने लिखा, ''चुनाव में गारंटी देकर गए मोदी जी. अब मोदी जी की गारंटी का बोझ इतना है कि छत्तीसगढ़ जैसा छोटा राज्य सह नहीं पा रहा. बजट के प्रावधान गवाही दे रहे हैं कि मोदी की गारंटी बीजेपी सरकार को भारी पड़ रही है.'' ■

पर्यावरण की रक्षक

आज पर्यावरण को बचाना एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को स्वीकार किया है कक्षा दस की छात्रा आरना वधावन ने. 8,000 से अधिक पेड़ लगाने का श्रेय पाने वाली आरना ने अपनी दूरदर्शी परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए युवा पर्यावरण क्लब की स्थापना की. कोविड-19 महामारी में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों ने उन्हे कुछ करनेपर मजबूर कर दिया और उन्होने वृक्षों का महत्त्व समझा और कम उम्र में ही पर्यावरण संरक्षण की मुहीम पर निकल पढ़ी. अपने आँगन में एक पौधा लगाने के एक साधारण कार्य से जो शुरुआत हुई, वह एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन में बदल गई।

आरना वधावन साकेत के ज्ञान भारती स्कूल में 10वीं कक्षा में हैं पर फिर भी उन्हें आईआईटी दिल्ली में स्नातकोत्तर छात्रों के द्वारा किया जाने वाला कोर्स मानदेय के साथ दिया गया जिसके लिए उन्होंने "सस्टेनेबल हैबिटैट" पर एक प्रोजेक्ट किया और जिसे आईआईटी, दिल्ली में बहुत सराहा गया

आरना ने सीबीएसई और 1एम1बी द्वारा आयोजित फ्यूचर टेक ओलंपियाड में भी पहला स्थान हासिल किया है। आरना पर्यावरण के बारे में जागरूकता फैलाने में भी सदा आगे रहती है।

हाल हे में उन्होने प्रिंसेस दिया कुमार फाउंडेशन के लिए पर्यावरण सरक्षण की आवश्यकता पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जिस के लिए उन्हे काफी प्रशंसा मिली.आरना वधावन सिर्फ एक युवा पर्यावरणविद् नहीं हैं; वह हम सभी के लिए एक प्रेरणा हैं। आरना पर्यावरण जागरण के लिए समय समय पर TEDx इवेंट्स, में हिस्सा लेती है और जोश टॉक्स के माध्यम से अपनी सोच लोगों तक पहुँचाती है. उन्होने WWF इंडिया, TERI और गर्ल अप जैसे संगठनों के साथ सहयोग किया है।जिनीवा की अर्थ प्राइज फाउंडेशन ने आरना को यूथ बोर्ड मेम्बर में शामिल किया.

झारखंड

कारागार से कद ऊंचा?

आनंद दत्त

झारखंड की पहचान अस्थिर सरकारों वाले राज्य के रूप में रही है. यह छवि बीते नौ साल में थोड़ी धुंधली पड़ रही थी, लेकिन वक्त ने फिर करवट ली. अपने कार्यकाल के पांचवें साल में प्रवेश कर चुके हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा. बीती 31 जनवरी की रात उन्हें ईडी ने राजभवन के अंदर गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद जिस भाव-भंगिमा के साथ वे ईडी की गाड़ी में फ्रंट सीट पर बैठे और समर्थकों, मीडियाकर्मियों को थम्स अप किया, उससे उन्होंने मजबूत सियासी संदेश देने की कोशिश की. थोड़ी देर बाद थोड़े मायूस, थोड़े मजबूत चेहरे के साथ उनकी पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन भी उनसे मिलने गईं.

ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह दृश्य झारखंड सहित देशभर की आदिवासी राजनीति और आदिवासियों पर अपना प्रभाव छोड़ने जा रहा है? क्या इस गिरफ्तारी ने सोरेन का सियासी कद ऊंचा कर दिया है? रांची के दीपाटोली कैंट स्थित एक पान वाले मनोज कुमार (बदला हुआ नाम) खुद को कट्टर भाजपा समर्थक बताते हैं लेकिन वे भी कहते हैं, ''भाजपा वाला सब हद कर दिया. इतना नहीं करना चाहिए था. ये गलत हुआ है. आजकल किस पार्टी में भ्रष्ट आदमी नहीं है जी?'' झारखंड की राजनीति को पिछले 20 साल से कवर कर रहे पत्रकार सुरेंद्र सोरेन कहते हैं, ''हेमंत सोरेन अब तक बतौर राजनेता शिबू सोरेन के बेटे ही थे. लेकिन गिरफ्तारी ने उन्हें देश के स्तर पर बतौर मजबूत आदिवासी नेता स्थापित कर दिया है. या यूं कह लें कि राजनीति में उनका पुनर्जन्म हुआ है.''

सोरेन की गिरफ्तारी और फिर चार दिन बाद फ्लोर टेस्ट के दौरान दिए उनके भाषण की चर्चा झारखंड के बाहर भी, खासकर आदिवासी क्षेत्रों में खूब हो रही है. छत्तीसगढ़ के आदिवासी नेता अरविंद नेताम कहते हैं, ''एक आदिवासी या हेमंत की छवि को समझने के लिए आपको विधानसभा में दिए भाषण के मात्र दो बिंदुओं को समझना होगा. हेमंत ने कहा कि ''मैं आंसू नहीं बहाऊंगा, वक्त आने पर इनको जवाब दूंगा.'' दूसरा, ''हम जंगल से बाहर आ गए तो इनके कपड़े मैले होने लगे.'' इन दो बातों में देशभर के आदिवासियों के नेचर और मौजूदा दर्द को साफ देखा जा सकता है. ''आदिवासी जो झेलता है, दिलेरी के साथ फेस करता है.'' इस बात की पुष्टि रांची के वरिष्ठ पत्रकार नीरज सिन्हा भी करते हैं. वे कहते हैं कि इस भाषण के बाद सोरेन ने अपना दायरा झारखंड से बाहर भी बढ़ा लिया है. वैसे, लोकसभा चुनाव या उसके बाद इसका कितना असर होगा, यह अभी देखना बाकी है.

भारत आदिवासी पार्टी के कांतिलाल रोत राजस्थान के उभरते आदिवासी नेता हैं. नेताम की बात को आगे बढ़ाते हुए वे कहते हैं, ''हम पूरे देश के आदिवासियों की तरफ से हेमंत सोरेन को धन्यवाद देना चाहते हैं कि एक आदिवासी नेता ने हार नहीं मानी, संघर्ष किया और सरकार को गिरने नहीं दिया.'' उनका कहना है कि आदिवासियों की आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए बहुत समय बाद आदिवासियों के बीच एक बड़ा नेता मिला है. वहीं त्रिपुरा के आदिवासी नेता और टिपरा मोथा प्रमुख प्रद्योत माणिक्य अलग राय रखते हैं. उनका मानना है कि ''हेमंत के पिता शिबू सोरेन रियल ट्राइबल लीडर थे. हेमंत को अगर बड़ा बनना है तो यह अब उन्हें चुनाव में अपने प्रदर्शन से बताना होगा. यह आदिवासी और गैर-आदिवासी के बीच की लड़ाई नहीं है.''

आदिवासी मुद्दों पर बारीक नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर ने हाल में झारखंड के विभिन्न इलाकों का दौरा किया. वे कहते हैं, ''केवल ईडी प्रकरण से हेमंत के कद के ग्राफ को नहीं मापा जाना चाहिए. वे तो सरकार में आते ही इसकी तैयारी में लग गए थे. चाहे वह सरना धर्म कोड पास करने की बात हो, 1932 स्थानीय नीति का मुद्दा हो या फिर भाषा आंदोलन हो. हां, झुकने की बजाए गिरफ्तारी देकर उन्होंने इस ग्राफ को तेजी से ऊंचा कर दिया है.''

इधर, आम आदिवासियों के बीच यह भावना भी प्रबल है कि सोरेन को बाहरी-बिहारी लोगों ने फंसा दिया है. खुद सोरेन भी फ्लोर टेस्ट के दौरान यह कहते सुने गए, ''मैं एक आदिवासी वर्ग से आता हूं. नियम, कायदे-कानून की जानकारी का थोड़ा अभाव रहता है. बौद्धिक क्षमता हमारे विपक्ष के बराबर नहीं है. '' लेकिन गिरफ्तारी से पहले बीते चार साल में अपने विरोधियों को हर कदम पर मात देते आए सोरेन की इस स्वीकारोक्ति को इतनी आसानी से मान लेना चाहिए? वह भी तब, जब अपनी सरकार बचाने के लिए कांग्रेस के तीन विधायकों को गिरफ्तार कराना, विधायकों को रायपुर शिफ्ट करना, सरना धर्म कोड पास कर गेंद केंद्र के पाले में डालना, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी को राजभवन से बाहर निकाल सीएम के क्षेत्राधिकार में ले आना,

48
साल के हैं हेमंत सोरेन

2
मामले हैं ईडी के पास हेमंत से जुड़े, एक में गवाही हो चुकी है

24
लोग ऐसे हैं जिन्हें ईडी ने अब तक राज्य में गिरफ्तार किया है, हालांकि मामले अलग-अलग, लेकिन कहीं न कहीं सरकार से जुड़े हुए हैं

5
लोग इनमें हेमंत के करीबी हैं

44
साल की हो चुकी है इनकी पार्टी जेएमएम

सहानुभूति!
क्या हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद आदिवासियों में उनके प्रति सहानुभूति उपजी है, इसे लेकर बिरादरी में सुगबुगाहट

आनंद दत्त

दिल्ली स्थित आवास पर ईडी के पहुंचने से पहले वहां से निकल जाना, जैसी सियासी चालबाजियां वे लगातार चलते रहे हों.

आरोप-प्रत्यारोप, पूछताछ और गिरफ्तारी की इस कड़ी में सोरेन के अलावा बाकी सभी गैर-आदिवासी हैं. इसमें उनके प्रेस सलाहकार अभिषेक श्रीवास्तव, उनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्र, करीबी दोस्त विनोद सिंह, अमित अग्रवाल, सत्ता के बेहद करीबी पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश जैसे नाम शामिल हैं. सोरेन एक संथाल आदिवासी हैं. ऐसे में सवाल तो बनता है कि उनके सही या गलत काम, जो कि अभी साबित होने हैं, में कोई अन्य आदिवासी व्यक्ति या समुदाय, मसलन, मुंडा जनजाति के लोग क्यों नहीं शामिल हैं?

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी इस मुद्दे पर कहते हैं, ''आदिवासी कभी लूटता नहीं, चोरी नहीं करता है. ऐसे में हेमंत सोरेन का ये पैसों का कारोबार कौन करता? इसलिए उन्होंने अपने आसपास ऐसे लोगों को जगह दी, जो इसमें माहिर हैं. जो पैसे कमा कर भी लाता रहा और उसको इन्वेस्ट भी करता रहा. जहां तक बात हेमंत सोरेन का कद ऊंचा होने की है, तो वह केवल उनके समर्थकों की नजर में है. राज्यभर के आदिवासियों में नहीं. बीते एक हफ्ते में मैंने बड़ी संख्या में आदिवासी लोगों को भाजपा जॉइन कराया है. कुछ जाति-वर्ग के लोग भाजपा के खिलाफ हैं, वे हेमंत के सपोर्ट में हैं, बाकी कोई नहीं.''

ओडिशा के मयूरभंज से दो बार भाजपा के सांसद रह चुके सालखन मुर्मू फिलहाल पार्टी छोड़ आदिवासी सेंगेल अभियान चला रहे हैं. इसके तहत वे धर्म कोड सहित अन्य मुद्दों पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं. वे कहते हैं, ''आदिवासी जनमानस बाइ नेचर करप्शन या गलत काम में कम लिप्त रहता है. लेकिन जो आदिवासी पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, बाकी लोगों की बीमारियों का असर उन पर भी पड़ता है. यहां पर मामला अलग है. सोरेन खानदान के सभी लोग इसमें संलिप्त रहे हैं. उनके इर्द-गिर्द के अधिकतर लोग जेल में हैं. ये कुछ तो इंडिकेशन देता है न.''

सहानुभूति काल कब तक

लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव सिर पर हैं. जब पीएम मोदी राम मंदिर के रथ पर सवार होकर झारखंड के चुनावी दौरों पर पहुंचेंगे और कहेंगे कि हम भ्रष्टाचारियों को छोड़ते नहीं, तब क्या सोरेन के प्रति बनी सहानुभूति बरकरार रह पाएगी? क्या जेएमएम इस ''सहानुभूति काल'' को विधानसभा चुनाव होने तक जनता, खासकर आदिवासी वोटरों के बीच, जो कि कुल 28 रिजर्व सीट पर किसी को बनाने-बिगाड़ने की क्षमता रखते हों, बनाए रख पाएगी? ईडी की जांच में जब खुलासे होंगे, जो सोरेन की प्रतिष्ठा, सियासी फायदे के अनुकूल नहीं होंगे, तब इस सहानुभूति की उम्र क्या तेजी से घट जाएगी? यह बात काबिले-गौर इसलिए भी है कि देश की दूसरी जातियां ऐसे आरोपों के बावजूद अपने नेता के साथ खड़ी रहती हैं. लालू प्रसाद यादव इसकी सबसे मजबूत मिसाल हैं. लेकिन आदिवासी भ्रष्टाचार के आरोप को बर्दाश्त नहीं करते. शायद यही वजह है कि शिबू सोरेन सीएम रहते विधानसभा उप-चुनाव हार गए थे. अपने गढ़ संथाल से लोकसभा के चुनाव हार गए. हालांकि तब के राजनैतिक हालात अलग थे.

माणिक्य फिर कहते हैं, ''अगर पब्लिक यह मानती है कि हेमंत ने उनके लिए काम किया है, तो उन्हें वोट करेगी. चाहे हवा किसी भी ओर हो, अगर पब्लिक नहीं मानेगी तो सत्ता में रहते हुए भी सहानुभूति काम नहीं करेगी.'' वहीं, नेताम कहते हैं, ''जब तक अंतिम फैसला नहीं आ जाता, यह बरकरार रहने वाली है.'' श्याम सुंदर इसमें एक अहम बात जोड़ते हैं, ''संथाल ही नहीं, मुंडा आदिवासी भी मानने लगे हैं कि आदिवासी होने की वजह से उनको टारगेट किया गया है. हेमंत पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, यह बात आदिवासी जानते हैं, पर उलिहातू जो कि बिरसा मुंडा का गांव है, वहां एक आदिवासी ने साफ कहा कि अगर वे भाजपा से हाथ मिला लेंगे तो आरोप खत्म हो जाएंगे.''

लड़ाई परसेप्शन बनाने-बिगाड़ने की है. सोरेन फिलहाल इसमें आगे नजर आ रहे हैं और सहानुभूति अभी उनके साथ है. भाजपा ने वक्त रहते इसे भांपा है. यही वजह है कि विधानसभा में विश्वास मत के दौरान भाजपा या उसके सहयोगी दलों के किसी भी नेता ने सीधे सोरेन को निशाने पर लेने की बजाए कांग्रेस पर निशाना साधा. वे जेएमएम को बार-बार याद दिलाते रहे कि शिबू सोरेन को कांग्रेस ने ही गिरफ्तार करवाया था. क्या इसे यह माना जाए कि हेमंत सोरेन को मिल रही सहानुभूति की लहर में शिबू सोरेन के रास्ते भाजपा घुसने की कोशिश कर रही है?■

आवरण कथा
पाकिस्तान
कांटों भरा

ताज
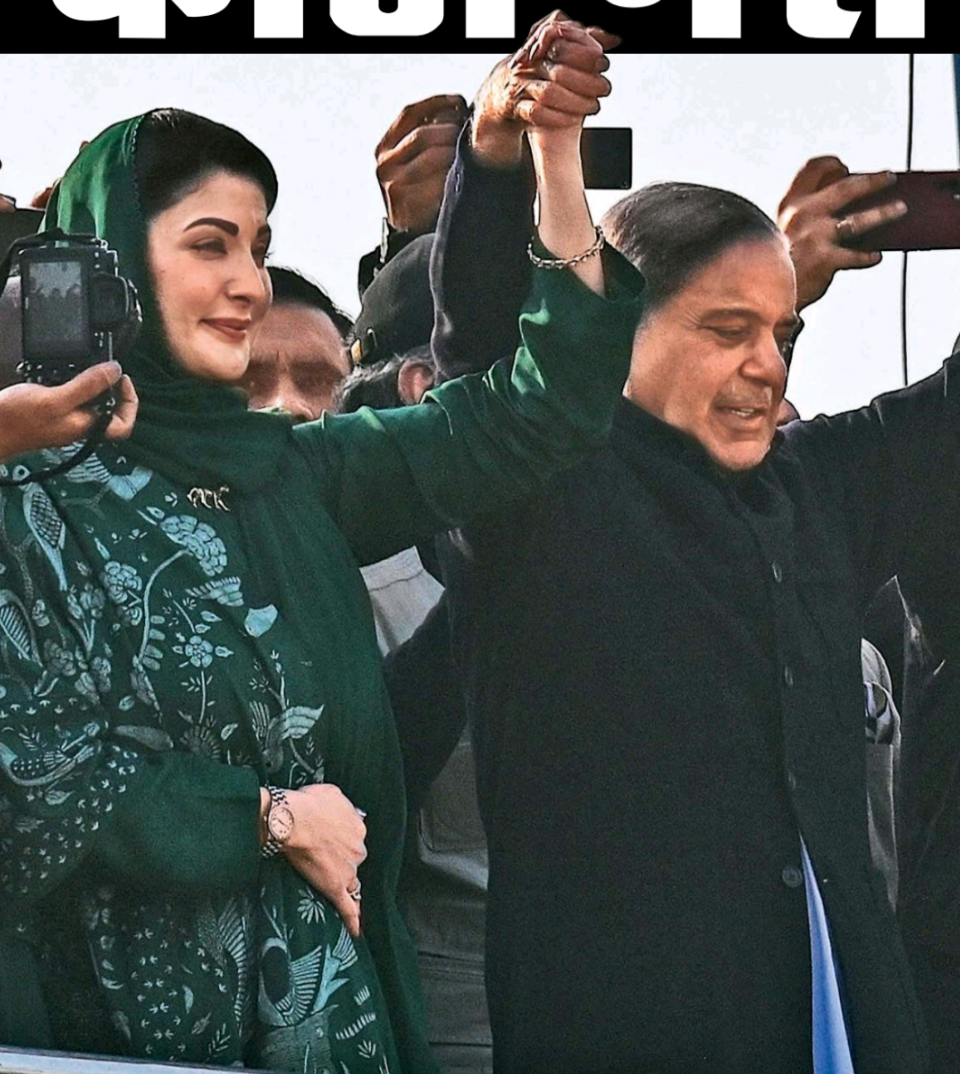
खंडित जनादेश के बाद शहबाज शरीफ फिर वजीर-ए-आजम बनने को तैयार, मगर उनके सामने ढहती अर्थव्यवस्था, बेहिसाब महंगाई, अराजक इमरान समर्थकों और फौजी दबदबे से जूझने की चुनौती

हसन जैदी, *कराची में*

एकजुटता की ताकत
पंजाब के कसूर में 6 फरवरी को पीएमएल-एन की रैली में मरियम नवाज अपने चाचा शहबाज और अब्बा पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ

किस्तान में तवारीख जैसे फिर-फिर उसी मोड़ पर लौट आती है. जाने-माने शायर सलमान पीरजादा की आम चुनाव 2024 के नतीजों पर चुटीली बातें सब कुछ बयान कर देती हैं. उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट में चुटकी ली, ''जालिमों ने ऐसी जबरदस्त धांधली की कि मुझे 2018 के चुनावों की याद दिला दी.'' वे जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के नाराज समर्थकों की चीख-चिल्लाहट का हवाला देते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) पार्टी को बहुमत से दूर रखने के लिए नतीजों में गड़बड़ी की गई. हालांकि पटीआइ से जुड़े उम्मीदवारों को नेशनल असेंबली में सबसे अधिक सीटें आईं. फिर, पीरजादा 2018 के पिछले आम चुनाव का हवाला देते हैं, जब दूसरी पार्टियों ने आज जैसी ही चुनावी धांधली का आरोप मढ़ा था और इमरान खान के हाथ मामूली फासले से सत्ता आ गई थी.

पहली नजर में दोनों आरोपों में दम नजर आता है. 2018 की तरह, इस बार भी कई सीटें ऐसी हैं जहां आखिरी दौर की गिनती में वोटों की संख्या शुरुआती दौर के रुझान से एकदम उलट थी. फर्क सिर्फ यह है कि 2018 में पीटीआइ मजे-मजे फायदे में थी, जबकि 2024 में उसे खामियाजा भुगतना पड़ा और वह हंसी-खुशी विरोधी पार्टियों के हक में आ गई. इनमें खासकर पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन), पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) और सिंध की शहरी पार्टी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट (एमक्यूएम) हैं. दोनों बार आरोपों के निशाने पर 'फौजी हुक्मरान' हैं.

इससे भूमिकाओं में भी ऐतिहासिक बदलाव आ गया. पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट कप्तान अप्रैल, 2022 में सत्ता से बेदखल हो गए, क्योंकि उन्होंने उसी 'फौजी निजाम' को नाराज कर दिया, जिसकी मदद से उन्हें 2018 में वजीरे आजम की गद्दी मिली थी. इमरान मई, 2023 से कैद में हैं, और उन्हें एक के बाद एक तीन मामलों में 14 साल तक की जेल की सजा सुनाई गई है, जिनमें दो तो चुनाव से महज हफ्ते भर पहले ही सुनाए गए. इस बीच, निजाम ने नवाज शरीफ को बहाल कर दिया है. उन्हें उनके तीसरे कार्यकाल के चौथे साल 2017 में प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया था, और छह साल जिल्लत में काटने पड़े, जिनमें चार साल विदेश

चुनाव 2024 खंडित सियासत

पाकिस्तान नेशनल असेंबलीः मोटी जानकारी

★-पाकिस्तान की नेशनल असेंबली पार्लियामेंट का निचला सदन है. उसमें कुल 336 सीटों में जनरल/चुनाव वाली 266 के लिए वोट पड़ते हैं. सरकार बनाने के लिए किसी पार्टी को कम से कम 134 जनरल सीटों की जरूरत होती है. जनरल सीटें चार सूबों में बंटी हुई हैं—पंजाब (141 सीटें), सिंध (61), खैबर पख्तूनख्वा (45), बलूचिस्तान (16). इस्लामाबाद में तीन सीटें हैं

★-इसके अलावा 60 नामजद सीटें औरतों और 10 नामजद सीटें अल्पसंख्यकों के लिए रिजर्व हैं

★-नामजद सीटें पार्टियों को 266 जनरल सीटों पर उनकी आनुपातिक ताकत के आधार पर आवंटित की जाती हैं

★-किसी पार्टी को हर 3.5 सीटें जीतने पर एक औरत सीट मिलती है

★-अल्पसंख्यकक सीटें हर सूबे को उनकी संबंधित अल्पसंख्यक आबादी के अनुपात में बांटी जाती हैं

ग्राफिकः तन्मय चक्रवर्ती

बड़ी दस्तक
कराची में 5 फरवरी की रैली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी (बीच में)

में देश-निकाले की तरह बिताने पड़े. पिछले वक्त फौजी हुक्मरानों से उनके टकराव और तमाम जुर्मों पर सजा को अदालतों ने विराम लगा दिया, ताकि शायद फौज को इमरान खान को सियासी मात देने का मौका मिल जाए. फौज इमरान समर्थकों के रावलपिंडी फौजी मुख्यालय पर हमले और मई, 2023 में लाहौर कोर कमांडर के आवास पर आगजनी से और नाराज हो गई. नए फौज प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने उपद्रवियों पर देश भर में सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया है.

आम चुनावों से पहले चुनाव आयोग ने पीटीआइ पर बतौर पार्टी चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी, चुनाव चिह्न (बल्ला) और पार्टी के भीतर चुनाव नियमों का पालन न करने के लिए झंडे भी जब्त कर लिए. फिर भी, इमरान के जेल में बंद होने के बावजूद पीटीआइ समर्थकों के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन से सत्ता-प्रतिष्ठान चौंक गया. बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ने को मजबूर इमरान की पीटीआइ

फौज ने पहले ही इशारा कर दिया है कि उसकी पसंद नवाज के बजाए शहबाज हैं. आखिर नवाज अपनी चलाने के लिए जाने जाते हैं

नेशनल असेंबली 2024

जनरल सीटें **266**

जरूरी बहुमत **134**

93, 75, 54, 17, 6, 19, 2
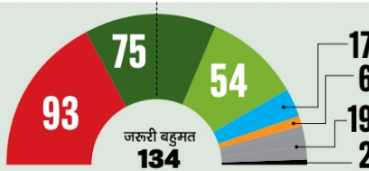
सूबाई चुनाव*

पंजाब
जनरल सीटें : **297**
जरूरी बहुमत : **149**
137, 116, 10, 8, 25, 1
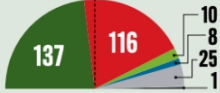
खैबर पख्तूनख्वा
जनरल सीटें : **115**
जरूरी बहुमत : **59**
84, 7, 5, 4, 13, 2
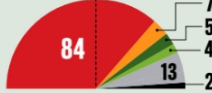
सिंध
जनरल सीटें : **130**
जरूरी बहुमत : **66**
84, 28, 11, 7
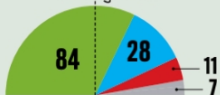
बलूचिस्तान
जनरल सीटें : **51**
जरूरी बहुमत : **27**
11, 11, 10, 4, 2, 13

*साथ-साथ चुनाव हुए

पीटीआइ से जुड़े निर्दलीय · पीएमएल-एन · पीपीपी · पीएमएल-क्यू · जेयूआइ-एफ · एमक्यूएम · बलूचिस्तान अवामी पार्टी · अवामी नेशनल पार्टी · निर्दलीय और अन्य · खाली/चुनाव टला

से जुड़े उम्मीदवार नेशनल असेंबली की कुल 265 सीटों (एक सीट का चुनाव टल गया) में से 93 सीटें जीत गए. हालांकि यह बहुमत के लिए जरूरी 134 सीटों से काफी कम है, मगर यह संख्या बाकी दलों में सबसे अधिक है. शरीफ की पीएमएल-एन को सिर्फ 75 सीटें मिलीं. बिलावल भुट्टो के नेतृत्व वाली पीपीपी 54 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर रही, और एमक्यूएम-पी 17 सीटों के साथ चौथे स्थान है. बाकी सीटें एक दर्जन से ज्यादा छोटी पार्टियों के पास गईं. पीटीआइ ने ऐलान किया है कि वह करीब 80 सीटों के नतीजों को अदालत में चुनौती देगी. उधर, चुनाव करवाने वाले कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकड़ ने नतीजों को सही करार दिया. उन्होंने दलील दी, ''वाकई धांधली का मंसूबा होता, तो सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाले क्या ऐसे जीत जाते?''

केंद्र में कोई भी एक पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, और कोई नए चुनाव कराने के पक्ष

में नहीं है, इसलिए गठबंधन सरकार ही लाजिमी है. इमरान ने जेल से ही पीटीआइ के किसी मुख्य पार्टी के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया. इसलिए, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) गठबंधन सरकार ही इकलौता विकल्प है, जिसे लोग पीडीएम-2.0 कह रहे हैं. पीडीएम ने अप्रैल, 2022 में अविश्वास प्रस्ताव में इमरान के सत्ता गंवा बैठने के बाद डेढ़ साल तक सत्ता संभाली थी. उसमें पीएमएल-एन और पीपीपी के अलावा कई इमरान-विरोधी पार्टियां हैं, जो मिलकर बहुमत का आंकड़ा पार कर जाती हैं.

हालांकि, आम चुनाव के साथ हुए सूबों के चुनाव से हालात और पेचीदा हो गए हैं. सबसे ताकतवर सूबे पंजाब में पीएमएल-एन ने कुल 297 जनरल सीटों में से 137 सीटें जीतीं, जो 149 सीटों के जरूरी बहुमत से 12 कम हैं. वजह यह कि पीटीआइ ने 116 सीटें जीतकर और वोटों का तकरीबन सीधा बंटवारा करने में कामयाब होकर हैरान कर दिया. सबसे अशांत सूबे खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआइ ने 115 जनरल सीटों में से 84 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल कर लिया, तो वहां उसकी सरकार बनाना तय है. देश की तीसरी बड़ी ताकत पीपीपी ने सिंध में 130 में से 84 सीटों के साथ अपने गढ़ को बरकरार रखा. बलूचिस्तान में दिलचस्प तीतरफा बंटवारा हुआ, जिससे पीपीपी गठबंधन सरकार बना सकती है.

एपी

शहबाज की मुश्किलें

केंद्र में पीडीएम 2.0 सरकार बनाने की तैयारियों के मद्देनजर पीएमएल-एन और पीपीपी के बीच तगड़ी सौदेबाजी का अंदाजा है, जिससे सरकार के आराम से चलने को लेकर शक पैदा हो गया है. इरादों के शुरुआती इजहार से तो लगता है कि बड़े भाई नवाज शरीफ के बजाए पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ही नए प्रधानमंत्री होंगे. नवाज शरीफ ने चुनाव से पहले ही इशारा कर दिया था कि अगर पीएमएल-एन को चुनाव में साफ जनादेश नहीं मिला तो वे चौथी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं संभालना चाहेंगे. सियासी पंडितों का यह भी कहना है कि फौज ने चुपचाप अपनी पसंद शहबाज को बता दिया है. फौजी हुक्मरान नवाज की बनिस्बत शहबाज के साथ अधिक सहज रहे हैं, क्योंकि नवाज की फितरत ज्यादा अपनी चलाने की होती है. मगर फिलहाल शहबाज अल्पमत सरकार ही चलाएंगे, क्योंकि पीपीपी ने सरकार में शामिल होने के बदले बाहर से समर्थन देने का फैसला किया है. पीपीपी के को-चेयरमैन बिलावल भुट्टो-जरदारी और पीएमएल-एन के अध्यक्ष शहबाज शरीफ दोनों ने ऐलान किया है कि वे खुशी से नहीं, बल्कि ''देश के व्यापक हित में'' सरकार बनाने जा रहे हैं.

पीपीपी की सरकार में हिस्सेदारी की दिलचस्पी न होने की वजह शायद यह हो सकती है कि यह कांटों का ताज पहनने जैसा है. फिर, पिछली पीडीएम सरकार के बारे में पार्टी को लेकर लोगों में गलतफहमी और पहले के मुख्य विरोधियों के साथ गलबहियां डालने से भविष्य में पार्टी के सियासी नतीजों पर असर की फिक्र भी हो सकती है. उधर, देश की अर्थव्यवस्था खस्ताहाल है—विकास दर में गिरावट आई है, इसकी बड़ी वजह तो इमरान सरकार की बदइंतजामी रही है, मगर उसके बाद आई पीडीएम

पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था खस्ताहाल है. उसे पटरी पर वापस लाने के लिए कड़ी शर्तों वाले आइएमएफ कार्यक्रम से जुड़ना पड़ सकता है

सरकार पर लोगों का ठीकरा फूटा. महंगाई दर करीब 40 फीसद बनी हुई है और फलों, सब्जियों और पेट्रोल सहित सभी जरूरी सामान की कीमतें आसमान छू रही हैं. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) का अनुमान है कि पाकिस्तान का बाहरी कर्ज 2023-24 में 130.8 5 अरब डॉलर छू जाएगा, जो 2022-23 के 123.57 अरब डॉलर से ज्यादा है. अर्थव्यवस्था की बहाली के लिए फौरन कुछ सख्त उपायों की जरूरत होगी, जिससे लोग नाराज होकर सड़क पर उतर सकते हैं. इस पर भी आम राय है कि फौरन कड़ी शर्तों वाले आइएमएफ मदद कार्यक्रम में शामिल होना होगा. फौज के नियंत्रण वाली विशेष निवेश सुविधा परिषद (एसआइएफसी) पहले ही नेशनल एयरलाइन पीआइए और पाकिस्तान स्टील मिल्स जैसे सरकारी सफेद हाथियों को निजी क्षेत्र को देने की सिफारिश कर चुकी है. निजीकरण के इस नए दौर से बिलाशक मजदूरों की नाराजगी बढ़ेगी. सो, खस्ताहाल अर्थव्यवस्था और उसकी बहाली शरीफ भाइयों के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होगी.

पिंजरे में कैद शेर
मई 2023 में इस्लामाबाद की एक अदालत में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (एकदम बाएं); कराची में 11 फरवरी को प्रदर्शन करते इमरान समर्थक

एपी

नवाज की पहेली

पीएमएल-एन ने नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भले जोरदार चुनाव प्रचार किया, मगर कई लोगों का तब भी लगा था कि बड़े शरीफ असल में अपनी बेटी मरियम की सियासी जमीन तैयार करने और यह साबित करने में जुटे थे कि 2017 में उनसे नाजायज तरीके से कुर्सी छीनी गई थी. हो सकता है कि उन्होंने ये दोनों लक्ष्य हासिल कर लिए हों, मगर अब बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा कि पंजाब की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मरियम नवाज कैसा कामकाज दिखाती हैं. दरअसल, पीएमएल-एन का खासकर पंजाब में महत्वाकांक्षी नाराज नौजवानों से सामना है, जो अमूमन रिवायती सियासी पार्टियों के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे हैं. पीएमएल-एन के अपने उम्मीदवारों के चयन से भी इशारा मिलता है कि शरीफ परिवार ही उसके केंद्र में है और वही तय करता है कि किस पर भरोसा करना है. अब देखना यह है कि क्या मरियम इस धारणा को बदल सकती हैं और नौजवानों को पार्टी की ओर खींच सकती हैं. उन्हें अपना रवैया भी बदलना पड़ सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि उन्हें असहमति बर्दाश्त नहीं होती.

पीएमएल-एन केंद्र और पंजाब में सरकार बनाने तो जा रही है, मगर पार्टी इस हकीकत से भी रू-ब-रू है कि उसे पंजाब सूबे के मध्य हलके में गंभीर झटके लगे हैं, जिसे वह अपना गढ़ मानती है. पार्टी के बड़े लीडर पीटीआइ के गुमनाम उम्मीदवारों के सामने हार गए. पूर्व गृह मंत्री और पंजाब पीएमएल-एन के अध्यक्ष राना सनाउल्लाह अपनी सीट भी हार गए. उन्होंने जो कहा, उसमें दम है. उन्होंने एक टीवी चैनल से कहा, ''इस चुनाव में मुख्य मुद्दा महंगाई है. लोग बिजली, गैस और पेट्रोल के दाम बढ़ने से नाराज हैं, उन्हें बिलों का भुगतान करने के लिए अपने घरेलू सामान बेचने पड़ रहे हैं. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने (चुनाव प्रचार में) क्या कहा, उससे इन तीन चीजों का दर्द भुलाया नहीं जा सका. चुनाव के बीच (इमरान खान को) तीन मामलों में दोषी ठहराए जाने का शायद उलटा असर हुआ और उनके हक में सहानुभूति लहर चली, भले ही यह अदालती कार्रवाई थी, हमारा कोई लेना-देना नहीं था.''

भुट्टो का गणित

पीपीपी के केंद्र में सरकार को बाहर से समर्थन देने के फैसले पर पीएमएल-एन के कई वरिष्ठ नेताओं ने नाराजगी जाहिर की है कि पीपीपी हिस्सेदारी से बचना भी चाहती है और मलाई भी काटना चाहती है. अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, पीपीपी समर्थन के बदले में पीएमएल-एन से राष्ट्रपति पद, सभी चार सूबों की गवर्नरशिप, नेशनल असेंबली के स्पीकर और सीनेट के चेयरमैन का पद मांग रही है. दिलचस्प यह है कि इसका मतलब न सिर्फ आसिफ अली जरदारी की राष्ट्रपति पद पर वापसी होगी, बल्कि ये तमाम संवैधानिक पद असेंबलियों के जल्दी भंग हो जाने पर भी बरकरार रहेंगे.

बिलावल ने 13 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरदारी के दोबारा राष्ट्रपति बनने की वकालत की. उन्होंने कहा, ''मैं यह इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वे मेरे अब्बा हैं, बल्कि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान में आग लगी हुई है और सिर्फ उन्हीं में उसे बुझाने की सलाहियत है.'' मौजूदा हालात के मद्देनजर यह पीपीपी के लिए सबसे स्मार्ट रणनीति हो सकती है, बिलावल इन चुनावों में पीपीपी को मिले फायदे को और मजबूत करने की ओर देख रहे होंगे. एक तो, पीपीपी ने सिंध सूबे (कराची को छोड़कर) में भारी जीत हासिल

की और एक बार फिर सभी चारों सूबों में प्रतिनिधित्व वाली इकलौती पार्टी बनकर उभरी है. पार्टी बलूचिस्तान में (मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत-ए-उलेमा-ए-इस्लाम या जेयूआइ-एफ के साथ) मिलकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और सिंध और बलूचिस्तान दोनों में सरकार बनाने जा रही है. नेशनल असेंबली में भी उसकी संख्या में सुधार हुआ. लेकिन 1990 के दशक के बाद से पंजाब में उसने जो जमीन खो दी है, उसे वापस पाने के लिए उसे कड़ी मेहनत करनी होगी. देश में तकरीबन आधे वोटरों वाला पंजाब ही मायने रखता है. हालांकि, मुख्यधारा के सबसे नौजवान नेता के नाते बिलावल के पास वक्त है.

पीपीपी की सरकार में शामिल होने में हिचक की वजह यह एहसास हो सकता है कि यह कांटों भरा ताज है और नौजवान बिलावल के पास अभी काफी लंबा वक्त है

इमरान की लंबी छाया

अलबत्ता इस बात से किसी को कम ही गुरेज है कि तमाम उम्मीदों के विपरीत पीटीआइ वह करने में कामयाब रही जो उससे पहले कोई भी पार्टी अपने खिलाफ सत्ता-प्रतिष्ठान के ऐसे हमले के सामने नहीं कर पाई थी. वह न केवल अपने सामने पैदा की गई चुनावी बाधाओं को नाकाम करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में सफल रही—साझा चुनाव चिह्न न होते हुए भी उसने मतदाता तक यह जानकारी पहुंचाई कि हरेक निर्वाचन क्षेत्र में किस उम्मीदवार को वोट देना है—वह उन खुफिया अफसरों को भी गच्चा दे सकी जिनका काम ही पीटीआइ की लामबंदियों पर निगाह रखना था. इन नतीजों ने निश्चित रूप से इमरान का हौसला बढ़ाया है, जिन्हें चुनावों से ठीक हफ्ते भर पहले तीन अलग-अलग मामलों में 10 साल, 14 साल और सात साल की सजा दी गई थी. इनमें से पहले दो मामले उनकी तरफ से सरकारी स्तर के उपहारों में से अपने लिए रखी गई महंगी वस्तुओं के बारे में गलतबयानी और कुख्यात 'साइफर' मामले में सरकारी गोपनीयता कानून के उल्लंघन से जुड़े थे. अलबत्ता जिसने कई लोगों को नाराज कर दिया, वह तीसरा फैसला था, जिसमें उन्हें और उनकी बीवी बुशरा को इसलिए दोषी ठहराया गया कि बुशरा की 'इद्दत' की इस्लामी अवधि पूरी होने या पिछली शादी के बाद इंतजार करने से पहले ही उन्होंने शादी का करार कर लिया.

यहां तक कि जो लोग इमरान और उनकी लगातार सियासी लफ्फाजी और गतिविधियों के खिलाफ थे, वे भी सत्ता-प्रतिष्ठान के एक ऐसे मामले में पड़ने से नाराज थे जो लाजिमी तौर पर पूरी तरह निजी मामला था. पीटीआइ के समर्थकों ने जाहिरा तौर पर इसे इमरान के साथ घोर नाइंसाफी की एक और मिसाल की तरह देखा और शायद इसी की झलक उनके मतदान के लिए बड़े

देश का नया खैरख्वाह

पाकिस्तान के नए फौज प्रमुख आसिम मुनीर देश में जम्हूरियत के फलने-फूलने के पैरोकार हैं. उनकी चुनौती यह है कि सियासी तौर पर निष्पक्ष बने रहें और देश की हिफाजत में फौज की भूमिका को बदस्तूर बनाए रखें

पाकिस्तान में अकेला सबसे ताकतवर शख्स आम तौर पर फौज प्रमुख ही होता है और अभी उस ओहदे पर जनरल आसिम मुनीर हैं, जिन्होंने 29 नवंबर, 2022 को कुछ विवादों के बीच पाकिस्तान फौज की कमान संभाली थी, हालांकि उस समय वे सबसे वरिष्ठ लेफ्टिनेंट जनरल थे.

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उनको जनरल कमर जावेद बाजवा के स्थान पर चुना था जो एक विस्तार पाने के बाद अपने तीन साल के कार्यकाल की दो अवधि पूरी कर चुके थे. पता चला कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जनरल मुनीर की नियुक्ति के पक्ष में नहीं थे. हालांकि असल में पीटीआइ के सर्वेसर्वा ने सार्वजनिक रूप से इससे इनकार किया लेकिन बाद में हुई घटनाओं से इन शुरुआती अफवाहों की पुष्टि होती दिखाई दी.

जनरल मुनीर के प्रति इमरान की चिढ़ की कुछ वजहें थीं. पहला यह कि उनकी नियुक्ति से इमरान खान के पसंदीदा उम्मीदवार जनरल फैज हामिद की सेना प्रमुख बनने की संभावना तुरंत खत्म हो जाती. जनरल फैज पर आरोप है कि वे इमरान का मजबूत हाथ थे और 2018 के चुनाव से पहले नेताओं पर पीटीआइ में शामिल होने के लिए दबाव डालने में मदद कर रहे थे और जब इमरान प्रधानमंत्री थे तो उस दौरान वे सियासी मामले भी देख रहे थे.

लेकिन जनरल मुनीर और इमरान खान के बीच तनाव होने का सबसे बड़ा संकेत यह था कि उन्हें अचानक आइएसआइ के महानिदेशक पद से हटा दिया गया जबकि उन्होंने आठ महीने पहले ही 2019 में यह पद संभाला था. आइएसआइ के मुखिया का
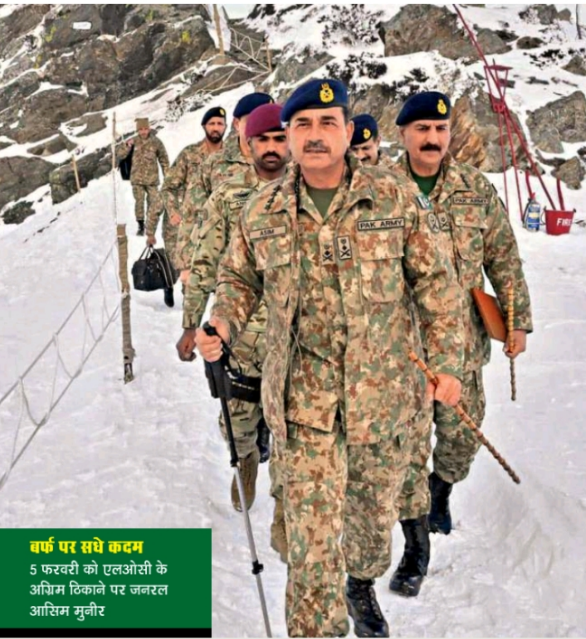
बर्फ पर सधे कदम
5 फरवरी को एलओसी के अग्रिम ठिकाने पर जनरल आसिम मुनीर

सामान्य कार्यकाल तीन साल होता है. यह भी चर्चा थी, हालांकि इसकी कभी पुष्टि नहीं हुई, कि जनरल मुनीर ने जब इमरान के नजदीकी लोगों के भ्रष्टाचार के मसले की तरफ उनका ध्यान खींचा तो समस्याएं खड़ी होने लगीं. उनकी जगह जनरल फैज को आइएसआइ का मुखिया बनाया गया.

काफी अनुभवी अधिकारी

रावलपिंडी में जन्मे जनरल मुनीर को उत्कृष्ट अधिकारी माना जाता है. हालांकि यह भी सच है कि वे किसी फौजी अफसर के खानदान से नहीं हैं और वे मंगला में ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल के जरिए 1986 में फौज में भर्ती हुए. मंगला में उन्हें 'स्वर्ड ऑफ ऑनर' का प्रतिष्ठित सम्मान मिला. वे काकुल का हिस्सा कभी नहीं रहे जबकि उनसे पहले के सभी सेनाध्यक्ष काकुल में लंबे प्रशिक्षण दौर से गुजरे हैं.

सूत्रों के मुताबिक, जनरल मुनीर को यकीन हो गया कि मई 2023 में इमरान की गिरफ्तारी के बाद पीटीआइ समर्थकों का उपद्रव फौज में बगावत भड़काने की कोशिश थी

उनकी सैन्य परिवार की भी पृष्ठभूमि नहीं है. उनके पिता स्कूल शिक्षक थे और एक मस्जिद में इमाम थे. उनकी शुरुआती शिक्षा मदरसे में हुई. उन्होंने साल साल की उम्र में ही कुरान को कंठस्थ कर लिया. यही वजह है कि उन्हें अक्सर हाफिज साहब कहा जाता है जिसका मतलब है जिसने कुरान को कंठस्थ कर रखा हो.

वे जनरल बाजवा के करीबी रहे हैं और उन्होंने उनकी मातहती में इन्फैंट्री ब्रिगेडियर के रूप में काम किया, सियाचिन समेत फोर्स कमान नॉर्दर्न एरियाज में फौज की कमान संभाली. वे गुजरांवाला में भी कोर कमांडर रहे और अपने करियर के दौरान पूरी फौज को आपूर्ति करने वाले क्वार्टर मास्टर जनरल रहे. सबसे दिलचस्प शायद यह है कि वे इकलौते ऐसे फौज प्रमुख हैं जो मिलिट्री इंटेलिजेंस (सैन्य खुफिया) और आइएसआइ दोनों के प्रमुख रहे.

इस्लामाबाद हाइकोर्ट के अहाते से इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जब 9 मई, 2023 को पूरे पाकिस्तान में हिंसक झड़पें हुईं तो पीटीआइ समर्थकों के खिलाफ देश भर में धरपकड़ की गई. सेना के भीतर मौजूद सूत्रों का दावा है कि जनरल मुनीर इससे सहमत थे कि यह दंगा-फसाद फौज के भीतर बगावत भड़काने की सुनियोजित कोशिश थी. लिहाजा, फौज ने दंगाइयों के खिलाफ सैन्य अदालतों में मुकदमा चलाने के लिए दबाव डाला, हालांकि नागरिक समाज के एक तबके और अदालतों ने इसका विरोध किया.

जनरल मुनीर ने सियासी तौर पर पक्षपात का जोरदार तरीके से खंडन किया है और देश में जम्हूरियत को समृद्ध होते देखने का अपना संकल्प जताया है, लेकिन पीटीआइ में कई लोग मान रहे हैं कि उनकी मौजूदा समस्याएं तब तक खत्म नहीं होंगी जब तक कि जनरल मुनीर के हाथ में कमान है. विदेश में बैठे पार्टी के कई समर्थक सोशल मीडिया पर उन्हें लगातार निशाना बनाते रहे हैं. पाकिस्तान की सियासत जिस तरह बंटी हुई है, उसमें आने वाले महीनों में जनरल मुनीर को राजनैतिक रूप से तटस्थ रहते हुए सेना की मांगों के साथ संतुलन साधना पड़ेगा. साथ ही, यह आश्वस्त करना होगा कि सशस्त्र सेना का उम्मीदों भरा यह विश्वास बना रहे कि उसके भले में ही पाकिस्तान का भला है.

—हसन जैदी

पाकिस्तानी चुनावों की पेचीदा रहगुजर

पाकिस्तान के पहले राष्ट्रीय आम चुनाव, 1970 में, बांग्लादेश के निर्माण की तरफ ले गए. उसके बाद हुए नेशनल असेंबली के 10 चुनावों में केवल दो बार किसी एक पार्टी को बहुमत मिला. यही नहीं, किसी एक भी प्रधानमंत्री ने कभी अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया

1947-1970

आजादी के बाद पाकिस्तान ने 1951 में पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, 1953 में सिंध और 1954 में पूर्व पाकिस्तान के सूबाई चुनाव करवाए. राष्ट्रव्यापी चुनाव वाला संविधान 1956 में लागू हुआ, पर सियासी उथल-पुथल रही जिसमें एक के बाद एक प्रधानमंत्री नियुक्त और बर्खास्त किए गए. 1958 में मार्शल लॉ लगा दिया गया और जनरल अय्यूब खान ने तख्तापलट कर दिया, 1959 में होने वाले चुनाव स्थगित कर दिए. उनकी निगहबानी में 1962 में हुए चुनाव अप्रत्यक्ष थे जिनमें कोई सियासी पार्टी शामिल नहीं थी.

1977

जुल्फिकार अली भुट्टो की अगुआई वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नेशनल असेंबली (एनए) की 200 में से 155 सीटें जीतीं, जो जबरदस्त जीत थी. दक्षिणपंथी पार्टियों का गठबंधन पाकिस्तान नेशनल एलायंस (पीएनए) मात्र 36 सीटें जीत सका. हालांकि पीपीपी के खिलाफ चुनावी धांधली के आरोप लगाए गए और बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए

★ अशांति और अफरातफरी के बीच फौज प्रमुख जनरल जिया-उल-हक ने मार्शल लॉ का ऐलान किया और भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया गया. जुलाई 1977 में जनरल जिया ने तख्तापलट कर दिया. भुट्टो के खिलाफ हत्या के आरोप लगे, लंबे मुकदमे और अपील के बाद 4 अप्रैल, 1979 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया

1985

जनरल जिया की फौजी हुकूमत के मातहत गैर-दलीय आधार पर सियासी पार्टियों की शिरकत के बगैर चुनाव करवाए गए. जिया के समर्थक निर्दलीयों ने एनए की सभी चुनाव योग्य 207 सीटें जीत लीं. जिया का विरोध कर रही पार्टियों के गुट मूवमेंट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी ने चुनावों का बहिष्कार किया

★ सरकार बनी जिसके प्रधानमंत्री मुहम्मद खान जुनेजो थे. मार्च, 1988 में जिया ने उन्हें ''भ्रष्ट और नकारा'' होने की वजह से बर्खास्त कर दिया और एक और पार्टीविहीन चुनाव का फैसला किया, लेकिन अगस्त में एक विमान दुर्घटना में उनकी मौत का मतलब यह था कि पाकिस्तान बहुदलीय चुनावों की तरफ लौट सका

1988

भुट्टो की बेटी **बेनजीर** की अगुआई में पीपीपी ने एनए की 204 में से 93 सीटें जीतीं, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता नवाज शरीफ की अगुआई में जिया समर्थक पार्टियों का गठबंधन इस्लामी जम्हूरी इत्तेहाद (आइजेआइ) रहा जिसने 56 सीटें जीतीं

★ पीपीपी ने गठबंधन सरकार बनाई; बेनजीर भुट्टो किसी मुस्लिम मुल्क की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं

★ राष्ट्रपति गुलाम इसहाक खान ने अगस्त 1990 में 'भ्रष्टाचार' का हवाला देकर बेनजीर सरकार को बर्खास्त कर दिया

1990

नवाज शरीफ की अगुआई वाले आइजेआइ गठबंधन ने एनए की 207 में से 105 सीटें जीतीं, पीपीपी और बेनजीर की अगुआई वाले चार पार्टियों के पीपल्स डेमोक्रेटिक एलायंस (पीडीए) को सिर्फ 44 सीटें मिलीं. शरीफ प्रधानमंत्री बने

★ शरीफ ने राष्ट्रपति खान की ताकत पर लगाम कसने की कोशिश की, जिन्होंने 1993 में उनकी सरकार 'भ्रष्टाचार' के लिए बर्खास्त कर दिया. अदालत ने शरीफ के पक्ष में फैसला दिया, पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो खान ने भी ऐसा ही किया

1993

पीपीपी ने एनए में बहुमत सीटें—89—जीतीं, पर यह काफी नहीं था. शरीफ की नए नाम वाली पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) ने 73 सीटें जीतीं. 1988 की तरह बेनजीर ने छोटी-छोटी पार्टियों की मदद से गठबंधन बनाया और दूसरी बार प्रधानमंत्री बन गईं

★ प्रधानमंत्री और उनके शौहर **आसिफ अली जरदारी** के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों और राजनैतिक उथल-पुथल के बीच राष्ट्रपति फारूक लेगारी ने 1996 में सरकार को बर्खास्त कर दिया

1997

पीएमएल-एन ने आम चुनाव में 217 में से 135 सीटें जीतीं और भ्रष्टाचार के खिलाफ भारी बहुमत वाला जनादेश हासिल किया. पीपीपी महज 18 सीटें जीत सकी. शरीफ दूसरी बार प्रधानमंत्री बने; बेनजीर मुल्क छोड़कर चली गईं

★ 1999 के करगिल युद्ध के बाद शरीफ ने फौज प्रमुख **जनरल परवेज मुशर्रफ** को हटाने की कोशिश की, जिन्होंने 1999 में तख्तापलट करके उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया और 2001 में राष्ट्रपति बने

★ शरीफ गिरफ्तार और भ्रष्टाचार के मुकदमे में 14 साल कैद की सजा सुनाई गई. वे निर्वासन में चले गए. जनरल मुशर्रफ ने 2002 में चुनाव करवाए

2002

मियां मुहम्मद अजहर की अगुआई में मुशर्रफ समर्थक पीएमएल (कायद) ने 118 सीटें जीतीं, जबकि अमीन फहीम की अगुआई में पीपीपी ने (बेनजीर निर्वासन में थीं और उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में सजा सुनाई जा चुकी थी) 8 1 सीटें जीतीं. दक्षिणपंथी मजहबी पार्टियों के गठबंधन मुतहिदा मजलिस-ए-अमल (एमएमए) ने 60 सीटें जीतीं, जबकि पीएमएल (एन) को 19 सीटें मिलीं

★ पीएमएल (क्यू) ने एमएमए के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई, जिसमें मीर जफरुल्ला खान जमाली प्रधानमंत्री बने. फौज के साथ मतभेदों के चलते 2004 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया; शौकत अजीज को प्रधानमंत्री बनाया गया

★ बढ़ती दहशतगर्दी, लाल मस्जिद की कार्रवाई, बलूच नेता अकबर बुगती की हत्या ने मुशर्रफ को 2007 में इमरजेंसी लगाने को मजबूर कर दिया. 2008 में उन्होंने चुनावों का ऐलान किया, जिन पर दिसंबर 2007 में बेनजीर भुट्टो की हत्या का साया पड़ गया

2008

हमदर्दी की लहर पर सवार पीपीपी ने 272 में से 122 सीटें जीतीं, जबकि पीएमएल (एन) को 92 और पीएमएल (क्यू) को 41 सीटें मिलीं. उन्होंने एमक्यूएम और अवामी नेशनलिस्ट पार्टी (एएनपी) के साथ गठबंधन बनाया, जिसमें **यूसुफ रजा गिलानी** प्रधानमंत्री बनाए गए

★ जनरल मुशर्रफ के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू हुई, जो मुल्क छोड़कर निर्वासन में चले गए

★ गिलानी को 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने 'अदालत की मानहानि' की वजह से अयोग्य ठहराया और उनकी जगह राजा परवेज अशरफ आए

★ 2013 में नए चुनाव करवाए गए, पहली बार कोई सरकार पूरे पांच साल चली, जिसमें न तो फौज ने उसके कार्यकाल में कटौती की और न ही राष्ट्रपतियों ने उसे नियंत्रित किया

2013

फिर शरीफ की अगुआई और पीएमएल-क्यू और एनएपी के साथ गठबंधन में पीएमएल-एन ने 272 में से 126 सीटें जीतीं, जबकि जरदारी की अगुआई में पीपीपी ने 38 सीटें जीतीं. इन चुनावों में इमरान की पीटीआइ 27 सीटें जीतकर नई ताकत के तौर पर उभरी. गठबंधन की अगुआई करते हुए शरीफ ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की कमान संभाली

★ पनामा पेपर्स में नाम आने के बाद शरीफ को 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति छिपाने के आरोप में बर्खास्त कर दिया

2018

2018 के आम चुनाव में **इमरान खान** की पीटीआइ ने 116 सीटें जीतीं, जबकि अब शहबाज शरीफ (उनके भाई नवाज अब भी अयोग्य और निर्वासित थे) की अगुआई में पीएमएल-एन ने 64 सीटें जीतीं और पीपीपी 43 सीटें जीतकर तीसरे नंबर पर आई. इमरान ने एमक्यूएम और पीएमएल-क्यू के साथ मिलकर सरकार बनाई और प्रधानमंत्री बने

★ महामारी के साल में गहराते आर्थिक संकट के बीच फौज के साथ बढ़ती तकरार के चलते इमरान अलग-थलग पड़ गए और अप्रैल 2022 में उन्हें अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटा दिया गया

★ इमरान को सत्ता से बेदखल करने के लिए पीएमएल-एन, पीपीपी और अन्य पार्टियां पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) के नाम से गठबंधन बनाकर साथ आईं; शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने

—संकलनः **सैकत नियोगी**

पैमाने पर निकलने में दिखी हो. मगर क्या इसका मतलब यह है कि इमरान जल्द बाहर आ सकते हैं और फिर आजाद हो सकते हैं? ज्यादातर सयाने जानकारों को इसमें शक है. पीटीआइ के लिए अब भी ढेरों अड़चनें हैं, भले ही नेशनल असेंबली में उनके पास सबसे ज्यादा सीटों का गुट हो. एक तो इसलिए कि वे सब एक पार्टी के अनुशासन से बंधे होने के बजाए तकनीकी तौर पर निर्दलीय हैं, और आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं कि दूसरी पार्टियां उन्हें तोड़कर अपने साथ आने के लिए फुसलाने या रिश्वत देने की कोशिश कर सकती हैं. धीरे-धीरे पीएमएल-एन की तरफ बढ़ने का सिलसिला शुरू भी हो गया है.

ऐसा होने से रोकने के लिए यह मुमकिन है कि पीटीआइ अपने निर्दलीय उम्मीदवारों से किसी ऐसी छोटी पार्टी में शामिल होने को कहे जिसे पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) ने इन असेंबली के लिए मान्यता दे रखी है. मजहबी-सियासी पार्टी मजलिस-ए-वहदत-ए-मुस्लिमीन (एमडब्ल्यूएम) के साथ उसकी बातचीत चल भी रही है. निर्दलीय अधिसूचना जारी होने के तीन दिन के भीतर दूसरी पार्टी में शामिल हो सकते हैं और ऐसा करने से वे कानून के दायरे में आ जाएंगे जो उन्हें पाला बदलने से रोकेगा.

दूसरी अड़चन महिलाओं और अल्पसंख्यकों को आवंटित आरक्षित सीटें हैं, जिनसे संसद में सीटों की संख्या अंततः बढ़ जाएगी. ये आरक्षित सीटें सियासी पार्टियों की जीती गई सीटों की संख्या के अनुपात में आवंटित की जाती हैं और निर्दलीयों को उससे बाहर रखा जाता है. पीटीआइ का कहना है कि एमडब्ल्यूएम ने आरक्षित सूची के लिए उम्मीदवारों की पर्याप्त बड़ी सूची नहीं दी है, जैसा कि ईसीपी के नियम कहते हैं. इसके अलावा पीटीआइ उन सीटों के नतीजों को भी चुनौती दे रही है जिन पर उसे लगता है कि हेरफेर किया गया है. दोनों का हश्र अदालतों में याचिकाओं के रूप में हो सकता है. क्या पीटीआइ समय रहते अदालती आदेश हासिल कर पाएगी ताकि वह सरकार के गठन और उसके सियासी दुष्परिणामों को रोक पाए? संभावना बहुत मुश्किल दिखाई देती है.

क्या पीटीआइ के पास सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के माध्यम से अफरा-तफरी फैलाने की ताकत है? यह संभावना भी नजर नहीं आती, खासकर 9 मई को उसके ऐसे आखिरी दुस्साहस के बाद की गई कड़ी कार्रवाई को देखते हुए. मगर हो सकता है कि सत्ता-प्रतिष्ठान और यहां तक कि पीएमएल-एन भी पीटीआइ को कुछ रियायतें देकर मुल्क में ध्रुवीकरण कम करना चाहें. हालांकि तत्काल तो यह संभावना कम ही है कि जिद्दी इमरान को राजनीति में लिप्त होने की खुली छूट दी जाएगी. मसलन, उन्होंने अली अमीन गंडापुर को

भारत-पाकिस्तान रिश्ते

इंतजार करो और देखो

भारत ने अनुच्छेद 370 हटाया तो पाकिस्तान ने दर्जा घटा दिया, अब इस्लामाबाद को उसे बहाल करने की पहल करनी है

शरीफ बंधु—नवाज और शहबाज—भारत के साथ दोस्ताना रिश्तों पर जोर देने के लिए जाने जाते रहे हैं. भले ही वे सत्ता में वापस आ गए हैं, पर विदेश नीति से जुड़ी सारी पहल पाकिस्तानी फौज ही तय करेगी, जैसा कि होता रहा है. थोड़े-से वक्त के लिए जब प्रतिष्ठान की कमान पूर्व फौज प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के हाथों में थी, उन्होंने भारत के साथ बेहतर रिश्तों सहित पास-पड़ोस में अमन-चैन की वकालत करके सियासी तबके तक को हैरान कर दिया था, और अतिवाद से लड़ने तथा दहशतगर्दी को खत्म करने की बात कही थी. पाकिस्तान ने अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद गुस्से में भारत के इस्लामाबाद स्थित उच्चायुक्त को निष्कासित करके, तिजारती रिश्तों को मुल्तवी करके, यातायात की सारी कड़ियों को तोड़कर और भारतीय फिल्मों और नाटकों के प्रदर्शन सहित सारे सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर पाबंदी लगाकर भारत के साथ रिश्तों का दर्जा घटा दिया था. मार्च, 2021 में जनरल बाजवा उस वक्त भारत के प्रति सुलह का रवैया अपनाते लगे जब उन्होंने इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में मौजूद जमावड़े से कहा, ''अतीत को दफना कर आगे बढ़ने का वक्त आ गया है. मगर सार्थक बातचीत की बहाली के लिए पड़ोसी को भी, खासकर भारत के कब्जे वाले कश्मीर में, अनुकूल माहौल बनाना होगा.''

भारत के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत फिर शुरू करने की दो बड़ी पूर्व शर्तें थीं—कि वे दहशतगर्दी के स्रोतों को बंद करें और ऐसा करने के सबूत दिखाएं, और जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली की किसी भी मांग से बाज आएं, जिसे भारत विशुद्ध आंतरिक मामला मानता है. भारत हालांकि पाकिस्तान की हर नई सरकार या फौजी निजाम को रिश्ते सुधारने के मौके के तौर पर देखता है, पर भारतीय विशेषज्ञों का कहना है कि जनरल मुनीर ने अभी तक यह खुलासा नहीं किया है कि भारत के साथ रिश्तों को लेकर उनका नजरिया क्या होगा. यही नहीं, यह पाकिस्तान ही था जिसने भारत के साथ रिश्तों का दर्जा घटाया था, इसलिए गेंद अब इस्लामाबाद के पाले में है. भारत तब तक 'इंतजार करो और देखो' की मुद्रा में है.

—ब्यूरो रिपोर्ट
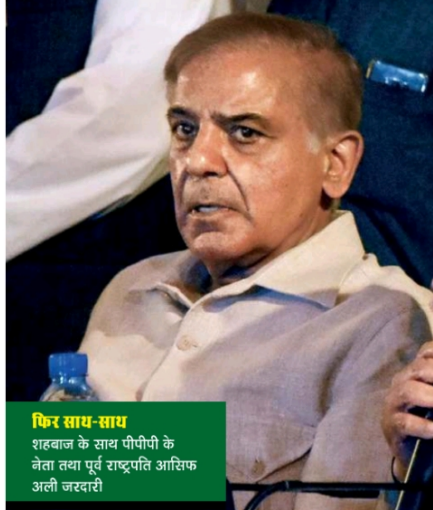
फिर साथ-साथ
शहबाज के साथ पीपीपी के नेता तथा पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी

फौज को यह एहसास हो चला है कि आर्थिक बहाली के लिए सियासी स्थिरता जरूरी है, जिसके बिना उसकी स्थिति भी खतरे में पड़ जाएगी

खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री के पद के लिए नामजद किया है, जो काम करने और नतीजे देने से ज्यादा पार्टी के चतुर रणनीतिकार तौर पर जाने जाते हैं. इसे मुख्य रूप से फौज की जरा परवाह न करने की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि गंडापुर पार्टी के भीतर ज्यादा लोकप्रिय नहीं हैं और उन पर 9 मई के दंगों में शामिल होने के आरोप भी लगे हैं. पाकिस्तान के सियासी जानकारों का मानना है कि अगर कोई लीक से हटकर असामान्य घटनाक्रम नहीं घटता है, तो सियासी उबाल धीरे-धीरे ठंडा होता जाएगा. ऐसी स्थिति में पीटीआइ के लिए चुनौती यह होगी कि वह चुनाव का अगला मौका मिलने तक अपने को साबुत और कायम रखे.

जनरल मुनीर की चुनौती

कुछ लोगों को मौजूदा सियासी फिजा निजाम के लिए बारूद के ढेर की तरह लग सकती है. सियासी पार्टियों की चौतरफा नाराजगी को थोड़ी सावधानी से संभालने की जरूरत होगी. मगर ज्यादा लंबे नजरिये से देखें तो खंडित जनादेश फौज के सियासी इंजीनियरों के लिए अल्लाह तआला का भेजा तोहफा भी है, क्योंकि इससे उन्हें सियासी कर्ताधर्ताओं को फुसलाने

एपी

और उन पर दबाव डालने की ज्यादा गुंजाइश मिल जाती है. अलबत्ता, मौजूदा चुनावी नतीजे सियासत में ध्रुवीकरण के अलावा किसी और चीज की तरफ इशारा करते हैं, और वह है कि जम्हूरी सियासत में छेड़छाड़ करने की फौजी निजाम की ताकत की भी सीमा है, और यह कि चुनावों में हेरफेर करना ज्यादा मुश्किल हो गया है. फौजी निजाम इससे कुछ हद तक शुरू से ही वाकिफ था. यही वजह है कि चुनावों को असेंबलियों के भंग होने से तीन महीने की संवैधानिक तौर पर अनिवार्य अवधि से आगे टाला गया.

पाकिस्तान के डावांडोल आर्थिक हालात के मद्देनजर फौजी निजाम को भी बखूबी एहसास है कि किसी भी आर्थिक बहाली के लिए सियासी स्थिरता सबसे अव्वल जरूरत या पूर्वशर्त है और अर्थव्यवस्था पर ध्यान न देने से संस्था के तौर पर उसकी अपनी हैसियत भी खतरे में पड़ सकती है. मगर ज्यों-ज्यों इस बात के लिए सार्वजनिक शोर-शराबा जोर पकड़ रहा है कि फौज अपने को सियासत से पूरी तरह अलग करे—चुनाव नतीजों से हैरान ज्यादातर सियासी पार्टियां फौरन इसकी मांग कर रही हैं—फौज प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के लिए चुनौती यह होगी कि वे इस मांग और खुद को पाकिस्तान का निर्णायक रक्षक व देश के राष्ट्रीय हितों का मध्यस्थ मानने के सेना के अटूट विश्वास के बीच संतुलन कैसे साधते हैं. ■
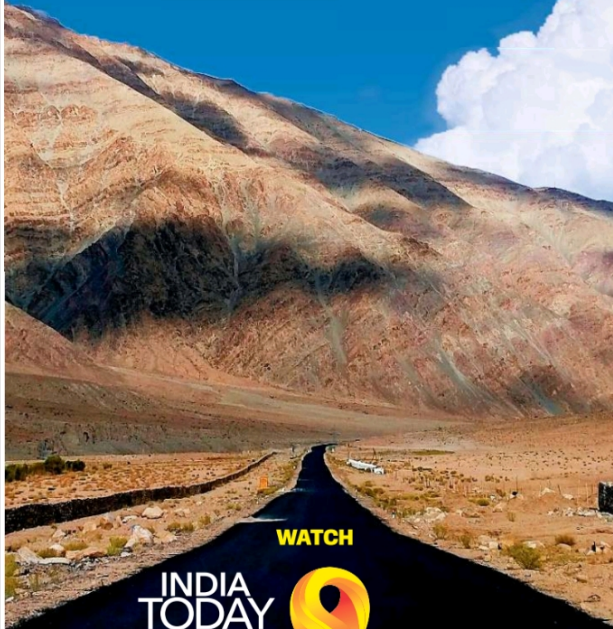
धार्मिक मिशन
अबू धाबी में 14 फरवरी को मंदिर के उद्घाटन के बाद भीड़ का अभिवादन करते प्रधानमंत्री मोदी

दुनियाभर में लहराया आस्था का परचम

ताकतवर स्वामिनारायण संप्रदाय दुनियाभर के विभिन्न शहरों में कुछ सबसे बड़े और भव्य हिंदू मंदिरों का निर्माण कर रहा है. अबू धाबी में हाल में खुला विशाल मंदिर इन्हीं में एक है. इसकी अंदरूनी कहानी कि आखिर वे यह सब कैसे कर रहे हैं

जुमाना शाह

संत पंचमी के दिन दूर-दूर तक फैले रेगिस्तान के बीच स्थित अबू धाबी शहर का बाहरी इलाका संस्कृत के श्लोकों के उच्चारण से गूंज उठा. संयुक्त अरब अमीरात में सबसे बड़े हिंदू मंदिर के उद्घाटन के मौके पर एक हफ्ते तक चलने वाले समारोह के सिलसिले में पिछले कुछ महीनों से दुनियाभर से यहां जुटे हजारों हरिभक्त (स्वयंसेवक) खुशी और गर्व से फूले नहीं समा रहे थे. 14 फरवरी को गुजरात स्थित स्वामिनारायण संप्रदाय के आध्यात्मिक नेता महंत स्वामी ने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन समारोह का हिस्सा बने.

मंदिर का निर्माण हिंदू धर्म के वैष्णव संप्रदाय से जुड़ी बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामिनारायण संस्था यानी बीएपीएस की तरफ से कराया गया है, जिसकी स्थापना 1800 के दशक की शुरुआत में घनश्याम पांडे ने की थी. घनश्याम पांडे अयोध्या में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे एक विद्वान संन्यासी थे, जिन्होंने घूम-घूमकर अपनी आस्था का प्रचार किया. अपने प्रवचनों के जरिए उन्होंने बड़ी संख्या में अनुयायी बनाए. पांडे अपने अनुयायियों के बीच सहजानंद स्वामी और अंततः भगवान स्वामिनारायण के तौर पर जाने गए, जिन्हें उनके भक्त भगवान कृष्ण का अवतार मानते हैं. सहजानंद गुजरात जाकर बस गए और अपने जीवनकाल के दौरान दो क्षेत्र बनाए—वडताल गडी (खेड़ा) और अहमदाबाद गडी. इनसे चार और संप्रदाय उभरे—बीएपीएस, मणिनगर गडी, वसना गडी और सोखदा गडी. बीएपीएस संप्रदाय वडताल गडी से उपजा है.

बीएपीएस की स्थापना 1907 में शास्त्रीजी महाराज ने की थी. संस्था का दावा है कि दुनियाभर में उसके दस लाख से अधिक सदस्य, 80,000 स्वयंसेवक 1,550 से अधिक मंदिर और 5,025 केंद्र हैं. इसकी ओर से 17,000 साप्ताहिक आयोजन होते हैं. रॉबिंसविले (न्यू जर्सी), नई दिल्ली और गांधीनगर (गुजरात) स्थित अक्षरधाम मंदिरों के अलावा बीएपीएस के कुछ और भी ख्यात मंदिर हैं, जिसमें लंदन, ह्यूस्टन, शिकागो, अटलांटा, टोरंटो, लॉस एंजेलिस और नैरोबी स्थित मंदिर शामिल हैं. बीएपीएस के प्रवक्ता बंसल भालजा कहते हैं कि अगले मंदिर पेरिस, सिडनी और जोहान्सबर्ग में निर्मित हो रहे हैं. वहीं, बहरीन के शाह ने भी मंदिर के लिए जमीन की पेशकश की है.

बीएपीएस छह स्वामिनारायण संप्रदायों में से सबसे शक्तिशाली संप्रदाय बनकर उभरा है, जिसका मुख्य कारण इसके मजबूत सामाजिक बंधन और समुदाय में निरंतर मिल रहा समर्थन है. यह वित्तीय तौर पर मजबूत है और वैश्विक स्तर पर सत्ता के गलियारों में खासा दखल रखता है. खासकर गुजरात में दशकों से दलगत राजनीति से इतर तमाम स्थानीय नेता स्वामिनारायण संप्रदाय का आशीर्वाद पाने को लालायित रहते हैं. हालांकि बीएपीएस अराजनैतिक है, लेकिन 'उपयुक्त' उम्मीदवारों को समर्थन की इसकी प्रवृत्ति किसी से छिपी नहीं है.

इस संप्रदाय के अनुयायियों का एक बड़ा हिस्सा समृद्ध पाटीदार समुदाय है. वैसे यह सिर्फ इसी वर्ग तक सीमित नहीं है. संप्रदाय की तरफ से जारी एक बयान में इस तथ्य को रेखांकित किया गया है कि अबू धाबी

700
करोड़ रुपए
अबू धाबी के बीएपीएस मंदिर की लागत

15,000
टन
राजस्थान के गुलाबी बलुआ पत्थरों का प्रयोग मंदिर के बाहरी हिस्से में किया गया है

6,000
टन
सफेल इटैलियन मार्बल का इस्तेमाल आंतरिक सज्जा में किया गया है

30
हजार+
पत्थर के टुकड़ों को भारत के 5,000 कुशल कारीगरों ने तराशा है

में एक मुस्लिम शासक ने हिंदू मंदिर के लिए जमीन दान दी, मंदिर के मुख्य वास्तुकार एक कैथोलिक ईसाई और परियोजना प्रबंधक एक सिख हैं. नींव की डिजाइन तैयार करने का काम एक बौद्ध ने किया और निर्माण कंपनी एक पारसी समूह की थी. यही नहीं, मंदिर संचालक की जिम्मेदारी एक जैन ने संभाली है. बीएपीएस का खाड़ी देश में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर स्थापित करना इस लिहाज से भी उल्लेखनीय है कि संयुक्त अरब अमीरात में 33 लाख से अधिक प्रवासी भारतीय आबादी में बमुश्किल लगभग 100-150 परिवार ही बीएपीएस के सदस्य हैं.

रेगिस्तान के बीच मंदिर

बीएपीएस हिंदू मंदिर अबू धाबी के बाहरी इलाके अबू मरेखाह क्षेत्र में है. मंदिर के लिए 13.5 एकड़ जमीन संयुक्त अरब अमीरात के प्रेसिडेंट और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने 2019 में उपहार में दी थी. अन्य 13.5 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया. मंदिर परिसर 27 एकड़ में फैला है. कथित रूप से बीएपीएस मंदिर अनूठी पारंपरिक और अखंड वास्तुकला का 'पत्थरों से बना पहला मंदिर' है और यह रेतीले इलाके के अनुरूप बना है. इसमें मुख्य मूर्ति भगवान स्वामिनारायण की है, और परिसर में सात हिंदू देवी-देवताओं के सात अन्य मंदिर भी हैं.

मंदिर निर्माण में 700 करोड़ रुपए लगे, जो बीएपीएस भक्तों और स्वयंसेवकों ने दान और वित्तीय मदद के तौर पर मुहैया कराई थी. बंसल का दावा है, ''बीएपीएस की 50 से अधिक देशों में मौजूदगी है, जहां विभिन्न जाति-धर्म और संप्रदायों के लोगों ने मंदिर निर्माण और कई अन्य सामाजिक-आध्यात्मिक परियोजनाओं के लिए आगे आकर वित्तीय मदद दी.'' संप्रदाय का दावा है कि उसके राजस्व का सबसे बड़ा साधन बीएपीएस सदस्यों और हरिभक्तों से मिलने वाला धन है. उन्हें एक दशमांश यानी अपनी आय का पांच से 10 फीसद हिस्सा दान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. फंड जुटाना इस संप्रदाय के कभी कोई समस्या नहीं रहा. न्यू जर्सी के रॉबिंसविले स्थित अक्षरधाम मंदिर के निर्माण पर 9.6 करोड़ डॉलर का खर्च आया. इसे भी अनुयायियों से मिले दान की राशि से बनाया गया था. (देखें बीएपीएस की दुनिया)

भव्यता
रॉबिंसविले अक्षरधाम मंदिर; (नीचे) बीएपीएस मंदिर, लंदन

शटरस्टॉक

बीएपीएस की दुनिया

- 1800 के शुरुआती दशक में स्थापित और कभी वैष्णव संप्रदाय का हिस्सा रहा बीएपीएस आज 50 से अधिक देशों में फैला है. इसके विशाल नेटवर्क में दस लाख से अधिक सदस्य, 80,000 स्वयंसेवक, 1,550 से अधिक मंदिर और 5,025 केंद्र हैं

- आमतौर पर संप्रदाय का नेतृत्व गुणातीत गुरु करते हैं और भगवान स्वामिनारायण के छठे आध्यात्मिक उत्तराधिकारी महंत स्वामी महाराज (वीनू पटेल) 2016 से इसकी अगुआई कर रहे हैं. उनके पूर्ववर्ती प्रमुख स्वामी महाराज (शांतिलाल पटेल) को इस संप्रदाय में एक खास पूजनीय दर्जा हासिल रहा है. उन्होंने गुणातीत गुरु के तौर पर 45 वर्षों तक बीएपीएस का का नेतृत्व किया. इस दौरान 1,125 मंदिरों की स्थापना हुई और 1997 में अबू धाबी में मंदिर बनाने का विचार भी उन्हीं का था

- संप्रदाय की कमाई सदस्यों के अलावा स्थानीय स्तर पर समुदायों के बीच मौजूद हरिभक्तों की मदद से हासिल होने वाले चंदे से होती है. इसके सदस्यों को फाउंडेशन को अपनी आय का पांच से 10 फीसद हिस्सा दान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है

- यूएई में पांच साल में बनकर तैयार हुए मंदिर की लागत बीएपीएस सदस्यों और हरिभक्तों से मिले दान से ही वहन की गई. संप्रदाय का सबसे बड़ा ग्लोबल टेंपल रॉबिंसविले, न्यूजर्सी में है. इसका उद्घाटन अक्तूबर 2023 में हुआ और इसके निर्माण पर 9.6 करोड़ डॉलर (करीब 797 करोड़ रुपए) खर्च हुए

शटरस्टॉक

प्रधानमंत्री मोदी पहले भी बीएपीएस के कई आयोजनों में हिस्सा ले चुके हैं. लेकिन वे एकमात्र ऐसे नेता नहीं हैं जो संप्रदाय के साथ नजदीकी बढ़ाना उचित समझते हैं. 2005 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति दिवंगत ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर के उद्घाटन में शामिल हुए थे. 2007 में तत्कालीन कनाडाई प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने टोरंटो में बीएपीएस मंदिर का उद्घाटन किया था. प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी कई बार बीएपीएस मंदिरों का दौरा कर चुके हैं. किंग चार्ल्स और उनकी पत्नी कैमिला लंदन स्थित नेसडेन स्वामिनारायण मंदिर में कई बार जा चुके हैं. वहीं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी पत्नी 2023 में अपनी राजकीय यात्रा के दौरान भारत में केवल एक मंदिर गए थे और वह दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर था.

विवाद भी जुड़े

बीएपीएस ने अच्छा-खासा प्रभुत्व स्थापित कर रखा है. लेकिन वह गाहे-बगाहे विवादों के कारण भी सुर्खियों में रहा. सितंबर 2002 में आतंकवादियों ने कथित तौर पर गोधरा

कांड के बाद दंगों का बदला लेने के लिए गांधीनगर स्थित अक्षरधाम मंदिर पर हमला बोल दिया. उसमें 33 लोग मारे गए, पर 2014 में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया.

हिंदू समुदाय का एक वर्ग स्वामिनारायण भगवान को हिंदू देवताओं के बराबर रखने के प्रयास का विरोध करता है. 1948 में दलितों को अपने मंदिरों में प्रवेश से रोकने के कथित प्रयास पर स्वामिनारायण संप्रदाय का कहना था कि उनका परिसर बॉम्बे हरिजन मंदिर प्रवेश अधिनियम, 1947 और फिर बाद में बने बॉम्बे हिंदू स्थान सार्वजनिक पूजा (प्रवेश प्राधिकरण) अधिनियम 1956 के दायरे में नहीं आता क्योंकि वे हिंदू धर्म से जुड़े नहीं हैं.

हालिया विवाद सितंबर 2023 का है, जब गुजरात के बोटाद के सालंगपुर गांव में कष्टभंजनदेव हनुमान मंदिर परिसर में स्वामिनारायण के चरणों में बैठे हनुमान का एक भित्तिचित्र दिखा. उस चित्र पर रंग पोत दिया गया और शारदापीठ द्वारका के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज सहित कई समुदायों के साथ मिलकर विश्व हिंदू परिषद ने स्वामिनारायण संप्रदाय पर प्रतिबंध लगाने के लिए आंदोलन छेड़ दिया. बाद में संप्रदाय ने आपत्तिजनक भित्ति चित्र को हटा लिया. बंसल दावा करते हैं कि यह अब बीती बात हो चुकी है और वैसे भी सालंगपुर मंदिर बीएपीएस मंदिर नहीं था.

इससे अधिक गंभीर मामला 2021 का है, जब रॉबिंसविले मंदिर के कुछ श्रमिकों ने न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान को लेकर अमेरिका में बीएपीएस के खिलाफ मुकदमा ठोक दिया. संस्था पर आव्रजन और श्रम कानूनों के उल्लंघन का भी आरोप लगा. एफबीआइ ने मंदिर का दौरा किया और वहां कार्यरत 134 कारीगरों में से 110 को सुरक्षात्मक हिरासत में ले लिया. वहीं, बंसल ने 12 श्रमिकों (जुलाई 2023 में) के उस एक बयान का हवाला देने में देर नहीं लगाई, जिसमें कहा गया था कि उन्हें पैसे और अमेरिकी नागरिकता के बदले ये आरोप लगाने के लिए मजबूर किया गया था.

बहरहाल, बीएपीएस को शायद यह उम्मीद होगी कि अरब देश में सबसे बड़े मंदिर के निर्माण से सनातन धर्म के वैश्विक चेहरे के तौर पर उभरने के उसके प्रयासों को मजबूती मिलेगी. लगता है कि संप्रदाय को प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन प्राप्त है, पर यह देखना अभी बाकी है कि वहां का विशाल हिंदू समुदाय इस भव्य मंदिर को अपनाता है या नहीं. ■

नया दांव जयंत चौधरी (हरे कुर्ते में) अपने समर्थकों के साथ

मनीष अग्निहोत्री

खास रपट

रालोद-भाजपा गठबंधन

कमल को कितना सींच पाएगा हैंडपंप

जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के एनडीए में शामिल होने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदला राजनैतिक परिदृश्य. किसानों और जाटों को साधने में महत्वपूर्ण होगी दोनों दलों की दोस्ती

आशीष मिश्र

ष्ट्रीय लोकदल (रालोद) के संस्थापक अजित सिंह का जन्मदिन मनाने के लिए कार्यकर्ता नई दिल्ली के शाहजहां रोड स्थित पार्टी के कार्यालय में जुटने लगे थे. कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी अपने पिता के जन्मदिवस पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में शामिल होने की आधिकारिक घोषणा कर सकते हैं. ये अटकलें तब शुरू हुईं जब 9 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए चौधरी ने 'एक्स' पर पोस्ट किया था: ''दिल जीत लिया.'' जब उनसे पूछा गया कि क्या वे भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं तो उन्होंने कहा था, ''आज मैं किस मुंह से इनकार करूं.'' जैसी उम्मीद थी, चौधरी ने वैसा ही किया. अपने पिता और पार्टी संस्थापक अजित सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देने के बाद चौधरी ने रालोद के एनडीए में शामिल होने की घोषणा कर दी. चौधरी ने कहा, ''मैंने अपने सारे विधायकों से बात कर ली है. हमें अल्प समय में यह फैसला लेना पड़ा क्योंकि परिस्थितियां ऐसी थीं. हमारे सभी विधायक और कार्यकर्ता इस फैसले में हमारे साथ हैं.'' रालोद के शामिल होने से यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए का कुनबा बीते एक दशक के भीतर रिकॉर्ड बढ़ चुका है.

इससे पहले पिछले वर्ष दिसंबर में अपने जन्मदिन पर चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जिस तरह से तारीफों के पुल बांधे, उसने भी इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टी रालोद के बदले रुख की ओर संकेत कर दिया था. हुआ यह था कि उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,244 सिपाहियों की भर्ती निकली. इस भर्ती के लिए युवक निर्धारित उम्र सीमा में तीन साल छूट की मांग कर रहे थे. चौधरी की पार्टी रालोद भी युवाओं की मांग के समर्थन में थी. चौधरी ने भी सोशल मीडिया पर अपनी इस मांग को उठाया था. मुख्यमंत्री ने 26 दिसंबर को युवाओं की मांग मानते हुए सिपाही भर्ती के लिए निर्धारित उम्र सीमा में तीन साल की

छूट देने का ऐलान कर दिया. इस फैसले के तुरंत बाद चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''कल मेरा जन्मदिवस है और इससे अच्छा तोहफा नहीं मिल सकता! उत्तर प्रदेश में 60,244 सिपाही भर्ती में तीन साल की आयु सीमा बढ़ेगी! योगी जी ने उचित निर्णय लिया है.''

यूपी में विपक्षी इंडिया गठबंधन के भीतर समाजवादी पार्टी (सपा) के साथ मजबूती से खड़े चौधरी के रुख में आए इस बदलाव के पीछे लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को जिम्मेदार माना जा रहा है. चौधरी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के सीट बंटवारे के फॉर्मूले से नाराज थे. सपा ने रालोद को इंडिया गठबंधन में सात सीटें देने की घोषणा की थी. हालांकि इन सीटों की घोषणा तो नहीं हुई थी लेकिन यह माना जा रहा था कि इनमें बागपत, कैराना, नगीना, बिजनौर, मेरठ या अमरोहा, हाथरस और मथुरा लोकसभा सीटें शामिल थीं. सपा की ओर से कुछ शर्तें लगा देने से गठबंधन में दरार आना शुरू हुई. सपा ने कैराना, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में प्रत्याशी अपना और निशान रालोद का रहने की शर्त रखी थी. सपा का 'प्रत्याशी हमारा, सिम्बल तुम्हारा' दांव चौधरी की नाराजगी की बड़ी वजह बना. जाट नेता को यह डील मंजूर नहीं थी. यहीं से हैंडपंप (रालोद का चुनाव चिह्न) और साइकिल की राह अलग हो गई. हालांकि सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी कहते हैं, ''गठबंधन में सीटें तो दोनों दलों की सहमति से तय हुई थीं. अगर कोई असहमति थी तो जयंत चौधरी को बताना चाहिए था. जहां तक सपा उम्मीदवारों को रालोद के टिकट पर चुनाव लड़ाने का आरोप है तो चुनाव चिह्न तो उन्हीं के हस्ताक्षर से मिलने थे तो उम्मीदवार सपा का कैसे हो सकता है. यह आरोप बेबुनियाद है.''

दरअसल, जाटों और किसानों में पैठ रखने वाले रालोद के एनडीए में शामिल होने के निर्णय ने पश्चिमी यूपी का पूरा राजनैतिक परिदृश्य बदल दिया है. 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले किसान आंदोलन की तपिश झेल रही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जाट वोटों को लेकर मुतमइन थी. लेकिन जब मार्च में नतीजे आए तो पता चला कि पश्चिमी यूपी में भाजपा समर्थक वोट बैंक के दरकने की शुरुआत हो चुकी है. 2022 के विधानसभा चुनाव में पहली बार 17 जाट विधायक चुने गए. इनमें 10 भाजपा और सात सपा-रालोद के थे जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में कुल 14 जाट विधायक चुने गए थे और इनमें 13 भाजपा और एक रालोद का था. इस प्रकार विधानसभा में जाट विधायकों की संख्या बढ़ी लेकिन भाजपा की हिस्सेदारी घट गई. इसके बाद भाजपा संगठन डैमेज कंट्रोल में जुटा. विधानसभा चुनाव के करीब छह महीने के बाद 25 अगस्त, 2022 को पिछले 31 साल से संगठन और सरकार में किसी न किसी प्रकार की भूमिका में रहने वाले भूपेंद्र चौधरी को उत्तर प्रदेश भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया. यह पहली बार था जब भाजपा ने यूपी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी किसी जाट नेता को सौंपी थी. लक्ष्य साफ था कि पश्चिमी यूपी में दरकते जाट वोट बैंक

रालोद को भाता है गठबंधन

- रालोद की स्थापना 1996 में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे अजित सिंह ने जनता दल से अलग हुए गुट के रूप में की थी
- रालोद अपने 27 साल के राजनैतिक सफर में भाजपा से लेकर कांग्रेस, सपा सहित सभी प्रमुख दलों से 10 बार हाथ मिला चुका है
- अजित सिंह ने 1996 में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में बागपत लोकसभा सीट से चुनाव जीता लेकिन बाद में इस्तीफा दे दिया
- वर्ष 1999 के लोकसभा चुनाव में रालोद ने भाजपा से गठबंधन कर चुनाव लड़ा. दो सीटें जीतीं. अजित सिंह बागपत से चुनाव जीतकर सांसद बने
- वर्ष 2002 के विधानसभा चुनाव में रालोद ने भाजपा से गठबंधन किया. रालोद के 14 विधायक जीते, जो अब तक का रालोद का सर्वोत्तम प्रदर्शन है
- वर्ष 2003 में मुलायम सिंह यादव की सरकार बनने के बाद रालोद ने सपा से गठबंधन कर लिया. पार्टी के छह विधायक मंत्री बने
- रालोद ने 2004 का लोकसभा चुनाव सपा के साथ गठबंधन करके लड़ा. पार्टी के तीन सांसद जीते. 2007 के विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन बिखर गया
- वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव में रालोद ने उत्तर प्रदेश की 254 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे. पार्टी ने 1.95 प्रतिशत वोट पाए और उसके 10 विधायक विजयी रहे
- वर्ष 2009 का लोकसभा चुनाव रालोद ने भाजपा से गठबंधन करके कुल सात सीटों पर लड़ा. लोकसभा चुनाव में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए रालोद के पांच सांसद जीते
- वर्ष 2011 में रालोद केंद्र में सत्तारूढ़ यूपीए में शामिल हो गया. अजित सिंह केंद्र सरकार में मंत्री बने. कांग्रेस से मिलकर 2012 का विधानसभा चुनाव लड़ा और नौ सीटें जीतीं
- वर्ष 2014 का लोकसभा चुनाव रालोद ने यूपीए के सहयोगी के तौर पर ही कुल आठ सीटों पर लड़ा लेकिन एक भी जीतने में कामयाबी न मिली
- वर्ष 2017 का विधानसभा चुनाव रालोद ने अकेले 171 सीटों पर लड़ा लेकिन केवल एक ही सीट जीतने में कामयाबी मिली
- वर्ष 2019 का लोकसभा चुनाव रालोद ने सपा और बसपा के साथ मिलकर तीन सीटों पर लड़ा लेकिन इस बार भी चुनाव में खाता नहीं खुला
- वर्ष 2022 का विधानसभा चुनाव रालोद ने सपा के साथ गठबंधन करके 33 सीटों पर लड़ा. रालोद को आठ सीटें जीतने में कामयाबी मिली

को मजबूती के साथ खड़ा करना. जाट प्रदेश अध्यक्ष बनाकर इस वोट बैंक पर पकड़ मजबूत करने की भगवा रणनीति का पहला इम्तिहान दिसंबर, 2022 में मुजफ्फरनगर जिले की जाट बहुल खतौली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में लिया गया. रालोद-सपा और आजाद समाज पार्टी (आसपा) के संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर मदन भैया ने भाजपा उम्मीदवार राजकुमारी सैनी को 22 हजार से अधिक वोटों से हराया.

हालांकि भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में भाजपा ने रामपुर सदर विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल कर इतिहास रचा लेकिन जाट बहुल सीट पर मिली हार ने भगवा खेमे की जाट राजनीति पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था. इसके बाद से ही भाजपा नेताओं के बीच रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी से गठबंधन करने की मांग जोर पकड़ने लगी. विधानसभा में वर्तमान में रालोद के भले ही नौ विधायक हों और एक भी लोकसभा सांसद न हो लेकिन पश्चिमी यूपी के 26 जिलों में फैले जाट मतदाताओं पर इस पार्टी का खासा प्रभाव है. इनमें 27 लोकसभा सीटें आती हैं.

उत्तर प्रदेश की कुल पिछड़ी जातियों में जाटों का प्रतिशत 3.60 है लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की छह कमिशनरी में ये 18 से 20 फीसद तक हैं. 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का एकतरफा समर्थन करने वाले जाट मतदाताओं के एक बड़े वर्ग ने 2019 के चुनाव में सपा-बसपा-रालोद गठबंधन को वोट दिया था. इससे बने जाट-मुस्लिम समीकरण से पश्चिमी यूपी में पांच मुस्लिम सांसद जीते थे. खतौली विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने संकेत दिया था कि पश्चिमी यूपी में दोबारा जाट-मुस्लिम समीकरण अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है. मई 2023 में हुए नगरीय निकाय चुनाव में भारी भरकम जीत के बावजूद भाजपा को जाट बहुल सीटों पर मिली हार काफी खटकी. मुजफ्फरनगर में तो 2017 के नगरीय निकाय चुनाव के मुकाबले इस बार भगवा खेमे का जनाधार और घट गया. 2017 के चुनाव में बुरी तरह खेत रहे रालोद ने खतौली और जानसठ नगरपालिका परिषद पर कब्जा जमाकर अपनी बढ़ती ताकत का एहसास कराया. इस प्रकार मुजफ्फरनगर में नगरपालिका परिषद की सीट छोड़ दें तो यहां भाजपा असरदार साबित नहीं हुई. इसी तरह जाट मतदाताओं का मिजाज बताने वाली बड़ौत, मुरादनगर, हापुड़, अनूपशहर, चंदौसी, गजरौला, अतरौली, खैर, इगलास समेत कई नगरपालिका परिषद में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा. विधानसभा उपचुनाव हारने के बाद खतौली नगर पालिकापरिषद के चुनाव में भाजपा को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी. यहां रालोद-सपा-आसपा के गठबंधन के आगे भाजपा उम्मीदवार तीसरे नंबर पर पहुंच गया. यहीं से 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चलने वाली भाजपा को रालोद की जरूरत काफी शिद्दत से महसूस होने लगी.

“जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने से पश्चिमी यूपी में भाजपा और एनडीए दोनों को फायदा होगा. पिछले दो लोकसभा चुनाव में रालोद का सूखा दूर हो सकता है तो भाजपा भी पश्चिमी यूपी की हारी सीटें दोबारा जीत सकेगी”

—मनोज सिवाच,
प्रोफेसर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

पिछले वर्ष मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने, आयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से बने माहौल और नीतीश कुमार के एनडीए में वापस आने के बाद रालोद को लेकर अटकलें शुरू हो गई थीं. भाजपा के वरिष्ठ नेता यह दावा करते हैं कि लोकसभा चुनाव में रालोद का सबसे अच्छा प्रदर्शन भाजपा के साथ ही दिखाई दिया है.

राजनैतिक विश्लेषक अब रालोद के एनडीए कुनबे में शामिल होने से पश्चिमी यूपी में जाट मतदाताओं के एकजुट होने की उम्मीद लगा रहे हैं. मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग में प्रोफेसर डॉ. मनोज सिवाच बताते हैं, ''रालोद के एनडीए में शामिल होने के बाद से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में न केवल जाट मतदाता भाजपा-रालोद के पक्ष में एकजुट होगा बल्कि कुछ इलाकों में बना जाट-मुस्लिम गठजोड़ भी बिखर जाएगा. इसका फायदा एनडीए को लोकसभा चुनाव में मिलेगा.''

एनडीए के पक्ष में जाट मतदाताओं का एकमुश्त समर्थन सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, मुरादाबाद जैसी लोकसभा सीटों पर बड़ा असर दिखाएगा, जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हार का समाना करना पड़ा था. एनडीए गठबंधन के सहयोगी के तौर पर भाजपा रालोद को तीन सीटें देने को राजी हो सकती है. इनमें मुजफ्फरनगर या बागपत में से एक का होना तय है, जिन पर पिछले लोकसभा चुनाव में क्रमशः अजित सिंह और चौधरी को हार का सामना करना पड़ा था. चौधरी का भाजपा से गठबंधन का दांव दादा चौधरी चरण सिंह और पिता अजित सिंह की राजनैतिक विरासत लेने में अहम होगा. इस परिस्थिति में बागपत सीट रालोद के लिए सबसे सुरक्षित मानी जा रही है. बागपत लोकसभा सीट पर 1977 में चौधरी चरण सिंह पहली बार जीते थे. पिछले दो लोकसभा चुनावों से बागपत लोकसभा सीट पर भाजपा का कब्जा है.

भाजपा से गठबंधन करके अपने पिता और दादा की कर्मभूमि पर जयंत एक बार फिर हैंडपंप गाड़ सकते हैं. पंजाब, हरियाणा में दोबारा खड़े होते किसान आंदोलन की तपिश को हल्का करने में भी रालोद, भाजपा का मददगार हो सकता है. रालोद के राष्ट्रीय सचिव अनुपम मिश्र बताते हैं, ''अब केंद्र और राज्य सरकार से किसानों के मुद्दों को उठाकर उनका सम्मानपूर्वक समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा.'' भाजपा-रालोद दोस्ती से गन्ने की मिठास बढ़ने की उम्मीद भी लगाई जा रही है. रालोद लंबे समय से किसानों को गन्ने का उचित मूल्य देने की मांग करता रहा है. प्रदेश सरकार गन्ने की एमएसपी से इतर बोनस के रूप में प्रति कुंतल 10 रुपए देने की घोषणा कर किसानों को और राहत दे सकती है.

भाजपा-रालोद की दोस्ती के सामने चुनौतियां भी हैं. दोनों दलों के जमीनी नेताओं के लिए आपस में सामंजस्य बिठाना आसान नहीं होगा क्योंकि अभी तक वे एक-दूसरे के राजनैतिक प्रतिद्वंद्वी रहे हैं. लेकिन इस गठबंधन की कामयाबी दोनों दलों के जमीनी कार्यकर्ताओं के लचीले रवैए से ही तय होगी. ■

विकसित भारत @2047 के लिए भारत का विज़न

आत्मनिर्भर और विकसित भारत का संकल्प

भारत सरकार ने पिछले एक दशक के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ने के मकसद से विभिन्न योजनाई शुरू की हैं. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, बुनियादी ढांचे के विकास, रोजगार सृजन और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर बहुआयामी दृष्टिकोण के साथ भारत ने पूरा ध्यान आत्मनिर्भरता हासिल करने के अपने संकल्प पर केंद्रित कर दिया है, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में इन सभी क्षेत्रों में भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक सफलता भी हासिल की है. देश का डिजिटल और भौतिक बुनियादी ढांचा नई ऊंचाइयां छू रहा है. सभी क्षेत्रों में भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है और अभूतपूर्व आर्थिक सफलता के लिए उसे सराहा भी जा रहा है.

सरकार की नीतियों के प्रति निवेशकों का भरोसा बढ़ने से भारत की क्षमताओं और सफलता को लेकर लोगों के नजरिए में सकारात्मक बदलाव आया है. आत्मनिर्भर भारत के सिद्धांत पर चल रही सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तनकारी पहल की हैं, और इनके जरिये देश को आर्थिक समृद्धि, सामाजिक सशक्तिकरण और पर्यावरण अनुकूल सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ा रही है. उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना इस बदलाव का सशक्त उदाहरण है, वहीं बुनियादी ढांचागत प्रगति और कल्याण से जुडी कई योजनाएं भी हैं, जिनका उद्देश्य स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देना, प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना और जोखिमों के प्रति कंपनियों को सुदृढ़ करना है. मोदी सरकार ने स्थिरता, सामंजस्यता और निरंतरता के आधार पर वित्तीय प्रबंधन और नीति-निर्माण के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता दिखाई है. इसी सिद्धांत को अपनाते हुए रिकॉर्ड उत्पादक व्यय, कल्याणकारी योजनाओं में निवेश, फिजूल खर्ची पर नियंत्रण और वित्तीय अनुशासन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हालिया केंद्रीय बजट को खासी सराहना मिली है. सरकार ने परियोजनाएं समय पर पूरी करके संसाधनों का सीमित इस्तेमाल किया जाना भी सुनिश्चित किया है.

डिजिटल क्रांति: प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाने की कवायद

डिजिटल क्रांति आत्मनिर्भरता की दिशा में निरंतर आगे बढ़ते भारत के लिए मील के एक पत्थर की तरह है. यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस एक बड़ी पहल है, जो देशभर में डिजिटल लेन-देन में एक गेम-चेंजर बनकर उभरी है. पिछले वर्ष रिकॉर्ड-तोड़ 100 अरब ट्रांजैक्शन और करीब दो लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि के लेन-देन के साथ यूपीआई ने भुगतान के तरीके में नई क्रांति ला दी. यहां तक, सबसे दूरदराज के गांव भी अब इसमें पीछे नहीं हैं. जैम त्रयी (बैंक खाता, आधार और मोबाइल फोन) से मिलकर बने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचाया है. इसके तहत 34 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंची है. इससे न सिर्फ पारदर्शिता आई और भ्रष्टाचार घटा, बल्कि समावेशिता को बढ़ावा मिला और इन सबसे बढ़कर सरकार के प्रति जनता का भरोसा भी बढ़ा. कोविड-19 महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में भारत ने सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटों से निपटने के लिए तकनीक का सहारा लेते हुए कोविन प्लेटफॉर्म के जरिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया. इसके अलावा, सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं में किसी भी तरह की धांधलेबाजी से बचने के लिए तकनीक का सहारा लेने पर जोर दिया, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में दक्षता और पारदर्शिता आई और युवाओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित हुए.

बुनियादी ढांचा विकास: आत्मनिर्भर भारत का एक प्रमुख स्तंभ

बुनियादी ढांचे पर मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी एजेंडे ने आत्मनिर्भर भारत की नींव रखी. रेलवे लाइनों के विद्युतीकरण को दोगुना करने से लेकर चार-लेन राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क विस्तार तक, देश ने कनेक्टिविटी और गतिशीलता बढ़ने में अभूतपूर्व प्रगति देखी. पिछले दशक में भारत ने बुनियादी ढांचे के विकास में शानदार काम किया, भारतमाला, सागरमाला, पीएम गति शक्ति, उड़ान, स्मार्ट सिटी मिशन आदि जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं इसी का हिस्सा हैं. इन पहलों ने न सिर्फ कनेक्टिविटी और दक्षता को बढ़ावा दिया बल्कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सतत विकास की आधारशिला भी रखी. भारतमाला और सागरमाला परियोजनाएं सड़क और बंदरगाह कनेक्टिविटी को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई हैं. वहीं स्मार्ट सिटी मिशन एक अन्य महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य तकनीक और नवाचार को अपनाकर शहरी क्षेत्रों को टिकाऊ और रहने योग्य जगहों में तब्दील करना है. बुनियादी ढांचा आर्थिक वृद्धि और
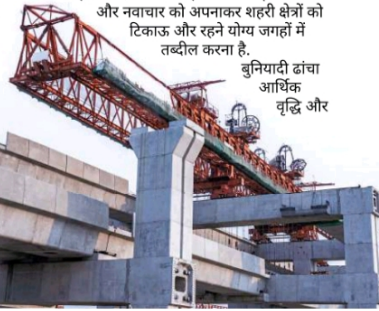
औद्योगिक विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है और हालिया बजट में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 11 लाख करोड़ रुपये का आवंटन दर्शाता है कि सरकार इस पर कितना ध्यान दे रही है. ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और बोगीबील ब्रिज जैसी बड़ी परियोजनाएं बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, रोजगार के अवसर बढ़ाने और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के भारत के दृढ़ संकल्प को रेखांकित करती हैं. खासकर, रेलवे क्षेत्र विद्युतीकरण, रेल लाइनों के दोहरीकरण और यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाओं की शुरुआत में व्यापक निवेश के साथ बड़े पैमाने पर बदलाव की मिसाल बना है. वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी परियोजना शुरू होना रेलवे के आधुनिकीकरण और उन्नयन को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता का नमूना है, जिससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे.

भारत सरकार की बुनियादी ढांचा विकास पहलों का उद्योगों और विभिन्न क्षेत्रों पर गहरा असर पड़ा है. इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है और प्रतिस्पर्धात्मकता भी बढ़ी है. चार-लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार और रेलवे लाइनों के विद्युतीकरण से परिवहन नेटवर्क में व्यापक सुधार हुआ, इससे रसद लागत घटने के साथ वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही संभव हुई. यह विनिर्माण, कृषि और लॉजिस्टिक्स जैसे उद्योगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद रहा, क्योंकि इन क्षेत्रों का संचालन काफी हद तक कुशल बुनियादी ढांचे पर निर्भर करता है. निजी क्षेत्र ने उत्पादकता बढ़ने, लागत घटने और बाजार विस्तार की संभावनाओं के मद्देनजर बुनियादी ढांचे में इस प्रगति को काफी सराहा है. कनेक्टिविटी बढ़ने से कच्चे माल, बाजार और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तक पहुंच बढ़ी है. इससे व्यवसायों को अपना कामकाज बढ़ाने और नए ग्राहकों तक पहुंचने की सुविधा मिल रही है. वहीं, सागरमाला पहल के जरिये बंदरगाहों के आधुनिकीकरण से समुद्री व्यापार और लॉजिस्टिक आपूर्ति में वृद्धि हुई है. व्यापार बढ़ने के साथ ही निर्यात में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी है.

ग्रामीण भारत सशक्तिकरण: बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता और गरीबी उन्मूलन

आत्मनिर्भर भारत का लाभ ग्रामीण भारत के दूरदराज के इलाकों तक नजर आ रहा है, जहां बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता लोगों का जीवन आसान बना रही है. उजाला योजना जैसी पहल के अलावा 10 करोड़ ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुंचने से जीवन की गुणवत्ता तो सुधरी ही है, सामुदायिक स्तर पर आर्थिक सशक्तिकरण भी हुआ. प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण तंत्र ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया और अरबों रुपये बचाए. गरीबी उन्मूलन के प्रयासों ने पिछले एक दशक में करीब 25 करोड़ लोगों को आर्थिक बदहाली से बाहर निकाला. ऐसी तमाम पहल समावेशी विकास के प्रति सरकार की वचनबद्धता दर्शाती हैं और सुनिश्चित करती हैं कि विकास का लाभ समाज के हर तबके तक पहुंचे. आम नागरिकों का जीवन बेहतर बनाने के उद्देश्य से बनाई गई योजनाओं के साथ मोदी सरकार का खास जोर गरीबी उन्मूलन और सामाजिक कल्याण पर है. जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली योजनाएं नागरिकों का धन और ऊर्जा बचाती हैं और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच भी बढ़ाती हैं. वित्तीय प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता मौजूदा और भावी पीढ़ियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करती है. इसी तरह, रूफटॉप सोलर योजना और एलईडी बल्ब वितरण जैसी पहलों ने न केवल घरों के लिए बिजली का बिल घटाया है बल्कि पर्यावरण सततता में भी योगदान दे रही हैं. उज्ज्वला और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के जरिये गरीबों और मध्यम वर्ग का व्यय घटाने पर सरकार का फोकस होना समावेशी विकास और कल्याण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता रेखांकित करता है.

ऊर्जा सुरक्षा और सततता: पर्यावरण अनुकूल बदलाव

ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास की अनिवार्यता आत्मनिर्भर भारत के मूल में समाहित है. नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों पर मोदी सरकार के फोकस ने भारत को पर्यावरण अनुकूल विकास के मामले में एक वैश्विक नेता के तौर पर स्थापित किया है. पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण ने उत्सर्जन घटाया और खासी लागत भी बचाई. 2025 तक 20 फीसद इथेनॉल मिश्रण का महत्वाकांक्षी लक्ष्य ऊर्जा क्षेत्र में निर्भरता कम करने के एक नए युग की शुरुआत साबित होगा. सौर ऊर्जा, बायोगैस संयंत्र और ग्रीन हाइड्रोजन पहल में व्यापक निवेश पर्यावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों को लेकर भारत के संकल्प को रेखांकित करता है. स्वदेशी संसाधनों के इस्तेमाल के साथ स्वच्छ ऊर्जा उपायों को अपनाकर भारत न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरा कर रहा है बल्कि वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य को भी बदल रहा है. रूफटॉप सोलर योजना और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को प्रोत्साहन की बदौलत स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को अपनाने में काफी तेजी आई है, जो पर्यावरणीय क्षति घटाने के लिहाज से काफी अहम है.

डीकार्बोनाइजेशन और नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ने उद्योग हितधारकों और पर्यावरण हितैषियों दोनों की सराहना हासिल की है. सौर ऊर्जा क्षमता के तेजी से विस्तार से न केवल कार्बन उत्सर्जन में कमी आई, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में नवाचार और निवेश को भी बढ़ावा मिला. विनिर्माण, निर्माण और यूटिलिटी समेत विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े उद्योग नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों को अपने कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने, ऑपरेशनल जोखिमों को घटाने और साथ ही पर्यावरण संरक्षण को लेकर अपनी साख बढ़ाने के साधन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं. भारत के नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने की राह में तेजी से बढ़ते कदमों में निजी क्षेत्र का खासा योगदान है, जो सौर, पवन और अन्य स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं में भारी-भरकम निवेश कर रहा है. कंपनियां नवीकरणीय ऊर्जा से होनी वाली लागत बचत, ऊर्जा सुरक्षा और ब्रांड की साख पर पड़ने वाले सकारात्मक असर के फायदों को अच्छी तरह समझती हैं.

पीएलआई योजना: विनिर्माण और निवेश को मजबूती

उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं देश की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को

बढ़ाकर 'आत्मनिर्भर भारत' का लक्ष्य साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण स्तंभ की तरह हैं. 1.97 लाख करोड़ रुपये (करीब 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के महत्वाकांक्षी परिव्यय के साथ ये योजनाएं भारत के औद्योगिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले 14 प्रमुख क्षेत्रों को लक्षित करती हैं. इन 14 क्षेत्रों में मोबाइल विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे विविध उद्योग शामिल हैं. हर क्षेत्र ही भारत के आर्थिक परिदृश्य के लिहाज से खास अहमियत रखता है, और पीएलआई योजनाओं का उद्देश्य निवेश और नई प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि विनिर्माण दक्षता के साथ बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सके. पीएलआई योजना के प्राथमिक उद्देश्यों में विविधता है. पहला, नवाचार और तकनीकी उन्नयन के साथ रणनीतिक क्षेत्रों में घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित करना. दूसरा, आधारभूत और सहायक उद्योगों के निर्माण को बढ़ावा देकर मजबूत सप्लाई चेन विकसित करना और भारतीय निर्माताओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा की स्थिति में लाना. पीएलआई योजनाओं के तहत चुने गए 733 आवेदनों में से 176 एमएसएमई लाभार्थी बने हैं, जिनमें फार्मास्यूटिकल, दूरसंचार, खाद्य प्रसंस्करण और कपड़ा जैसे क्षेत्र शामिल हैं. वहीं, नवीकरणीय ऊर्जा विनिर्माण को लेकर उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजनाओं पर सरकार की सक्रियता ने निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया है.

वैश्विक स्तर पर भारत का बढ़ता कद: दुनियाभर में जमाई धाक

आत्मनिर्भरता और घरेलू मोर्चे पर विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ता भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय मंचों और पहलों में सक्रिय भागीदारी के जरिये दुनियाभर में अपनी धाक जमा रहा है. जी-20 शिखर सम्मेलन जैसे अहम आयोजन ने भारत को वैश्विक आर्थिक व्यवस्था पर अपनी छाप छोड़ने और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुखर आवाज बनने का मंच मुहैया कराया. वहीं, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जैसी पहलों ने न केवल दुनिया को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से रू-ब-रू कराया बल्कि दुनियाभर को सेहत और एकता का संदेश भी दिया. अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) का हिस्सा होना दर्शाता है कि भारत जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने और नवीकरणीय ऊर्जा पहल के मामले में वैश्विक स्तर पर अगुआ की भूमिका निभाने के लिए तैयार है. अपनी सॉफ्ट पॉवर का इस्तेमाल करके और दुनियाभर को असहज करने वाले मसलों में सक्रियता दिखाकर भारत विश्व मंच पर एक प्रमुख खिलाड़ी के तौर पर उभरा है, जो वैश्विक एजेंडे को आकार देने और देशों के बीच सहयोग बढ़ाने में योगदान दे रहा है. रणनीतिक कूटनीति और सक्रिय भागीदारी के जरिये भारत 21वीं सदी में एक नेता के तौर पर अपनी स्थिति मजबूत करते हुए वैश्विक कद बढ़ा रहा है.

प्रत्येक नागरिक का सशक्तिकरण: विकसित भारत के मजबूत स्तंभ

सरकार का विकसित भारत का विचार युवाओं, किसानों, महिलाओं और वंचितों पर विशेष ध्यान देने के साथ प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाने के इर्द-गिर्द केंद्रित है. मुद्रा योजना और रेहड़ी-पटरी वालों के लिए वित्तीय सहायता जैसी योजनाओं ने हर तरह की पृष्ठभूमि वाले लोगों के लिए उद्यमशीलता के रास्ते खोले. तीन करोड़ लखपति दीदी बनाने की हालिया घोषणा गरीब परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाती है. आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आयुष्मान योजना के तहत लाना समाज के सभी वर्गों तक स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच सुनिश्चित करने के सरकार के प्रयासों को जाहिर करता है. वित्तीय प्रबंधन और राजकोषीय अनुशासन के जरिये सरकार यह कोशिश कर रही है कि संसाधनों का बेवजह इस्तेमाल न हो, ताकि इन्हें भावी पीढ़ियों के लिए सहेजकर रखा जा सके.

भविष्य पर नजर: विकसित भारत का विचार

पिछला एक दशक भारत के लिए परिवर्तनकारी रहा है, जिसमें आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन, आर्थिक विकास को गति और नागरिकों के जीवन की बेहतरी के उद्देश्य से कई पहल की गईं. भारत के आत्मनिर्भरता और प्रगति की राह पर निरंतर आगे बढ़ते रहने के बीच सरकार भी विकास और समृद्धि की लेकर अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है. उद्योग जगत के नेताओं और उद्यमियों ने आर्थिक विकास और लचीलापन बढ़ाने में घरेलू विनिर्माण, नवाचार और उद्यमिता के महत्व को समझते हुए आत्मनिर्भर भारत के सुर में सुर मिलाया है. अनुसंधान एवं विकास, कौशल विकास और नई प्रौद्योगिकी में निवेश के जरिये कारोबार जगत भारत को नवाचार और उद्यमिता का एक वैश्विक केंद्र बनाने में अहम योगदान दे रहा है. प्रधानमंत्री का 'मोदी की गारंटी' वाला आश्वासन भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के उनके अटूट संकल्प को दर्शाता है. गरीबी उन्मूलन, नवाचार को प्रोत्साहन और विकास को गति पर ध्यान केंद्रित करने के साथ सरकार भावी पीढ़ियों के लिए उज्जवल भविष्य की नींव रख रही है. अब जब, पूरे देश ने अपना ध्यान 2047 तक विकसित भारत के विचार पर केंद्रित कर रखा है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रगति और विकास के सरकार के अटूट संकल्प के साथ एक समृद्ध और आत्मनिर्भर राष्ट्र का मार्ग अवश्य प्रशस्त होगा. मोदी सरकार का शासन मॉडल दोहरे स्तर पर काम करता है—20वीं सदी की चुनौतियों से निपटने के साथ 21वीं सदी की आकांक्षाओं को पूरा करना. सरकार ने अंतरिक्ष अन्वेषण, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और परिवहन आदि क्षेत्रों में तमाम पहल की हैं. नवाचार को प्रोत्साहन और नए अवसरों के उत्पन्न होने के साथ भारत प्रगति और समृद्धि की नई ऊंचाइयां छूने को तैयार है.

विघटन, विकास और विविधीकरण पर ध्यान देने के साथ भारत एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के तौर पर उभरने के लिहाज से अच्छी स्थिति में है. जैसे-जैसे राष्ट्र प्रगति के पथ पर नए आयाम तय कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी का 'न्यू इंडिया' का विचार भी तीव्र गति के साथ विस्तारित होकर सभी नागरिकों के लिए उज्ज्वल और समृद्ध भविष्य की गारंटी को मजबूत कर रहा है.
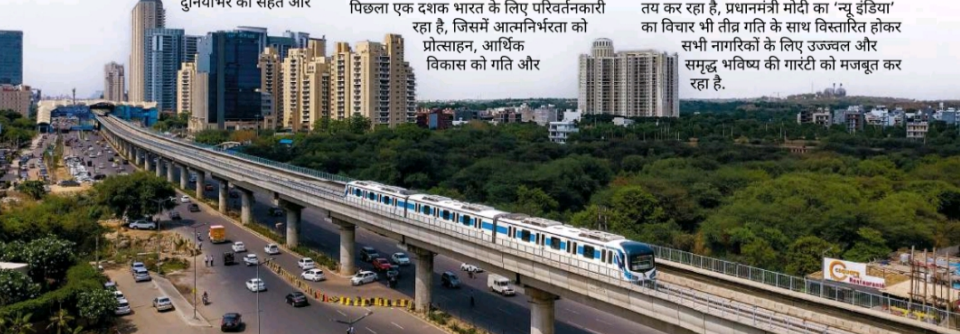
“खादी सिर्फ वस्त्र नहीं, अस्त्र भी है और शस्त्र भी है।”

नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

Khadi India

आलेख: श्री मनोज कुमार, अध्यक्ष, केवीआईसी, भारत सरकार

भारत के ‘स्वदेशी प्रतीक’ से ‘वैश्विक क्रांति’ तक: पीएम मोदी के नेतृत्व में ‘खादी पुनर्जागरण’

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वदेशी आंदोलन के दौरान जिस खादी को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष का सबसे सशक्त हथियार बनाया था, वह आज भारत के आत्मनिर्भरता की एक प्रबल शक्ति के रूप में विकसित हुई है। पिछले 9 वर्षों में, **‘आधुनिक भारत के शिल्पकार’**, **‘आत्मनिर्भर भारत के निर्माता’** और **‘विकसित भारत के सूत्रधार’**, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व में, **‘नये भारत की नयी खादी’** देश में गरीबी निर्मूलन, कारीगर सशक्तिकरण, खाद्य सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और बेरोजगारी उन्मूलन का सबसे सशक्त, सक्षम और सफल ‘अस्त्र और शस्त्र’ बनकर स्थापित हुई है। भारत की विरासत खादी के साथ **‘मोदी सरकार की गारंटी’** जुड़ने से खादी और ग्रामोद्योगी उत्पादों का कारोबार पिछले **वित्तवर्ष में 1.34 लाख करोड़ रुपये** को पार कर गया, जबकि इस क्षेत्र में **9.37 लाख से अधिक नये रोजगार** का सृजन हुआ है।

गत वर्ष नई दिल्ली के प्रतिष्ठित ‘भारत मंडपम’ में 9वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के दौरान, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के सामने **‘मोदी सरकार की गारंटीवाली- नए भारत की नई खादी’** की एक नई तस्वीर पेश की। प्रधानमंत्री जी के शब्दों में- “जिसे स्वदेश पर अभियान होगा, उसके लिए खादी वस्त्र है, लेकिन साथ-साथ जो आत्मनिर्भर भारत के सपने बुनता है, जो मेक इन इंडिया को बल देता है, उसके लिए खादी सिर्फ वस्त्र नहीं, अस्त्र भी है और शस्त्र भी है। संक्षेप में, ‘नये भारत की नयी खादी’ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उस दर्शन का विस्तार है, जिसमें उन्होंने कहा था, “खादी सिर्फ वस्त्र नहीं बल्कि एक विचारधारा है।”

‘मोदी सरकार की गारंटी’ ने ‘खादी आंदोलन’ को किया पुनर्जीवित

स्वतंत्रता से स्वायत्तता तक खादी जहां एक तरफ पूज्य बापू के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन का स्वाभिमान बनी, वहीं आज वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में **‘आत्मनिर्भर और विकसित भारत अभियान’** का अभिमान है। खादी पारंपरिक ग्रामीण कारीगरों द्वारा बनाया गया हाथ से बुना और हाथ से कता हुआ टिकाऊ वस्त्र है। गांधीजी ने खादी की कल्पना ‘स्वदेशी भावना’ को ठोस अभिव्यक्ति देने के साधन के रूप में की थी। उनका विचार था कि खादी के माध्यम से गांवों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। स्वतंत्रता-पूर्व, खादी का विकास वास्तव में एक गैर-सरकारी प्रयास था और गांधीजी ने गांवों में खादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1925 में अखिल भारतीय चरखा संघ नामक एक स्वायत्त संगठन का गठन किया था। गांधीजी का मानना था कि खादी स्वदेशी भावना का प्रतिनिधित्व करती है और भारतीयों को एकजुट करने, आर्थिक स्वतंत्रता और समानता प्राप्त करने का एक साधन है। उनका मानना था कि भारत की आत्मा उसके गांवों में निहित है और भारत की उन्नति के लिए इन गांवों का समृद्ध होना जरूरी है। इस अवधारणा को ध्यान में रखते हुए, आज़ादी के बाद 1956 में पारित संसद के एक अधिनियम द्वारा अप्रैल 1957 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) की स्थापना की गई थी। आज भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत केवीआईसी खादी को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के माध्यम से ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

आजादी के बाद हमारे राष्ट्रीय गौरव खादी को जो उपेक्षा झेलनी पड़ी वह जगजाहिर है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी देश और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पूर्व के वर्षों में खादी के साथ हुए सौतेले व्यवहार पर दुख व्यक्त किया है। हालाँकि, उनके नेतृत्व और अथक प्रयासों के तहत, खादी में एक उल्लेखनीय परिवर्तन आया है, जो केवल 9 वर्षों की अवधि में **मोदी सरकार की गारंटी** वाले एक **‘ग्लोबल ब्रांड’** के रूप में विकसित हुआ है। यह अब गरीबी के खिलाफ लड़ाई और देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक शक्तिशाली ‘अस्त्र’ बनकर उभरा है। नीति आयोग के आंकड़ों के अनुसार, पिछले 5 वर्षों में भारत में 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसके पीछे भी ‘खादी के पुनर्जागरण’ को एक कारक मानते हैं। गत वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में उन्होंने इस आंकड़े का हवाला देते कहा था कि 9 वर्ष पहले खादी और ग्रामोद्योग का कारोबार 31,154 करोड़ रुपये के बीच था, लेकिन आज ये एक लाख तीस हजार

करोड़ रुपए से भी अधिक तक पहुंच चुका है। पिछले 9 वर्षों में अतिरिक्त 1 लाख करोड़ रुपये इस सेक्टर में आए हैं। ये पैसा गांवों में खादी और ग्रामोद्योग सेक्टर से जुड़े गरीबों, वंचितों, दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, किसानों, युवाओं और आदिवासी भाई-बहनों सहित हाशिए पर मौजूद वर्गों तक पहुंचा है, जिसने उन्हें गरीबी रेखा से बाहर निकालने और खाद्य सुरक्षा प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी और ग्रामीणउद्योग को 'अस्त्र' के रूप में प्रयोग किया है। 2014 में अपने सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम **'मन की बात'** की शुरुआत ही से, उन्होंने लगातार जनता से खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों को समर्थन देने और खरीदने का आग्रह किया है, जो खादी उत्पादों के लिए संजीवनी साबित हुई है।

भारत मंडपम और राजघाट जैसे प्रतीकात्मक स्थानों पर जी-20 शिखर सम्मेलन-2023 के आयोजनों से लेकर विभिन्न बहुचर्चित वैश्विक मंचों पर, प्रधानमंत्री ने लगातार खादी पर प्रकाश डाला। उन्होंने जी-20 प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए इसके महत्व को प्रदर्शित करते हुए उन्हें खादी अंगवस्त्रम से अलंकृत किया। दिल्ली के द्वारका में नए एक्सपो सेंटर 'यशोभूमि' में विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ के दौरान, उन्होंने खादी स्टाल पर कारीगरों के साथ गर्मजोशी से बातचीत की और प्रोत्साहन दिया। परिणामस्वरूप; खादी, जो वित्तीय वर्ष 2013-14 से पहले नाजुक स्थिति में थी, को नया जीवनदान मिला। पिछले 9 वर्षों में, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) के प्रयासों से भारत के गांवों, कस्बों, शहरों और सीमावर्ती क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों के उत्पादन, बिक्री और रोजगार सृजन में क्रांतिकारी परिवर्तन दिखा है। ग्रामीण कारीगरों के कौशल को न केवल सम्मान मिल रहा है बल्कि उनकी शिल्पकला का उचित मूल्य भी मिल रहा है।

इस विकासशील और परिवर्तनशील युग में खादी-ग्रामोद्योग का उत्पादन 27 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 95 हजार करोड़ रुपये हो गया। खादी-ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री 33 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 1 लाख 34,000 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गई है। खादी कपड़ों के उत्पादन में 880 करोड़ रुपये से 2915.83 करोड़ रुपये तक आश्चर्यजनक वृद्धि देखी गई है। खादी कपड़ों की बिक्री 1,170 करोड़ रुपये से 6,000 करोड़ रुपये तक आश्चर्यजनक रूप से पहुंच गई है। उल्लेखनीय रूप से, दिल्ली में कनॉट प्लेस स्थित प्रमुख खादी शोरूम ने गांधी जयंती के दिन रिकॉर्ड 1.5 करोड़ रुपये की बिक्री की। खादी महोत्सव के दौरान पूरे देश में 25 करोड़ रुपये की खादी की बिक्री हुई। इसके अलावा, दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले-2023 (आईआईटीएफ) के दौरान महज 14 दिन में 15 करोड़ रुपये खादी की बिक्री हुई। ये उपलब्धियाँ पीएम मोदी की **'मेक इन इंडिया'**, **'वोकल फॉर लोकल'** और **'स्वदेशी उत्पाद'** पहल में लोगों के बेहद बढ़ते विश्वास को दर्शाती है। अपनी विविध योजनाओं के माध्यम से, केवीआईसी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पारंपरिक कारीगरों और महिलाओं को सशक्त बना रहा है।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी केवीआईसी लगातार मील के पत्थर स्थापित कर रहा है। केवीआईसी द्वारा क्रियान्वित खादी गतिविधियों में 80% खादी कारीगर महिलाएं हैं। हर चौथा खादी कारीगर सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों से है। इस प्रकार, खादी कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं और समाज के विभिन्न वर्गों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के कारण खादी सूती , रेशम की साड़ियाँ, सूती शर्ट और कुर्ते जैसे खादी उत्पाद न केवल घरेलू बाजारों में बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी काफी मांग में हैं। खादी की मांग में वृद्धि का श्रेय इसकी बढ़ती अपील और सरकार द्वारा लागू किए गए सहायक उपायों के साथ-साथ इन गतिविधियों में लगे कत्तिनों, बुनकरों और खादी श्रमिकों के समर्पित प्रयासों को दिया जाता है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी खादी को ग्रामीण भारत में कत्तिनों और बुनकरों के बीच आर्थिक आत्मनिर्भरता लाने का एक साधन मानते हैं। वर्ष 2013-14 में खादी कारीगरों को केवल 3.00 रुपये प्रति गुंडी (हैंक) का पारिश्रमिक मिलता था, जिसे 2014-15 में बढ़ाकर 4.00 रुपये प्रति गुंडी कर दिया गया और अब यह 10.00 रुपये प्रति गुंडी तक पहुंच गया है। यह 2013-14 से खादी कारीगरों के वेतन में 233.33% की पर्याप्त वृद्धि को दर्शाता है। 2016 से शुरू होकर, खादी कारीगरों को दी जाने वाली सहायता प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रदान की जाती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि इच्छित लाभार्थियों को सीधे लाभ प्राप्त हो। बेरोजगारी उन्मूलन के 'अस्त्र' के रूप में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) ने देश में रोजगार सृजन में भी नया कीर्तिमान स्थापित किया है।।

Khadi India

खादी विकास योजना की उपलब्धियाँ एक नजर में

- देशभर में लगभग 3,000 खादी संस्थाएं संचालित हैं
- लगभग 5 लाख खादी कारीगरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।
- खादी गतिविधियों में लगे कार्यबल में अब 80 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं।
- पिछले 9 वर्षों में खादी कारीगरों की पारिश्रमिक में 233 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- दिसबंर 2023 तक अर्धसैनिक बलों को 10.89 करोड़ रुपये से अधिक के खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की आपूर्ति की गई है।
- आईआईटी दिल्ली परिसर में खादी स्टोर युवाओं की पहली पसंद बन गया है।
- खादी उत्पादन, गुणवत्ता, ब्रांड वैल्यू और विपणन में विस्तार की योजना बनाई गई।
- 48,000 से अधिक खादी कारीगर वर्कशेड का सफलतापूर्वक निर्माण किया गया।
- 2 केंद्रीय पूनी संयंत्र और 470 खादी आउटलेट का पुनर्निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- देशभर में 5 केंद्रीय पूनी संयंत्र हैं, छठा प्लांट हरियाणा के भिवानी जिले के झुंपा गांव में प्रस्तावित है।

बेरोजगार युवाओं को उनके दरवाजे पर रोजगार के अवसर प्रदान करना है। अपनी स्थापना के बाद से, यह योजना पूरे देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने में एक प्रेरक शक्ति रही है। यह योजना आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के अनुरूप **'नौकरी मांगने वाले के बजाय नौकरी प्रदाता बनने'** के सपने को पूरा करती है। योजना के तहत 9 लाख से अधिक नई परियोजनाएं स्थापित की गई हैं, जो उद्यमशीलता उद्यमों में मजबूत वृद्धि को दर्शाती हैं। रोजगार सृजन पर प्राथमिक ध्यान देने के साथ, पीएमईजीपी ने देश के कार्यबल में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए 78 लाख से अधिक व्यक्तियों के लिए सफलतापूर्वक रोजगार सृजन किया है।

अकेले पिछले वित्तीय वर्ष में, इस योजना ने 9.37 लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार दिया, जो सेवा क्षेत्र पर इसके निरंतर प्रभाव को दर्शाता है। पीएमईजीपी के माध्यम से प्रदान की गई वित्तीय सहायता ₹23,000 करोड़ से अधिक की मार्जिन मनी सब्सिडी के वितरण में स्पष्ट है। यह सब्सिडी इच्छुक उद्यमियों को अपना उद्यम शुरू करने में सक्षम बनाने में सहायक रही है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) आर्थिक विकास के लिए उत्प्रेरक बना हुआ है। जैसे-जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, यह आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत के लिए सरकार के दृष्टिकोण के साथ जुड़कर सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

केवीआईसी की नई योजनाएं: खादी विकास योजना (केवीवाई) और ग्रामोद्योग विकास योजना (जीवीवाई)

ग्रामीण क्षेत्र में खादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए केवीआईसी ने खादी को पुनर्जीवित करने, आधुनिक बनाने और बिक्री बढ़ाने के लिए कई पहल की है। इनमें खादी उत्पादों के उत्पादन और बिक्री को बढ़ाने के लिए **'खादी विकास योजना (KVY)'** का विस्तार शामिल है। योजना के तहत, चार प्रमुख घटकों के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है, पहला है **ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (आई सेक) योजना**, जो केवीआईसी बैंकों के माध्यम से खादी संस्थानों (केआई) को केवल 4% की रियायती ब्याज दर पर ऋण प्रदान करती है। दूसरा, **'मौजूदा कमजोर खादी संस्थाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और विपणन के लिए सहायता'** प्रदान करने के तहत उनके आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और खादी बिक्री करनेवाले शोरूम के नवीनीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। खादी संस्थाओं को पूंजीगत व्यय और कार्यशील पूंजी के लिए अब 9.90 लाख रुपये के बजाय 15.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

'खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड योजना' के तीसरे घटक के तहत, बेहतर कार्य वातावरण के लिए व्यक्तिगत और समूह वर्कशेड के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाती है। खादी कारीगरों की कामकाजी स्थितियों में सुधार के लिए व्यक्तिगत वर्कशेड के निर्माण के लिए अब 60,000 रुपये के बजाय 1,20,000 रुपये और समूह वर्कशेड के निर्माण के लिए 40,000 रुपये के बजाय 80,000 रुपये प्रति कारीगर तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। **संशोधित बाजार विकास सहायता (एमएमडीए)** का चौथा घटक उत्पादक संस्थानों, बिक्री संस्थानों, कारीगरों और कार्यकर्ताओं के बीच वितरित किया जाता है, जिससे खादी संस्थानों और खादी कारीगरों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। सूती, ऊनी और पॉलीवस्त्र के लिए एमएमडीए की गणना अब प्राइम

शीर्ष संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर और खादी कारीगरों की क्षमता निर्माण

केवीआईसी ने खादी के आधुनिकीकरण और प्रचार के माध्यम से **'नए भारत की नई खादी'** के निर्माण के लिए पांच एमओयू पर भी हस्ताक्षर किए हैं। ये रणनीतिक समझौते निफ्ट (NIFT), प्रसार भारती, एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (QCI) जैसे शीर्ष संगठनों के साथ हैं। पीएम मोदी के 'वोकल फॉर लोकल' और 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण के अनुरूप, इन एमओयू का उद्देश्य केवीआईसी को आधुनिक बनाना और युवाओं के बीच इसके उत्पादों को बढ़ावा देना है। केवीआईसी ने विरासत शिल्प को उन्नत और आधुनिक बनाने और नए और आधुनिक डिजाइनों, नए खादी उत्पादों आदि की तकनीकी विशिष्टताओं पर विशेषज्ञ सलाह प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी) के साथ मिलकर खादी उत्कृष्टता केंद्र (सीओईके) भी स्थापित किया है।

वैश्विक मानकों के लिए बेंचमार्क डिजाइन प्रक्रियाएं स्थापित करने, नए कपड़े और उत्पाद बनाने और वस्त्र के लिए गुणवत्ता मानकों का प्रसार करने के लिए इस केंद्र को निफ्ट नई दिल्ली के साथ-साथ निफ्ट, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता और शिलांग के साथ हब और स्पोक मॉडल पर स्थापित किया गया है। केवीआईसी नवीनतम मशीनरी और प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए इन्वेंट्री, उत्पादन और गुणवत्ता प्रबंधन, पैटर्न बनाने और परिधान बनाने, विजुअल मर्चेंडाइजिंग इत्यादि जैसे विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से खादी कारीगरों और खादी श्रमिकों के कौशल बढ़ाने के लिए कार्यक्रम भी आयोजित कर रहा है। इसी प्रकार, गुणवत्ता में सुधार और उत्पादकता बढ़ाने और रोविंग लागत को कम करने के लिए नए केंद्रीय पूनी संयंत्र (सीएसपी) की स्थापना, विद्यमान संयंत्रों का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की (पीएमईजीपी) उपलब्धियां

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), गैर-कृषि क्षेत्र में नई इकाइयों की स्थापना में उद्यमियों की सहायता के लिए एमएसएमई मंत्रालय की प्रमुख योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) को क्रियान्वित कर रहा है। इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों/ग्रामीण और शहरी

कॉस्ट पर 30% के बजाय 35% की जा रही है। केवीवाई सकारात्मक बदलाव के उत्प्रेरक के रूप में उभरा है। इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत विभिन्न उपलब्धियां दर्ज की गई हैं, जो जमीनी स्तर पर इसके प्रभाव को रेखांकित करती हैं।

केवीआईसी **'ग्रामोद्योग विकास योजना' (GVY)** के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम को लागू करके गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के पूज्य बापू के सपने को पूरा कर रहा है। पिछले 9 वर्षों के दौरान विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से लगभग 14,000 खादी कारीगरों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। **हनी मिशन, कुम्हार सशक्तीकरण** आदि योजनाओं ने कारीगरों और लाभार्थियों को अपनी आय बढ़ाने और आजीविका के अवसरों में सुधार करने के बेहतरीन अवसर दिए हैं। एक सुदृढ़ सहायता के रूप में कारीगरों को मशीनरी और टूलकिट वितरित किए जाते हैं। विभिन्न ग्रामीण उद्योगों जैसे साबुन बनाना, ताड़ का गुड़, अगरबत्ती निर्माण, हाथ कागज रूपांतरण, चमड़ा उद्योग और ग्रामीण इंजीनियरिंग आदि में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। 1.92 लाख से अधिक मधुमक्खी बक्सों के वितरण के अलावा कारीगरों को 6000 से अधिक टूलकिट वितरित किए गए हैं, जिससे जमीनी स्तर पर कौशल विकास और उद्यमिता को सक्षम बनाया जा सके। इसके अलावा, कुम्हारी कारीगरों को 28,072 विद्युत चालित कुम्हारी चाक, 1658 होम स्केल क्ले ब्लंजर्स, 360 पगमिल्स और 54 भट्टियां भी अब तक कारीगरों को प्रदान की गई हैं, जिससे कुम्हारों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। इसी प्रकार **'स्फूर्ति' (SFURTI)** योजना के माध्यम से केवीआईसी ने परंपरागत कारीगरों के जीवन में भी बड़ा बदलाव किया है।

'आत्मनिर्भर और विकसित भारत' के लिए केवीआईसी की भविष्य की योजनाएं

खादी की भविष्य की योजनाओं में **'नए भारत की नई खादी'** पांच नई योजनाओं पर तेजी से काम कर रही है: खादी शक्ति, कुशल कारीगर विकास योजना, महिला सिलाई समृद्धि योजना, लोटस सिल्क और माटी कला कुम्हार सशक्तीकरण। **खादी शक्ति** का उद्देश्य खादी को बढ़ावा देना और देश के दूरदराज के गांवों में काम करने वाले कारीगरों को सहायता प्रदान करना है। **कुशल कारीगर विकास योजना** के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में अधिक से अधिक कुशल कारीगरों को तैयार करना है। **महिला सिलाई समृद्धि योजना** ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शक्ति को अधिक अवसर प्रदान करेगी। केवीआईसी की **लोटस सिल्क** योजना के बैनर तले मणिपुर के कारीगरों द्वारा कमल के तने से निकलने वाले रेशे से तैयार 'लोटस सिल्क' तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। कुम्हारों को उत्पादन और मजदूरी में वृद्धि के माध्यम से सम्मानजनक जीवन देने के उद्देश्य से **माटी कला कुम्हार सशक्तिकरण** के तहत कारीगरों को कौशल उन्नयन, प्रशिक्षण और उपकरण वितरित किए जाएंगे।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, **'खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन और खादी फॉर ट्रांसफॉरमेशन '** का मंत्र अब **"वैश्विक क्रांति"** के लिए तैयार है। इस मंत्र का सार खादी को अस्त्र और शस्त्र दोनों के रूप में जोर देने वाले नारे में समाहित है, जिसने खादी उद्योग को पुनर्जीवित किया है और इसे राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक में बदल दिया है। खादी को **फैशनेबल और पर्यावरण के अनुकूल** विकल्प के रूप में बढ़ावा देकर, केवीआईसी न सिर्फ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित कर रहा है बल्कि **'ग्लोबल वार्मिंग'** को भी कम करने के दिशा में अभूतपूर्व कोशिश कर रहा है। **मोदी सरकार की गारंटी** के अनुरूप केवीआईसी अपने प्रयासों से आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से पहुंचा रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी के समावेशी दृष्टिकोण के नारे **'सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास'** को खादी ने आत्मसात किया है। **'वोकल फॉर लोकल'** और **'मेक इन इंडिया'** की अवधारणा स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने और उसे सशक्त बनाने के केवीआईसी के मिशन के साथ गहराई से मेल खाती है। मोदी सरकार के विजन के अनुसार 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में केवीआईसी भी ग्रामीण भारत को आर्थिक रूप से सशक्त कर महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

> "मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती निर्माण और मिट्टी के बर्तन बनाने जैसे ग्रामीण आधारित उद्योगों के माध्यम से, केवीआईसी यह सुनिश्चित करता है कि ग्रामीण आबादी सक्रिय रूप से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहे **'नवीन खादी आंदोलन'** का लाभ उठा सके। "**एक भारत, श्रेष्ठ भारत**" का दृष्टिकोण विविधता में एकता पर जोर देता है। खादी और अन्य स्वदेशी उत्पादों के माध्यम से राष्ट्रीय पहचान की भावना को बढ़ावा देकर, केवीआईसी 2047 तक एक मजबूत और एकजुट **'विकसित भारत'** के निर्माण में योगदान दे रहा है।"
>
> Khadi India

पारंपरिक चिकित्सा के माध्यम से सशक्त होती स्वास्थ्य सेवा

आयुष मंत्रालय की प्रेरणादायक यात्रा

श्री सर्बानंद सोणोवाल
माननीय केंद्रीय मंत्री
आयुष और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

माननीय केंद्रीय मंत्री आयुष और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, श्री सर्बानंद सोणोवाल ने एक विशेष साक्षात्कार में माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत आयुष क्षेत्र में हुई उपलब्धियों और प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने अनुसंधान के क्षेत्र में मंत्रालय की प्रगति, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) जैसे अंतरराष्ट्रीय निकायों के साथ सहयोग और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में उपलब्धियों की रूपरेखा प्रस्तुत की जो विश्व स्तर पर आयुष प्रणालियों को बढ़ावा देने और घरेलू स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल सेवा के विस्तार और सुधार की दिशा में एक ठोस प्रयास को दर्शाती है।
प्रस्तुत हैं प्रमुख अंश:

प्रश्न: मंत्रालय आयुष सेक्टर में साक्ष्य सृजन के संबंध में किस प्रकार प्रगति कर रहा है?

आयुष मंत्रालय एक सशक्त अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। हमारे यहाँ पाँच अनुसंधान परिषद और अनेक राष्ट्र स्तरीय संस्थान हैं जो स्वायत्त निकायों के रूप में कार्यरत हैं और अनुसंधान गतिविधियों में सक्रिय हैं। विशेष रूप से हमारे आयुष रिसर्च पोर्टल में 41 हजार से अधिक शोध अध्ययन प्रकाशित हैं जिनमें कोविड-19 के 150 शोध अध्ययन शामिल हैं। हम क्लीनिकल रिसर्च पर भी ध्यान दे रहे हैं और अपने शोध प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए सेंटर फॉर एक्सिलेन्स जैसी योजना की पहल भी की गई है।

प्रश्न: हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में लॉन्च किए गए डब्ल्यूएचओ आईसीडी -11 टीएम मॉड्यूल 2 की विशेषता और महत्व के बारे में बताएँ?

सच कहें तो, दिल्ली में WHO द्वारा ICD-11 TM मॉड्यूल 2 जारी होना देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह मॉड्यूल, विशेष रूप से आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी (एएसयू) जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के लिए तैयार किया गया है जो रोगों (डिसॉर्डर्स और पैटर्न्स) के वर्गीकरण को एक मानक (स्टैंडर्ड) प्रदान करता है। यह मानकीकरण इन पद्धतियों में वैश्विक समझ और अनुसंधान की सुविधा प्रदान करता है और दुनिया भर में आयुष की पहुंच और स्वीकार्यता को प्रदर्शित करता है। हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसे हमारे देश की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और अपने "मन की बात" के नवीनतम एपिसोड में आईसीडी टीएम मॉड्यूल 2 की भूमिका और कार्यप्रणाली को स्पष्ट रूप से समझाया। उन्होंने कहा, यह मॉड्यूल न केवल आयुष क्षेत्र में अनुसंधान की सुविधा प्रदान करेगा बल्कि अकादमिक क्षेत्रों में भी नई चीजें सीखने की सुविधा प्रदान करेगा जिससे हमारे देश और दुनिया भर में आयुष (आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी) चिकित्सा को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

प्रश्न: मंत्रालय डब्ल्यूएचओ के साथ विभिन्न पहलुओं पर और किस प्रकार सहयोग कर रहा है?

आयुष मंत्रालय मानकों के विकास, डिजिटल प्रौद्योगिकी और अनुसंधान की दिशा जैसे कई मोर्चों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर काम कर रहा है। ICD-11 टीएम मॉड्यूल 2 रिलीज के अलावा हमने जामनगर, गुजरात में WHO के ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन (GCTM) की स्थापना भी की है जो किसी भी विकासशील राष्ट्र में अपनी तरह का पहला केंद्र है। आयुर्वेद प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (आईटीआरए), जामनगर और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई) को विश्व स्वास्थ्य संगठन के पारंपरिक औषधियों के सहयोगी केन्द्रों के रूप में नामित किया गया है। WHO m-Yoga ऐप को लॉन्च किया गया है और आयुष मंत्रालय ने 3 परियोजना सहयोग समझौतों (PCA) पर भी हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने कोविड-19 पर भी विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर काम किया है। आयुर्वेद, योग और यूनानी चिकित्सा पद्धति में प्रशिक्षण के लिए बेंचमार्क भी प्रकाशित किए गए हैं।

प्रश्न: आपके मंत्रालय ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में कौन-कौन सी उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं?

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में हमारे द्वारा किए गए प्रयासों के महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए हैं। उदाहरण के लिए आयुष के आयुष्मान आरोग्य मंदिर अभियान के अंतर्गत लाभार्थियों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने वालों का आंकड़ा 17 करोड़ को पार कर गया है। हमने असम में केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जैसी उल्लेखनीय पहल के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए 22 डिजिटल परियोजनाओं का विकास किया है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आयुष मिशन ने देश भर में स्वास्थ्य सेवा केंद्रों के संचालन में उल्लेखनीय प्रगति की है जो सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धि को और बढ़ाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

हाल के वर्षों में आयुष मंत्रालय ने , भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में और माननीय केंद्रीय आयुष और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोणोवाल के नेतृत्व में एक परिवर्तनकारी पहल की है। इन प्रयासों ने न केवल पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को उन्नत किया है बल्कि भारत को समग्र स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित किया है। प्रस्तुत है आयुष मंत्रालय द्वारा किए गए प्रेरणादायी कार्यों, उपलब्धियों और योगदान पर विस्तृत आलेख -

आईसीडी -11 टीएम अध्याय 26 मॉड्यूल -2 लॉन्च: ग्लोबल हेल्थकेयर में एक मील का पत्थर

10 जनवरी, 2024 को, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और आयुष मंत्रालय ने ICD-11 पारंपरिक चिकित्सा अध्याय 26 मॉड्यूल-2 संस्करण लॉन्च किया और इसे वैश्विक स्तर तक ले जाने की शुरुआत की। इस पहल के अंतर्गत आईसीडी-11 टीएम अध्याय 26 मॉड्यूल-2 में आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा की शब्दावलियों की इंडेक्सिंग की गई है जिससे बीमारियों (डिसॉर्डर्स और पैटर्न्स) की अंतर्राष्ट्रीय कोडिंग की सुविधा मिलती है। 529 प्रविष्टियों के साथ यह कदम भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों की वैश्विक मान्यता और स्वीकार्यता को प्रदर्शित करता है जिससे दुनिया भर में हेल्थकेयर मानकीकरण, स्वास्थ्य बीमा और अनुसंधान के अवसरों को बढ़ावा मिलता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन सहयोग: विकसित होती वैश्विक साझेदारी

जामनगर, गुजरात में पहले और एकमात्र ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन (डब्ल्यूएचओ जीसीटीएम) की स्थापना के अतिरिक्त आयुष मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ बड़े पैमाने पर सहयोग स्थापित किया

है जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन और डब्ल्यूएचओ कोलैबोरेशन सेंटर इन ट्रेडिशनल मेडिसिन (योग) की स्थापना जैसी पहल शामिल हैं। परियोजना सहयोग समझौतों और बेंचमार्क प्रकाशनों के माध्यम से भारत ने वैश्विक मंच पर पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान और एकीकरण को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

ब्रिक्स सहभागिता: अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सशक्त करने की पहल

भारत की सक्रियता से ब्रिक्स देशों ने अपनी राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में पारंपरिक चिकित्सा की भूमिका पर जोर दिया है। ब्रिक्स गठबंधन और परंपरागत चिकित्सा पर ब्रिक्स फोरम का निर्माण समग्र स्वास्थ्य देखभाल के लिए पारंपरिक चिकित्सा की क्षमता का उपयोग करने में सदस्य देशों को भी प्रोत्साहित करता है।

एससीओ सम्मेलन: व्यापार और सहयोग वृद्धि

प्रथम शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) सम्मेलन ने भारत के पारंपरिक चिकित्सा कौशल को प्रदर्शित होने का अवसर प्राप्त हुआ। इस आयोजन से महत्वपूर्ण व्यापारिक उपलब्धियाँ हासिल करने के अवसर प्राप्त हुए और सदस्य देशों के बीच साझेदारी को प्रोत्साहन मिला। 590 करोड़ रुपये से अधिक के ट्रेड कमिटमेंट्स और बी-टू-बी बैठकों के माध्यम से भारत ने पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दर्ज की और अपने बाजार की पहुँच को विस्तारित किया। इस आयोजन में 56 से अधिक एक्जीबिटर्स ने सहभागिता की। इस प्रयास से खरीदारों और विक्रेताओं के बीच 50 से अधिक बैठकें आयोजित हुईं। इसके अतिरिक्त, भारत, ताजिकिस्तान, आर्मेनिया, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया, कजाकिस्तान, बहरीन और श्रीलंका सहित 19 देशों के प्रतिभागियों की 75 से अधिक बैठकें आयोजित हुईं जिनमें पारंपरिक चिकित्सा व्यापार पर चर्चाएँ आयोजित की गईं।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस: विश्व स्तर पर वेलनेस प्रसार

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) एक वैश्विक उत्सव के रूप में उभर कर सामने आया है। इस उत्सव ने विश्व रिकॉर्ड स्थापित किए हैं और योग की सार्वभौमिक अपील में वृद्धि की है। गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और ओशन रिंग ऑफ योग जैसी अभिनव पहलों के साथ भारत ने योग की परिवर्तनकारी शक्ति से दुनिया भर में वेलनेस (स्वास्थ्य कल्याण) को बढ़ावा देने की भूमिका को प्रदर्शित किया है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयॉर्क में आयोजित IDY 2023 में प्रधानमंत्री जी ने 135 देशों के प्रतिनिधियों के साथ सामूहिक योग में सहभागिता की। सामूहिक योग के इस कार्यक्रम से एक विश्व रिकॉर्ड भी स्थापित हुआ। IDY 2023 में लगभग 23.14 करोड़ व्यक्तियों ने भारी संख्या में हिस्सेदारी की।

एम-योग ऐप: प्रौद्योगिकी के माध्यम से वेलनेस

एम-योग ऐप पर डब्ल्यूएचओ के साथ आयुष मंत्रालय का सहयोग विश्व स्तर पर योग और कल्याण को बढ़ावा देने में एक डिजिटल उत्थान का प्रतीक है। यह मोबाइल ऐप कोविड महामारी के स्वास्थ्य सेवाओं के पुनः बहाल होने और संयुक्त राष्ट्र की स्वस्थ रहें, मोबाइल बनें अभियान पहल के विचार से जुड़ कर काम करती है। मोबाइल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से समग्र स्वास्थ्य कवरेज को बढ़ावा मिलता है।

आयुष शिक्षा के नए आयाम : एक सशक्त भविष्य का निर्माण

ऐतिहासिक सुधारों और छात्र-केंद्रित पहल के साथ आयुष मंत्रालय ने भारत में आयुष शिक्षा में क्रांति ला दी है। भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिये राष्ट्रीय आयोग (National Commission for Indian System of Medicine- NCISM) अधिनियम, 2020 और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (NCH) अधिनियम, 2020 को सितंबर 2020 में अधिनियमित किया गया था। एनईपी (नेशनल एजुकेशन पॉलिसी) 2020 के साथ आयुष शिक्षा को जोड़ते हुए ये आयोग पारदर्शिता, दक्षता और छात्र केंद्रित शिक्षा को शिक्षा प्रणाली के भीतर लेकर आ रहे हैं जो आयुष शिक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन है और इस प्रकार आयुष शिक्षा का विनियमन और मानकीकरण अधिक सशक्त तरीके से सुनिश्चित होगा।

सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए आयुष: प्रिवेन्टिव और प्रोमोटिव हेल्थकेयर सुविधा

राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसे मुख्यधारा के साथ एकीकृत करने के आयुष मंत्रालय के प्रयासों में एक आधारशिला की तरह है। आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में नामित) की स्थापना और संचालन सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्थापित आयुष मंत्रालय के प्रमुख घटकों में से एक है। जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर व्यापक स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करना है। इन्हीं 12500 स्वीकृत केंद्रों में से 9000 से अधिक क्रियान्वित हैं जो आयुष सेवाओं के माध्यम से 17 करोड़ से अधिक लोगों को लाभान्वित कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त, सेवा प्रदान करने और अधोसंरचना मे वृद्धि के लिए 315 आयुष अस्पतालों और 5023 आयुष औषधालयों को अपग्रेड किया गया है।

एनएएम (NAM) ने आयुष को-लोकेशन योजना के अंतर्गत 2375 पीएचसी (प्राइमरी हेल्थ सेंटर), 713 सीएचसी (कम्युनिटी हेल्थ सेंटर) और 306 डीएच (डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल) को सहायता प्रदान की है। राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत गर्भावस्था के दौरान देखभाल के परिणामों में सुधार लाने और मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सुप्रजा (आयुष मातृ एवं नवजात शिशु हस्तक्षेप) जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से विशेष स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान किया जा रहा है। वयो मित्र योजना (आयुष वृद्धावस्था स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं) स्वास्थ्य और आयु के साथ वृद्धावस्था देखभाल को प्रोत्साहित करती है। इस का उद्देश्य आयुर्वेद-आधारित उपचारों के माध्यम से प्रिवेन्टिव और प्रोमोटिव स्वास्थ्य देखभाल करना, समग्र स्वास्थ्य कल्याण और बीमारी की रोकथाम और आयुष चिकित्सकों और सुविधाओं से सुसज्जित आयुष मोबाइल मेडिकल यूनिट की सुविधा का प्रसार करना है।

अनुसंधान पहल: साक्ष्य-आधारित अभ्यास को आगे बढ़ाना

आयुष मंत्रालय का मजबूत अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र पाँच अनुसंधान परिषदों और उनके नेटवर्क संस्थानों द्वारा पारंपरिक चिकित्सा में साक्ष्य-आधारित सेवाओं और नवाचार को बढ़ावा देता है। आयुर्जेनोमिक्स पहल और एआई-आधारित आयुरटेक परियोजनाओं में प्रमुख संस्थानों के साथ सहयोगात्मक प्रयास, स्वास्थ्य सेवा की उन्नति के लिए अत्याधुनिक तकनीक का लाभ उठाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं। देश भर के सभी एआईआईएमएस (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) में अत्याधुनिक आयुष-आईसीएमआर एडवांस्ड सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव रिसर्च की भी स्थापना की गई है। इसके अलावा कोविड जैसी लंबे समय तक चलने वाली महामारियों से निपटने के लिए अश्वगंधा के नैदानिक परीक्षण पर अनुसंधान भी किए जा रहे हैं। यह अनुसंधान अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए) लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन (एलएसएचटीएम) के साथ आयोजित कर रहा है।

स्वास्थ्य के लिए एआई: समग्र कल्याण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग

इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन(आईटीयू) के स्वास्थ्य से संबंधित फोकस ग्रुप को शामिल करते हुये, स्वास्थ्य सेवा में एआई (आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस) के क्षेत्र में भारत का नेतृत्व समग्र स्वास्थ्य कल्याण के लिये भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पारंपरिक चिकित्सा में एआई आधारित जेनोमिक्स और डिजिटल माध्यमों को अपनाकर, भारत सहयोगपूर्ण अनुसंधान और साक्ष्य आधारित अभिलेख तैयार करने की नई राह बना रहा है।

श्री नरेंद्र मोदी और श्री सर्बानंद सोणोवाल के दूरदर्शी नेतृत्व में आयुष मंत्रालय की यात्रा एक परिवर्तनकारी आंदोलन से कम नहीं रही है। वैश्विक मानकीकरण से लेकर जमीनी स्तर पर सशक्तीकरण तक, भारत के पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र ने उल्लेखनीय प्रगति की है जिससे दुनिया भर में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली प्रभावित हुई है। आज भारत समग्र कल्याण का चैंपियन बना हुआ है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज) और जन सामान्य संबंधी स्वास्थ्य कल्याण के प्रयास पारंपरिक चिकित्सा को अपनाने वाले देशों के लिए एक प्रेरणा के रूप में काम कर रहे हैं।

विक्रम साहनी,

एक दूरदर्शी नेता जो आत्मनिर्भर भारत को रूपांतरित कर रहे है

वर्तमान परिद्वेश्य में दूरदर्शी नेताओं की विशाल संख्या में, श्री विक्रमजीत सिंह साहनी आत्मनिर्भरता और समुदाय कल्याण के एक प्रतीक चिन्ह के रूप में हैं। एक बहुत साधारण सी शुरुवात करके पद्म श्री से सम्मानित होना, सन फाउंडेशन के चेयरमैन और विश्व पंजाबी संगठन के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सामाजिक व सांस्कृतिक संगठ्नों का गठन कर उन्हें सुचारू रूप से चलाना और उसके बाद अपने सामाजिक कार्यों की वजह से देश के संसद के उच्च सदन राज्य सभा के सदस्य बनने तक का उनका सफ्लतापूर्ण सफर , समाज के प्रति उनके समर्पण और दूरदर्शिता क प्रतीक है। उनकी योजनाएं, जैसे 'एंजल्स ऑफ सन' और 'भारत का रोजगार पुरुष', सामाजिक-आर्थिक सुधार लाने का प्रयास कर रही हैं। 'सूर्य किरण' पहला चरण है, जिसमें 20,000 से अधिक ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं, जो उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। उनका समर्थन युवाओं के कौशल विकास में भी है, जिससे उन्होंने सन फाउंडेशन के वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, दिल्ली, और मल्टी स्किल डेवेलपमेंट सेंटर, अमृतसर की स्थापना की है।

उनके नेतृत्व में, ये केंद्र युवाओं को नौकरी प्राप्त करने में मदद कर रहे हैं और इसमें पिछले साल 2500 से अधिक छात्रों को शामिल होने का साबित हुआ है। श्री साहनी ने नशे विरोधी अभियान के तहत पंजाब में पुनर्वास केंद्रों को स्थापित किया है और लगभग 500 युवाओं को नशे से बाहर निकालकर समाज में वापसी कराई है। उनका योगदान विदेशी मामलों में भी है, जैसे कि अफगानिस्तान में हिन्दुओं और सिखों की रक्षा करना और तुर्की, लीबिया, और ओमान में भारतीयों को सुरक्षित वापस लाना। कोविड-19 के दौरान, उनका सक्रिय योगदान स्वास्थ्य सेवाओं की सुरक्षा, ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स के वितरण, और गुरुद्वारा रकाब गंज में 400-बेड कोविड केयर सेंटर की स्थापना में था।

वैश्विक पटल पर श्री साहनी ब्रिक्स, बी20, इंडो-अरब फोरम और सार्क जैसे प्रतिष्ठित मंचों पर नेतृत्व की भूमिका निभाते हुए 'मेक इन इंडिया' पहल का उत्साहपूर्वक समर्थन करते रहे है। महामारी के दौरान संकट प्रबंधन से लेकर कौशल विकास और रोजगार के माध्यम से युवाओं के सशक्तिकरण तक, वह 'आत्मनिर्भरता' की भावना का प्रतीक हैं। जैसे-जैसे भारत आत्मनिर्भर भविष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है, श्री साहनी जैसे नेता देश के सूक्ष्म और व्यापक आर्थिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आते हैं। आत्मनिर्भरता, सशक्तिकरण और सामुदायिक कल्याण के सिद्धांतों के प्रति उनका समर्पण निस्संदेह उन्हें आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में स्थापित करता है।

नागास्त्र 1: नागपुर में सोलर इंडस्ट्रीज के उत्पादन के तहत पहला स्वदेशी एबॉर्ट, रिकवर और रीयूज क्षमता वाला लॉइटर एम्युनिशन

सोलर इंडस्ट्रीज : भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध

दूरदर्शी राष्ट्र के लिए समर्पित बारूद बनाने वाली एक कंपनी ने राष्ट्र की रक्षा का बीड़ा उठाया तथा बदलते वक्त के साथ सोलर इंडस्ट्रीज ने विकसित तथा समकालीन युद्धकला का साजो-सामान बनाने लगी ताकि हमारा देश किसी भी क्षेत्र से उत्पन्न खतरों को बेअसर कर सके।

सत्यनारायण नुवाल द्वारा 1996 में स्थापित सोलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज आज 2,600 एकड़ में फैला है तथा इस कंपनी में 8,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमि. और उसकी सहायक कंपनी इकॉनोमिक एक्स्प्लोसिव्ज लिमि. (ईईएल) के चेयरमैन के रूप में उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने सोलर ग्रुप मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी को देश में रक्षा क्षेत्र के उद्योग में विकसित होने का रास्ता दिखाया, जिसका कामकाज औद्योगिक विस्फोटकों, सैन्य विस्फोटकों, प्रोपेलैंट, डेटोनेटर, बूस्टर और पायरो डिवाइस तक फैला है। आज समूह की चार उपमहाद्वीपों में 4 मैन्यूफैक्चरिंग सुविधाएं स्थापित हैं, जो 60 से ज्यादा देशों की मांग पूरी करती हैं। सोलर के पास नागपुर में दुनिया का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक एचएमएक्स उत्पादन संयंत्र है, जो एचएमएक्स और एचएमएक्स आधारित अन्य पदार्थो का उत्पादन करता है, जिनके लिए अभी तक हमारा देश अपनी आवश्यकता के लिए पूर्ण रूप से आयात पर निर्भर था। भारत की जरूरतें पूरी करने के बाद यह अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इस्राएल जैसे देशों और दूसरे यूरोपीय देशों को एचएमएक्स और उसके अवयव नियमित रूप से निर्यात करता है। ईईएल संपूर्ण गोला-बारूद बनाने वाली भारत की पहली निजी कंपनी है। इसने 99.868 विश्वसनीयता के साथ 10 लाख मैनेड या हथगोले विकसित और सप्लाई किए, जिसने पुराने जमाने के एम 36 ग्रेनेड की जगह ली। समूह के पास 30 एमएम का गोला-बारूद, एंटी-टैंक माइंस, मिसाइलें, हवाई बम, आदि विकसित और मैन्यूफैक्चर करने की सुविधाएं हैं। डीआरडीओ की तकनीकी सहायता से ईईएल ने पिनाका मल्टी-बैरल रॉकेट प्रणाली के तीन विभिन्न कार्य प्रणाली के लिए विकसित किए हैं। हमारे सशस्त्र बलों को पिनाका रॉकेट प्रणाली की अत्यधिक आवश्यकता है और ईईएल ने इन जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादन के अपने बुनियादी ढांचे का इसके अनुरूप निर्माण किया है तथा आर्मीनिया से इसके निर्यात का ऑर्डर भी मिल चुका है। कंपनी स्वदेशी तोपों की मारक क्षमता 300 किमी तक बढ़ाने के लिए लंबी दूरी की सटीक रॉकेट प्रणाली महेश्वरास्त्र विकसित कर रही है। यह प्रणाली 10 मी से कम की सीईपी के साथ लक्ष्यों को सटीक ढंग से वेधने के लिए आइएनएस / जीपीएस से दिशानिर्देशित होगी और यह 90% से ज्यादा सामग्री स्वदेशी है।

अलग-अलग टिकाऊ क्षमता, दूरी और युद्धसामग्री वाले लॉइटरिंग एम्यूनिशन का विकास और निर्माण विभिन्न देशों की तरफ से विकसित किए जा रहे हथियारों में सबसे आगे है। सोलर इंडस्ट्रीज 15 किमी से 100 किमी से भी अधिक दूरी तक की और 1 किग्रा से 10 किग्रा तक युद्धसामग्री ले जाने की क्षमता वाली लॉइटर एम्यूनिशन श्रृंखला नागास्त्र विकसित कर रही है। लक्ष्य नहीं मिलने या मिशन समाप्त होने की स्थिति में इन लॉइटर एम्यूनिशन को वापस बुलाया और फिर इस्तेमाल किया जा सकता है। सफल उपयोगकर्ता परीक्षणों के बाद नागास्त्र 1 का उत्पादन शुरू हो गया है तथा नागास्त्र 2 व नागास्त्र 3 विकास का कार्य योजना बद्ध तरीके से विकसित हो रहा है।

दुश्मन की तरफ से तैनात ड्रोनों का मुकाबला करने के लिए ईईएल काउंटर ड्रोन प्रणाली भार्गवास्त्र विकसित कर रहा है, जो माइक्रो गाइडेड मिसाइलों का इस्तेमाल करके दुश्मन के ड्रोन झुंडों को मार गिराने की क्षमता से लैस है। सोलर ग्रुप ने गोला-बारूद और रक्षा प्रणालियां विकसित करने की सुविधाएं तैयार की हैं। उसके नागपुर स्थित परिसर में रॉकेट, भूमास्त्र / गोला-बारूद के कार्यप्रदर्शन मूल्यांकन के लिए आइसोथर्मल माइक्रो कैलोरीमेट्री (आइएमसी) पर आधारित एम्यूनिशन ऐंड एनर्जेटिक मटेरियल की शेल्फ लाइफ तय करने के लिए देश में विश्वस्तरीय सुविधा विकसित करने वाली पहली कंपनी है, जिसने शेल्फ लाइफ आकलन की मौजूदा 70 साल पुरानी आदिकालीन आइएसएटी आधारित पद्धति को आमूलचूल बदल दिया।

देश को गोला-बारूद और रक्षा प्रणालियों के मामले में आत्मनिर्भर बनाना सत्यनारायण नुवाल का जुनून है। उनकी अगुआई में सोलर समूह सरकार के मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड संकल्प को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। समूह ने अनुसंधान, तकनीकी परिष्कार, नए उत्पादों का विकास और उच्च ऊर्जा सामग्रियों के उत्पादन में कदम रखा है। इसने अत्यधिक स्वदेशी सामग्रियों के साथ और गुणवत्ता के वैश्विक मानदंडों को पूरा करते हुए अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियों का विकास करने के लिए प्रेरित मानव संसाधनों की समर्थ टीम का निर्माण किया है और अन्य उद्योगों और स्टार्ट-अप के साथ गठबंधन और भागीदारियां कायम की हैं।

सत्यनारायण नुवाल की कारोबारी सूझबूझ ने समूह के राजस्व के लिए लगातार उच्च वृद्धि का रास्ता पक्का किया है। सोलर इंडस्ट्रीज 2006 में सार्वजनिक कंपनी बनी जो बीएसई और एनएसई दोनों में सूचीबद्ध है तथा कंपनी का बाजार पूंजीकरण वर्तमान में करीब 60,000 करोड़ रुपए है।

भारतीय कृषि क्षेत्र में भौगोलिक संकेतक (जीआई)

धरोहर की सुरक्षा करना, किसानों को सशक्त बनाना

भौगोलिक संकेतक (जीआई) किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान के उत्पादों के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रतीक होते हैं, जिनमें उस स्थान की विशेषता या उस स्थान से जुड़ी ख्याति शामिल होती है। वे यह प्रमाणित करते हैं कि उत्पाद में विशिष्ट विशेषताएं हैं, जिसे पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके बनाया जाता है या जिसे उत्पत्ति के स्थान के कारण एक निश्चित प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। जीआई विशिष्ट क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए क्षेत्रीय उत्पादों की ख्याति और विरासत की संरक्षा करते हैं। वे उत्पादों को एक अलग पहचान प्रदान करते हैं और विशिष्ट क्षेत्रों से जुड़े उत्पादों की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को बनाए रखते हुए उनके भौगोलिक नाम के अनधिकृत उपयोग को रोकते हैं।

भारतीय किसानों द्वारा उत्पादन परंपराओं का समृद्ध इतिहास कृषि क्षेत्र में भौगोलिक संकेतों (जीआई) की विविधता का साक्ष्य रहा है। भारत अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में ऑर्गेनिक रूप से उत्पादित विशिष्ट कृषि उत्पादों के संरक्षण के लिए ठोस प्रयास कर रहा है। **माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित होकर और माननीय केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल** के नेतृत्व में सरकार जीआई-टैग किए गए उत्पादों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। इस दृढ़ प्रतिबद्धता ने न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत के अनूठे कृषि उत्पादों को प्रदर्शित करते हुए हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खरीदारों द्वारा संचालित वैश्विक बाजारों में, सुदृढ़ भारतीय कृषि ब्रांडों का विकास हमारे किसानों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनने में सहायता प्रदान कर रहा है। इस तरह की उल्लेखनीय उपलब्धियां उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) की रणनीतिक पहल और अटूट समर्पण के महत्वपूर्ण कारण हैं।

जीआई टैग: किसानों-उत्पादकों को सशक्त बनाना और संस्कृति को समृद्ध करना

भारत में फल, सब्जियां, मसाले और अन्य कृषि उत्पादों की एक श्रृंखला है। **जलवायु, मिट्टी और पारंपरिक कृषि पद्धतियों** सहित भौगोलिक कारक, इन उत्पादों को विशेष बनाने में योगदान करते हैं। हिमालय की तलहटी के सुगंधित बासमती चावल से लेकर उत्कृष्ट दार्जिलिंग चाय तक, प्रत्येक उत्पाद अपने उत्पति क्षेत्र के विशिष्ट विविधता को दर्शाते हैं, जो उत्पाद और भूमि के बीच संबंध सुनिश्चित करती है। कृषि उत्पादों के लिए एक भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग प्राप्त करना किसानों और समुदायों को समान रूप से लाभ प्रदान करता है।

सर्वप्रथम, जीआई-टैग उत्पाद प्रायः बाजार में अधिक कीमतों पर मिलते हैं, जिससे किसानों को उनके गैर-जीआई उत्पादों की तुलना में बेहतर लाभ मार्जिन मिलता है। इसके अलावा, जीआई टैग उत्पाद नामों के दुरुपयोग के विरूद्ध एक सुरक्षात्मक ढाल के रूप में कार्य करता है और उत्पादों को उनकी ख्याति से जुड़े अनुचित उपयोग को रोकता है, जिससे किसानों की आय की रक्षा होती है। इसके अतिरिक्त, जीआई-टैग किए गए उत्पादों पर दी गई वैश्विक मान्यता घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी व्यापक स्वीकृति सुनिश्चित करती है, जिससे बाजार का विस्तार होता और राजस्व में वृद्धि होती है। इसके अलावा, पारंपरिक कृषि पद्धतियों और क्षेत्रीय प्रोसेसिंग तकनीकों के संरक्षण को प्रोत्साहित करके, जीआई टैग इन उत्पादों से जुड़ी अनूठी विशेषताओं और उसकी विरासत को बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। आर्थिक लाभों के अलावा, जीआई-टैग किए गए उत्पाद ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और संबद्ध आर्थिक कार्यकलापों को

उत्प्रेरित करते हैं, रोजगार के अवसर सृजित करते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा, जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देना और जीआई उत्पादन पद्धतियों में अंतर्निहित प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग, पर्यावरण संरक्षण और दीर्घकालिक स्थिरता में योगदान देता है, जो बड़े पैमाने पर संरक्षण लक्ष्यों के साथ कृषि पद्धतियों को सुव्यवस्थित करता है।

कृषि की विरासत का लाभ उठाना : भारत में कृषि भौगोलिक संकेत

भारत हमेशा ही कृषि सामग्री का निवल निर्यातक रहा है, वर्तमान वर्षों में इस क्षेत्र पर फोकस देने में वृद्धि देखी गई है। यह परिवर्तन **वर्ष 2018 की कृषि निर्यात नीति** से आया है, जिसका उद्देश्य **चावल, झींगा, चीनी, चाय, मसाले** आदि जैसी आधारभूत वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देना है। भारत के **526 पंजीकृत जीआईएस** में से 219 उत्पाद कृषि और खाद्य क्षेत्र से संबंधित है, जो देश के समृद्ध भौगोलिक कारकों के साक्षी है, **जिसमें जलवायु, मिट्टी और पारंपरिक खेती और खेती के तरीके** शामिल हैं। ये जीआई टैग, विभिन्न श्रेणियों को कवर करते हैं, जो न केवल कृषि उत्पादों का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि प्रत्येक भारतीय राज्य की भौगोलिक विविधता और विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को दर्शाते हुए कई अन्य खाद्य पदार्थों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। **महाराष्ट्र** राज्य में 26 जीआई टैग हैं, जो अल्फोंसो आमों जैसे उत्कृष्ट कृषि उत्पादों के उत्पादन में राज्य की विरासत को रेखांकित करते हैं। गौर से देखें तो, **कर्नाटक और तमिलनाडु** राज्य में 22 जीआई टैग हैं, जो खाद्य पदार्थों में उनकी प्रमुखता का प्रतिबिंब है, जिसमें कुर्ग अरेबिका कॉफी और कोडाईकनाल मलाई पूंडू जैसी विश्व प्रसिद्ध खाद्य वस्तुएं शामिल हैं। यह विविधता पूरे भारत में देखने को मिलती है, जिसमें **केरल और उत्तराखंड** जैसे राज्य भी शामिल हैं जिनके पास क्रमशः 20 और 16 जीआई टैग हैं, जो उनकी विशिष्ट क्षेत्रगत कृषि कौशल को दर्शाते हैं।

पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, अपने 12 और 11 जीआई टैग के साथ, कृषि विविधता और विशिष्टता दोनों में अपनी समृद्ध परंपरा को उजागर करते हैं। इस समृद्ध ताने-बाने में योगदान देने वाले अन्य राज्यों में **गोवा, ओडिशा और असम** शामिल हैं, जिनके क्रमशः 9, 9 और 7 जीआई टैग हैं, जो गोवा काजू से तेजपुर लिची तक उत्पादों की एक श्रृंखला प्रदर्शित करते हैं। **बिहार, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश** भी इस श्रेणी में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, प्रत्येक राज्य अपने विशिष्ट कृषि और खाद्य पदार्थ को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जीआई टैग की सुरक्षा के तहत लाते हैं। जीआई टैग एक प्रतिस्पर्धी वैश्विक बाजार में प्रामाणिकता और मौलिकता के संकेतक के रूप में कार्य करते हैं, जो **मान्यता और प्रीमियम मूल्य निर्धारण** के माध्यम से किसान समुदायों को सशक्त बनाते हैं और पारंपरिक कृषि-खेती और संबंधित कृषक समुदायों के निर्वाह के लिए महत्वपूर्ण है।

नागा मिर्चा से बासमती चावल तक: कृषि क्षेत्र में भौगोलिक संकेतों की सफलता

1. मुन्स्यारी राजमा (उत्तराखंड)

उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों की खनिज समृद्ध मिट्टी में उगाया जाने वाला मुन्स्यारी राजमा, न केवल खाने में स्वादिष्ट है, बल्कि घुलनशील फाइबर का स्रोत भी है। 1600 मीटर से 2700 मीटर के बीच की ऊंचाई पर होने वाली खेती के साथ, यह राजमा सांस्कृतिक और आर्थिक विविधता का महत्व रखता है। खेती की प्रक्रिया में स्थानीय महिलाओं की भागीदारी, सतत कृषि और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने वाली व्यापक पहलों के अनुरूप सशक्तीकरण की एक परत जोड़ती है।

2. अल्फोंसो (महाराष्ट्र)

महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में देवगढ़ तालुका सबसे अच्छे अल्फोंसो आमों के उत्पादन का पर्याय है, जिसे देवगढ़ अल्फोंसो के रूप में जाना जाता है। यह अपने स्वाद, फल सुगंध, मोटी लुग्दी, कम फाइबर और पतले छिल्के के लिए जाना जाता है, अल्फोंसो आम फरवरी से मई-जून तक तैयार होता है। इस आम का नाम पुर्तगाली खोजकर्ता अल्फोंसो डी एल्बुकर्क के नाम पर रखा गया है आम की इस किस्म को दुनिया के सबसे अच्छी किस्मों में से एक माना जाता है।

3. रतलामी सेव (मध्य प्रदेश)

रतलामी सेव, मध्य प्रदेश के रतलाम में उत्पन्न होने वाला एक नमकीन स्नैक, चने के बेसन, लौंग और मिर्च से तैयार किया जाता है। अपने अनोखे मसालेदार स्वाद, हल्के पीले रंग और रतलाम में मूल के लिए जाना जाने वाला यह स्नैक मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में एक प्रमुख स्नैक बन गया है। इसकी लोकप्रियता सिंगापुर, अमेरिका, चीन और यूके जैसे देशों को निर्यात के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैली हुई है।

4. तिरुपति लड्डू (आंध्र प्रदेश)

तिरुपति लड्डू की आंध्र प्रदेश के तिरुमला मंदिर में एक प्रसाद के रूप में वैश्विक पहचान है। इसकी विशिष्ट गुणवत्ता का श्रेय धल, घी और नट्स जैसे प्राकृतिक घटकों के उपयोग को जाता है, जिसमें कुशल कारीगरी भी शामिल है। पवित्रता का प्रतीक, यह लड्डू एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रतीक बन गया है.

5. नागा मिर्चा

राज्य के बागवानी और कृषि विभाग के आवेदन के आधार पर, नागा मिर्चा को 2008 में जीआई-टैग प्रदान किया गया था। यह मिर्च अद्वितीय है और स्कोविल हीट यूनिट्स के अनुसार दुनिया की पांच सबसे तीखी मिर्च में शुमार की जाती है। वर्ष 2021 में नागालैंड राज्य कृषि विपणन बोर्ड और एईपीडीए के प्रयासों से इसका निर्यात एक महत्वपूर्ण स्तर तक पहुंचने में सक्षम हुआ- इसे पहली बार लंदन में 250 किलोग्राम खेप के रूप में निर्यात किया गया था। इसके विकास ने इस मिर्च के साथ-साथ मिर्च की अन्य भारतीय किस्मों के लिए कई अंतरराष्ट्रीय बाजार खोले हैं।

6. कन्याकुमारी मट्टी केले

2021 में, मदुरै एग्रीबिजनेस इन्क्यूबेशन फोरम – बौद्धिक संपदा सुविधा केंद्र (एमएबीआईएफ -आईपीएफसी) ने मट्टी केले के जीआई टैग हेतु आवेदन दायर करने की प्रक्रिया को पूरा किया। इस किस्म के एक किलो केले अब 70 - 80 रुपए के बीच बेचे जाते हैं, जो पिछले वर्षों की तुलना में काफी अधिक है। यह संगठन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), भारत सरकार द्वारा समर्थित और वित्तपोषित है। इसके अलावा, एमएबीआईएफ ने तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित 38 पौधों की किस्मों, तमिलनाडु में 50 ट्रेडमार्क, 15 पेटेंट और 6 भौगोलिक संकेतों को दाखिल करने की सुविधा भी प्रदान की है। 6 जीआई में तूतीकोरिन मैकरून, ऑथूर पान के पत्ते, मदुरै मारीकोलुंधु (दावना), कुंबम अंगूर, विलाचेरी मिट्टी के खिलौने और कन्याकुमारी मट्टी केला शामिल हैं।

7. गिर केसर आम

जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय और गुजरात कृषि-उद्योग, जिन्होंने गिर अभयारण्य के आसपास उगाए जाने वाले केसर आमों के लिए जीआई-टैग के लिए आवेदन किया था, उन्हें गुजरात के जूनागढ़ और अमरेली जिलों में उगाए जाने वाले आमों के लिए जीआई टैग प्रदान कर दिया गया था। जीआई-टैग के कारण साधारण केसर आमों को 'गिर केसर आम' के रूप में बेचने से रोकने में सहायता हुई और दोनों जिलों के किसानों को अपनी उपज में अंतर करने और उचित मूल्य प्राप्त करने में काफी मदद हुई।

8. नागपुर संतरे

नागपुर संतरे की खेती महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र (नागपुर और अमरावती क्षेत्र) और मध्य प्रदेश के कुछ भाग में व्यापक रूप से की जाती है। विगत वर्षों से, नागपुर को संतरा उत्पादक क्लस्टर के रूप में विकसित करने के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं ताकि इस क्षेत्र में संतरे की खेती करने वाले किसानों की आय बढ़ाई जा सके और उन्हें बाजार तक पहुंच प्रदान की जा सके। महाराष्ट्र राज्य कृषि विभाग के अनुसार ~ नागपुर जिले में ~ 40 लाख हेक्टेयर भूमि संतरे की खेती के अधीन है। वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय अंतरराष्ट्रीय बाजार में इन संतरों के निर्यात की एक बड़ी संभावना देखता है। उदाहरण के लिए, संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) के तहत, खट्टे फलों और अन्य कृषि उत्पादों के निर्यात में वृद्धि की प्रवृत्ति देखने जा रही है क्योंकि द्विपक्षीय समझौता अब यूएई बाजार में भारतीय निर्यातकों की शुल्क-मुक्त पहुंच प्रदान करता है। इन्हें अन्य खाड़ी देशों और कनाडा, अमेरिका, जर्मनी और यूके को भी निर्यात किया जाता है।

9. बासमती चावल:

भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग ने बासमती चावल को भारत की निर्यात सफलता की कहानी में सबसे आगे लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत, बासमती चावल का प्रमुख उत्पादक और निर्यातक होने के नाते,

भारतीय उपमहाद्वीप के हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले उत्पादन और विविध किस्मों की प्रचुरता के कारण अपना प्रभुत्व रखता है। इस क्षेत्र की अनूठी कृषि जलवायु परिस्थितियां, स्थानीय कृषि पद्धतियों में निहित विशिष्ट कटाई और प्रसंस्करण विधियों के साथ, बासमती चावल को इसकी विशिष्ट सुगंध और स्वाद से भर देती हैं। परिणामस्वरूप, बासमती चावल, भारत के चावल निर्यात का एक बड़ा हिस्सा है। वित्त वर्ष 2022-23 में, बासमती चावल का निर्यात, गैर-बासमती चावल के कुल 177.92 लाख टन की तुलना में 45.61 लाख टन था।

विरासत का संरक्षण, उत्कृष्ट स्वाद: दार्जिलिंग चाय पर भौगोलिक संकेत का प्रभाव

दार्जिलिंग चाय का विशिष्ट स्वाद और असाधारण गुणवत्ता का श्रेय दार्जिलिंग पहाड़ियों की अनुकूल भू-कृषि-जलवायु परिस्थितियों, मिट्टी की विशिष्ट संरचना और पारंपरिक खेती तकनीकों को जाता है। इसकी 2,000 मीटर की ऊंचाई पर 87 बागानों के उत्पादन क्षेत्र को भारतीय चाय बोर्ड भौगोलिक संकेतक (जीआई) के संदर्भ में सावधानीपूर्वक अंकित करता है।

केन्या और नेपाल जैसे देशों से चाय को दार्जिलिंग के रूप में नकली लेबल किए जाने के उदाहरण कड़े कानूनी सुरक्षा उपायों की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। उपभोक्ताओं की धारणाएं दार्जिलिंग चाय से वास्तविक मूल्य को और उजागर करती हैं। सर्वेक्षणों के अनुसार, 32 प्रतिशत घरेलू उपभोक्ता दार्जिलिंग चाय की बहुत अधिक प्रशंसा करते हैं, 56 प्रतिशत की उच्च प्रशंसा है, और 12 प्रतिशत की मध्यम प्रशंसा है। इसके अलावा, भारत में घरेलू उपभोक्ता असम या डुआर्स चाय की तुलना में दार्जिलिंग चाय के लिए 25% से 300% अधिक कीमत का भुगतान करने को तैयार हैं। इन बढ़ी हुई कीमतों के बावजूद, सर्वेक्षण में शामिल 92% चाय उपभोक्ताओं ने दार्जिलिंग चाय के स्वाद, गुणवत्ता और प्रतिष्ठा के लिए अपनी प्राथमिकता के कारण अधिक भुगतान करने की इच्छा की पुष्टि की। दिलचस्प बात यह है कि उपभोक्ता विश्वास मुख्य रूप से "दार्जिलिंग" नाम और खुदरा विक्रेता की प्रतिष्ठा पर टिका हुआ है, जीआई लोगो या सत्यापन प्रक्रियाओं पर बहुत कम ध्यान दिया गया है।

माल का भौगोलिक उपदर्शन (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 के तहत आवेदन प्रक्रिया और भूमिका

जीआई टैग प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया में उत्पाद के अनूठे गुणों और विशेषताओं का **विस्तृत परीक्षण** शामिल होता है, जो प्रत्यक्ष रूप से इसकी भौगोलिक उत्पत्ति से संबंधित होते है। आवेदकों को उत्पाद की विशिष्टता और विशिष्ट क्षेत्र से उसके संबंध का **साक्ष्य देना होगा।** सरकारी एजेंसियां, जैसे कि **भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री**, जीआई आवेदनों के प्रसंस्करण और परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न कृषि बोर्ड और संगठन आवेदन प्रक्रिया के संदर्भ में किसानों की सहायता करने के लिए सहयोग करते हैं।

भौगोलिक संकेतकों को नियंत्रित करने वाले **कानूनी फ्रेमवर्क** में अंतरराष्ट्रीय समझौते और घरेलू कानून दोनों शामिल हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, **बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पहलुओं (ट्रिप्स) पर** समझौता जीआई सुरक्षा के लिए आधार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत के संदर्भ में**, माल का भौगोलिक उपदर्शन (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999** प्रमुख कानून है। ट्रिप्स के तहत भारत के दायित्वों का पालन करने के लिए अधिनियमित जीआई अधिनियम भौगोलिक संकेतकों के पंजीकरण और संरक्षण के लिए कानूनी रूपरेखा बनाता है। यह जीआई पंजीकरण प्राप्त करने की प्रक्रियाओं, **पंजीकृत मालिकों को दिए गए अधिकारों** और जीआई-संरक्षित उत्पादों के अनधिकृत उपयोग के लिए **दंड** की रूपरेखा तैयार करता है।

भौगोलिक संकेतकों में आने वाली चुनौतियां और सरकार के कृषि प्रयास

यद्पि सफलता की कहानियां व्यापक हैं, परंतु चुनौतियां भी बरकरार हैं। किसानों को, विशेषकर दूरदराज के क्षेत्रों में, जीआई पंजीकरण प्रक्रिया में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त, अनधिकृत उपयोग के खिलाफ जीआई अधिकारों का प्रवर्तन सुनिश्चित करना एक सतत चुनौती बनी हुई है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि **छोटे स्तर के किसानों** की, जिनके पास संसाधनों और जागरूकता की कमी है, जीआई पंजीकरण प्रक्रिया तक पहुंच आसानी से हो सकें। इस संबंध में, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने समावेशी विकास के संवर्धन और पूरे देश में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अग्रणी पहलों की एक श्रृंखला शुरू की है। ऐसी ही एक परिवर्तनकारी पहल **एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी)** योजना है, जो संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है। यह योजना प्रत्येक जिले से एक अनूठे **उत्पाद के चयन, ब्रांडिंग और संवर्धन** को अनिवार्य बनाती है, जो देश के हर कोने में व्यापक सामाजिक-आर्थिक उन्नति को बढ़ावा देती है। प्रत्येक जिले की विशिष्ट विशेषताओं को पहचानकर और उनका संवर्धन करके, ओडीओपी पहल न केवल स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करती है बल्कि जमीनी स्तर की उद्यमिता को भी पोषित करती है।

ओडीओपी योजना को लागू करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार की गई **उत्पाद कार्रवाई रिपोर्टें** विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के सहयोग से विकसित की गई हैं। ये रिपोर्टें भौगोलिक संकेतक (जीआई) वस्तुओं के लिए व्यापक कार्य योजनाओं को चित्रित करती हैं, जो आपूर्ति श्रृंखला में समस्याओं को चिह्नित करती हैं और उन्हें दूर करने के लिए रणनीतिक कार्यक्रम का प्रस्ताव उपलब्ध कराती हैं। निर्यात-आयात (एक्जिम) विश्लेषण और हितधारक फीडबैक को शामिल करते हुए, ये रिपोर्ट विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और स्वायत्त निकायों के लिए ठोस प्रगति हेतु एक रोडमैप प्रस्तुत करती हैं। इसके अलावा, **एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी)** योजना ने बाजार लिंकेज को मजबूत करने और जीआई वस्तुओं के लिए व्यापार के अवसरों को बढ़ाने के लिए **क्रेता-विक्रेता बैठकों (बीएसएम)** की सुविधा प्रदान की है। साथ ही, यह पहल कारीगरों और उत्पादकों के प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन के महत्व पर जोर देती है, जिससे वे अपनी प्रामाणिकता को बनाए रखते हुए अपने शिल्प को आधुनिक बनाने में सक्षम हो सकें। कौशल उन्नयन कार्यक्रम या क्षमता विकास पहल के तहत प्रत्येक कार्यक्रम/कार्यशाला में **25 से 75 दिनों** की अवधि के लिए जीआई-टैग उत्पादों के **20-40 अधिकृत उपयोगकर्ताओं के बैच** को शामिल किया जाता है। इन प्रयासों के साथ-साथ डीपीआईआईटी ने जीआई के क्षेत्र में **जागरूकता और क्षमता विकास** के लिए कई पहलें शुरू की हैं।

जागरूकता कार्यक्रमों और कौशल उन्नयन कार्यशालाओं के माध्यम से, डीपीआईआईटी का लक्ष्य जीआई-टैग उत्पादों के अधिकृत उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाना, विशेषज्ञता और नवप्रयोग को बढ़ावा देना है। **प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों और कृषि मेलों** जीआई उत्पादों को प्रदर्शित करने और नेटवर्किंग के अवसरों को सुविधाजनक बनाने के मार्ग के रूप में कार्य करते हैं। कार्यक्रम 5 से 15 दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं और आयोजक की क्षमता के अनुसार स्टॉलों की संख्या कम से कम 25 होती है जिन्हें डीपीआईआईटी द्वारा अनुमोदित किया जाता है। प्रति जीआई 2 अधिकृत उपयोगकर्ताओं को अनुमति दी जाती है और इसी अनुसार इन्हें एडजस्ट किया जाता है। इसके अतिरिक्त, डीपीआईआईटी जीआई उत्पादों की वैश्विक उपस्थिति को बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए, **प्रचार अभियानों, फैशन शो और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों** के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, डीपीआईआईटी जीआई अध्ययन और जीआई सुविधा केंद्रों की स्थापना के लिए सहायता उपलब्ध करता है, अनुसंधान पहल और परिचालन खर्चों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इन कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता 37.00 लाख रुपए प्रति जीआई सुविधा केंद्र से लेकर **अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए अधिकतम 75 लाख रुपए** तक है, जिसमें प्रदर्शनियों, कौशल उन्नयन और जीआई जागरूकता कार्यक्रमों जैसी विभिन्न गतिविधियों के लिए विशिष्ट राशि आबंटित की जाती है।

भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा माननीय केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में भौगोलिक संकेतकों (जीआई) को बढ़ावा देने और सुरक्षित रखने की अपनी प्रतिबद्धता के प्रति कृतसंकल्प है जिसके लिए परिवर्तनकारी पहलें लागू की गई है। वित्तीय सहायता, बाजार सुविधा और जागरूकता अभियानों के माध्यम से, सरकार ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जीआई-टैग उत्पादों के फलने-फूलने के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया है। भविष्य को देखते हुए, सरकार भारत के विविध जीआई-टैग कृषि उत्पादों की निरंतर सफलता और मान्यता सुनिश्चित करने के लिए नियामक फ्रेमवर्क को मजबूत करने और हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

विकास के कीर्तिमान गढ़ रहा उत्तर प्रदेश

- 6 एक्सप्रेस-वे संचालित और 7 निर्माणाधीन एक्सप्रेस-वे के साथ यूपी बना 'एक्सप्रेस-वे प्रदेश'.
- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अचीवर स्टेट.
- भारत के सबसे बड़े डेटा सेंटर केंद्रों के रूप में उभर रहा गौतमबुद्धनगर
- देश की कुल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में लगभग 60% का योगदान.
- बैंकों/वित्तीय संस्थानों से परियोजनाओं के लिए धन आकर्षित करने में नंबर एक राज्य. वित्त वर्ष 2013-14 में देश में यूपी की हिस्सेदारी मात्र 1.1% थी, जो वित्त वर्ष 2022-23 में 15 गुना की वृद्धि के साथ बढ़कर 16.2% हो गई.
- सबसे अधिक हवाई अड्डों वाला राज्य. 4 अंतर्राष्ट्रीय और 16 घरेलू हवाई अड्डे संचालित.
- देश का पहला अंतर्देशीय जलमार्ग यूपी में विकसित। वाराणसी से हल्दिया तक संचालित, प्रयागराज भी होगा शामिल.
- नोएडा के जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे का निर्माण प्रगति पर। यह एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा.
- वाराणसी में 100 एकड़ में भारत के पहले फ्रेट विलेज की स्थापना.
- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार, अप्रैल 2023 तक यूपी से 1,26,000 निवेशक जुड़े. देश में सर्वाधिक.
- अयोध्या धाम में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ानें शुरू.
- ऑपरेशन कायाकल्प के तहत 1.40 लाख स्कूलों का कायाकल्प.
- मेरठ को दिल्ली से जोड़ने वाली देश की पहली रैपिड रेल सेवा संचालित.
- 18.4% की हिस्सेदारी के साथ यूपी घरेलू पर्यटकों के लिए बना नंबर 1 गंतव्य. 2023 में 32 करोड़ से अधिक घरेलू पर्यटकों का प्रदेश में हुआ आगमन.

- 96 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों के संचालन के साथ यूपी देश का सबसे बड़ा एमएसएमई हब.
- 'स्कूल चलो' अभियान के तहत, सरकारी स्कूलों में नामांकित छात्रों की संख्या 2017 में 1.34 करोड़ से बढ़कर 2023 में 1.92 करोड़ हो गई.
- 17 नगर निगमों में सेफ सिटी योजना.
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में देश में पहले स्थान पर. 2.63 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित. इस योजना के तहत किसानों को अब तक 64,694 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान.
- देश में सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज यूपी में. 65 मेडिकल कॉलेज संचालित और 22 निर्माणाधीन.
- संचारी रोग नियंत्रण विशेष अभियान से एक्यूट इंसेफेलाटिस सिंड्रोम (एईएस) और जापानी एन्सेफलाइटिस (जेई) से मृत्यु दर में 98% तक की कमी. पूर्वांचल इंसेफेलाइटिस से मुक्त.
- 'स्वच्छ भारत मिशन' के तहत 2.61 करोड़ शौचालय बनाने और सभी 75 जिलों को ओडीएफ घोषित करने वाला पहला राज्य.
- भारत की पहली सार्वजनिक परिवहन रोप-वे प्रणाली वाराणसी में की जा रही विकसित.
- मनरेगा के क्रियान्वयन में देश में प्रथम. मनरेगा के तहत 190 करोड़ मानव दिवस सृजित. 4.85 करोड़ श्रमिकों को मिला रोजगार.
- अगले पांच वर्षों में 10 लाख परिवारों वाले 17 शहरों को 'सौर शहर' के रूप में विकसित का कार्य प्रगति पर.
- 30 टन की क्षमता वाले प्लास्टिक कचरे से ईंधन उत्पादन के लिए समर्पित पहले संयंत्र की स्थापना अयोध्या नगरी में. इस मामले में अयोध्या उत्तर भारत में बनेगी अग्रणी.
- ई-टेंडरिंग प्रणाली में यूपी शीर्ष स्थान पर.
- महिलाओं के खिलाफ अपराधों और पास्को अधिनियम के तहत सजा दिलाने की दर में यूपी देश में शीर्ष स्थान पर,
- पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) के तहत देश में अग्रणी. अब तक 16.23 लाख लाभार्थियों को 2127.11 करोड़ रुपये का ऋण वितरित.
- अयोध्या राज्य की पहली 'सोलर सिटी' के रूप में हो रही विकसित.
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी) में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर. राज्य में 55.50 लाख घरों का निर्माण. केंद्र ने 2023-24 के लिए यूपी को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-आर) के तहत 1.44 लाख अतिरिक्त आवास इकाइयों की दी मंजूरी.
- कौशल-विकास नीति लागू करने वाला पहला राज्य.
- ई-मार्केट प्लेस (जेम) के तहत सर्वाधिक खरीदारी करने वाला पहला राज्य.
- स्पोर्ट्स कैपिटल' के रूप में उभरा यूपी. खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, एशियन यूथ हैंडबॉल चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप और आईटीएफ मेन्स का आयोजन.
- एसोचैम द्वारा उत्तर प्रदेश 'कौशल विकास में सर्वश्रेष्ठ राज्य' के रूप में हुआ स मानित.
- अंतर्देशीय मत्स्य पालन में उत्कृष्टता हासिल करने वाले राज्यों की प्रतिष्ठित 'ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया- 2023% में यूपी को मिला सम्मान.
- ग्रेटर नोएडा में उत्तर भारत का पहला हाइपरस्केल डेटा सेंटर योट्टा डी 1 संचालित.

कोयला क्षेत्र में हुआ नया सवेरा

आत्म-निर्भरता हासिल करने के लिए कोयला क्षेत्र के तेजी से आगे बढ़ते कदम

भारत की प्रगति के गतिशील परिदृश्य में, कोयला क्षेत्र एक विशिष्ट स्तंभ के रूप में उभरता है, जो उस "विकसित भारत" के इंजन को ईंधन देता है, जिसका निर्माण हम करना चाहते हैं। देश के औद्योगिक विकास के ताने-बाने में जटिल रूप से बुनी गई एक समृद्ध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ, कोयला उद्योग ने आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने और बुनियादी ढांचे के विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे-जैसे हम संधारणीयता और ऊर्जा मांगों के बीच जटिल संतुलन बनाते हैं, समृद्ध और विकसित भारत को आकार देने में कोयला उद्योग के सूक्ष्म योगदान की सराहना करना अनिवार्य हो जाता है। यह कोयला क्षेत्र की जटिल पेचीदगियों पर प्रकाश डालता है, "विकसित भारत" पर इसके बहुमुखी प्रभाव और इसकी क्षमता का जिम्मेदारी से दोहन करने के लिए आगे बढ़ने के रास्ते की खोज करता है।

जैसे-जैसे भारत आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है, कोयला क्षेत्र न केवल आर्थिक रूप से बल्कि जिम्मेदार संसाधन उपयोग के संरक्षक के रूप में भी एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में उभर रहा है। वाणिज्यिक कोयला खनन, नीति सुधार, गैसीकरण प्रयासों और संधारणीय प्रथाओं के प्रति प्रतिबद्धता जैसी पहलों में स्पष्ट सर्वव्यापी कार्यनीति, दक्षता, जिम्मेदारी और लचीलेपन की दिशा में एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक है। भारत के कोयला क्षेत्र की परिवर्तनकारी यात्रा ऊर्जा मांगों को संबोधित करने से कहीं आगे तक फैली हुई है; यह एक संधारणीय और आत्मनिर्भर भविष्य की नींव रखता है। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में, इस बहुआयामी दृष्टिकोण में नीतिगत सुधार, उत्पादन वृद्धि, पर्यावरणीय प्रबंधन, लॉजिस्टिक संवर्द्धन और सामाजिक जिम्मेदारी शामिल है।

भारत की आर्थिक प्रगति और ऊर्जा मांग में वृद्धि

दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरते हुए, भारत तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। पिछले दशक में औद्योगिक विकास में वृद्धि ने ऊर्जा की मांग को बढ़ा दिया है, इस रूझान के निकट भविष्य में भी जारी रहने की आशा है। जैसे-जैसे भारत "आत्मनिर्भर भारत" को अपना रहा है, कोयला और खनन क्षेत्र संरचनात्मक सुधारों के माध्यम से देश को कोयला और खनिज उपलब्धता में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सक्षम कर रहा है।

वाणिज्यिक कोयला खनन: ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देना

वाणिज्यिक कोयला खनन भारत को कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक कदम है। वाणिज्यिक खनन के लिए वाणिज्यिक कोयला नीलामी प्रक्रिया ने ऊर्जा सुरक्षा की एक मजबूत नींव रखी है, जिससे घरेलू कोयला उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इसने बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के नए रास्ते खोले हैं, जिससे देश के कार्यबल को आवश्यक रूप से बढ़ावा मिला है। खनन परिचालन से लेकर सहायक उद्योगों तक, कोयला मूल्य श्रृंखला में सृजित रोजगार के अवसर आर्थिक विकास और सामाजिक उत्थान दोनों में योगदान देते हैं। उद्योग-अनुकूल नीतियों ने पूरे कोयला क्षेत्र को आगे बढ़ाया है, जिससे वर्ष 2022-23 में घरेलू कोयला उत्पादन में 14.77% की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि न केवल बढ़ती मांग को पूरा करती है बल्कि आयात निर्भरता को भी कम करती है, जो आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इसके साथ ही, वित्त वर्ष 2023 में घरेलू कोयला प्रेषण सराहनीय रूप से 877.36 मिलियन टन तक पहुंच गया, जो वित्त वर्ष 2014 से 53.3% की पर्याप्त वृद्धि दर्शाता है। ये उपलब्धियां मात्र आँकड़ों से अलग हैं, जो न केवल परिचालन उत्कृष्टता को दर्शाते हैं बल्कि कोयला क्षेत्र को देश के मुख्य क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में स्थापित करते हैं। यह मजबूत वृद्धि रूझान सरकार की कार्यनीतिक दृष्टि का प्रमाण है, जो आर्थिक लचीलापन लाने और भारत के ऊर्जा परिदृश्य में इसके महत्व को मजबूत करने में कोयला क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है।

वित्त वर्ष 24 के दौरान घरेलू उत्पादन में वृद्धि के परिणामस्वरूप, घरेलू कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए आयातित कोयले की मात्रा में पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि (अप्रैल-नवंबर 2022) की तुलना में अप्रैल-नवंबर 2023 के दौरान 44.30% की कमी आई है। जबकि कोकिंग और गैर-कोकिंग

श्री प्रल्हाद जोशी

माननीय कोयला, खान एवं संसदीय कार्य मंत्री

आज हमने कोयले की कहानी को बदलकर इसे भारत की विकास कहानी बना दिया है। कुल कोयला उत्पादन पहली बार एक अरब टन को पार करने की संभावना है। भारत का कोयला क्षेत्र देश की ऊर्जा सुरक्षा में लगातार योगदान दे रहा है और इस तरह हमारी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को और गति प्रदान कर रहा है। देश की बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए, आत्मनिर्भर कोयला क्षेत्र के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

दोनों सहित कोयले के आयात की कुल मात्रा पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में नवंबर, 2023 तक अपेक्षाकृत स्थिर रही और इसमें मूल्य के संदर्भ में 32.04% की उल्लेखनीय कमी आई। इस कमी के परिणामस्वरूप देश में कोयला आयात पर निर्भरता कम करने का संकेत देते हुए इस समय-सीमा के दौरान 11.56 बिलियन अमेरिकी डॉलर की पर्याप्त बचत हुई है।

वित्त वर्ष 2030 में घरेलू कोयला उत्पादन सालाना 6-7% तक बढ़कर लगभग 1.5 बिलियन टन तक पहुंचने की आशा है।

हरित कल के लिए कोयला लॉजिस्टिक्स को पुनर्परिभाषित करना

कोयला परिवहन में परिवर्तनकारी यात्रा शुरू करते हुए, कोयला मंत्रालय ने बढ़ती मांगों के बीच कोयला लॉजिस्टिक्स नीति, एकीकृत कोयला लॉजिस्टिक्स योजना और अग्रणी फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) परियोजनाओं जैसी दूरदर्शी पहल शुरू की है। इन प्रयासों का उद्देश्य लागत दक्षता, संधारणीय और लचीला लॉजिस्टिक अवसंरचना तैयार करना है। परिवहन चुनौतियों को संबोधित करते हुए, सरकार नई रेलवे लाइनों का निर्माण करने, रेलवे नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने, विस्तार करने और दीर्घकालिक उत्पादन अनुमानों के अनुरूप एफएमसी परियोजनाओं और रेलवे साइडिंग को प्राथमिकता देने की योजना बना रही है। इन निकासी अवसंरचनाओं की योजना देश के दीर्घकालिक उत्पादन अनुमान के अनुरूप बनाई गई है। एफएमसी परियोजनाओं में पारंपरिक सड़क से रेल-आधारित प्रणालियों की ओर कार्यनीतिक बदलाव वायु प्रदूषण को कम करने, यातायात संकुलन को कम करने और सड़क क्षति को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है।

इसके अलावा, पीएम गति शक्ति के अनुरूप, मंत्रालय ने मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी अंतराल का निपटान करने के लिए 15 रेल परियोजनाएं शुरू की हैं। इनमें से, पाँच परियोजनाएँ पहले ही शुरू हो चुकी हैं, जो संधारणीय प्रथाओं के साथ कोयला उत्पादन वृद्धि को सुसंगत बनाने के लिए सरकार की निष्ठा को प्रदर्शित करती हैं।

कोयला कंपनियों ने 24,000 करोड़ रुपये की लागत से 1040 मिलियन टन की क्षमता वाली कुल 103 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) परियोजनाएं शुरू की हैं। वर्तमान में, 291 मिलियन टन क्षमता वाली 31 एफएमसी परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी हैं। ऊर्जा की मांग बढ़ने के साथ, कोयले की खपत वर्ष 2030 तक 980 मिलियन टन से बढ़कर 1.5 बिलियन टन हो जाने का अनुमान है, जिसके लिए कुशल लॉजिस्टिक्स की आवश्यकता होगी। मंत्रालय का लक्ष्य वित्त वर्ष 2029-30 तक कोयला परिवहन में रेल के शेयर को 75% से अधिक तक बढ़ाना है।

इन उद्देश्यों का समर्थन करने के लिए, रेल मंत्रालय व्यापक ऊर्जा कॉरिडोर परियोजना का प्रस्ताव करता है, जिसमें नई रेल लाइनों का निर्माण, उच्च घनत्व नेटवर्क सहित मौजूदा रेलवे लाइनों की क्षमता वृद्धि और बंदरगाहों तक रेल कनेक्टिविटी शामिल है। झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कुल 8 रेलवे परियोजनाओं की योजना बनाई गई है और इन्हें जमा आधार या संयुक्त उद्यम के आधार पर कोयला कंपनियों द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। इनमें से चार परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, भविष्य की कोयला निकासी मांग को पूरा करने के लिए कई महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं की पहचान की गई है।

रेल-समुद्र-रेल मार्ग

संधारणीय कोयला परिवहन के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप, मंत्रालय ने जलमार्ग परिवहन में कदम रखा है, कोयले के लिए रेल-समुद्र-रेल परिवहन शुरू किया है और एनडब्ल्यू-5 अंतर्देशीय जलमार्ग नेटवर्क का विस्तार किया है। रेल-समुद्र-रेल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए कोयला मंत्रालय की पहल अत्यधिक सफल साबित हो रही है, पिछले चार वर्षों में कोयले की तटीय शिपिंग में 125% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।

परिचालन में संधारणीयता सुनिश्चित करने के लिए कोयला/लिग्नाइट सीपीएसई का विविधीकरण

कोयला मंत्रालय सक्रिय रूप से सीपीएसई के भीतर व्यापक विविधीकरण को बढ़ावा दे रहा है, पिट-हेड टीपीपी, सौर ऊर्जा संयंत्र, कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण संयंत्र, महत्वपूर्ण खनिज अन्वेषण की स्थापना कर रहा है। लागत प्रभावी पिटहेड तापीय विद्युत संयंत्रों के लिए कोयला रहित भूमि के उपयोग पर जोर देते हुए, मंत्रालय के निर्देश का उद्देश्य भविष्य में कोयला अधिशेष की आशा करते हुए सीआईएल और एनएलसीआईएल दोनों के लिए संधारणीय संचालन को सुरक्षित करना है। इस कार्यनीति को लागू करते हुए, ऊर्जा मंत्रालय भविष्य की जरूरतों के लिए विद्युत उत्पादन के लिए लागत प्रभावी और समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करते हुए, तापीय विद्युत संयंत्रों के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के निर्माण को अनिवार्य करता है।

ई-नीलामी और अन्य पहलों के लिए सिंगल विंडो

वर्ष 2022 में अनुमोदित कोयले की ई-नीलामी के लिए सिंगल विंडो की शुरूआत का उद्देश्य कोयला बाजार को सुव्यवस्थित करना, बाधाओं को दूर करना और घरेलू कोयले की मांग को बढ़ाना है। अन्य पहलें जैसे कि खान योजनाओं और सिंगल विंडो के लिए दिशानिर्देश, और राजस्व-शेयरिंग मॉडल पर रद्द की गई खानों को फिर से खोलना, संसाधनों के इष्टतम उपयोग के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। इसके अतिरिक्त, कोयला क्षेत्र में कई अन्य सुधार शुरू किए गए, जिनमें तृतीय पक्ष की गुणवत्ता जांच और स्वचालित मार्ग के तहत कोयला खनन में 100% एफडीआई की अनुमति शामिल है।

पीपीपी- माइन डेवलपर सह ऑपरेटर (एमडीओ) की शुरूआत

सीआईएल ने घरेलू कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से खुली वैश्विक निविदाओं के माध्यम से कोयला खानों के लिए कार्यनीतिक रूप से प्रतिष्ठित एमडीओ को सूचीबद्ध किया है। इस क्षेत्र में एमडीओ की भागीदारी का आने वाले वर्षों में और विस्तार होने का अनुमान है, जो भारत के कोयला संसाधनों के संधारणीय विकास के लिए एक सकारात्मक रूझान को दर्शाता है।

परित्यक्त खानों में मौजूदा संसाधनों के उपयोग के लिए एक राजस्व शेयरिंग कार्य-तंत्र संधारणीय विकास के लिए महत्वपूर्ण है। 34 चिन्हित खानों के साथ यह दृष्टिकोण क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए संसाधनों के उत्तरदायित्व पूर्ण दोहन को बढ़ावा देता है, राजस्व का समान वितरण सुनिश्चित करता है।

मेक इन इंडिया कार्य योजना

आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने और स्थानीय उत्पादन को बढाने पर जोर देते हुए कोयला मंत्रालय कोयला खनन क्षेत्र के भीतर स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। इस पहल में सबसे आगे सीआईएल है, जो सक्रिय रूप से अत्याधुनिक उच्च क्षमता वाले

NLCIL - 20 MW Solar Power Project at Andaman & Nicobar Islands.

एचईएमएम और उन्नत संधारणीय खनिकों का अधिग्रहण कर रही है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व- मानवता की सेवा

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा समर्थित 'सुशासन' लोकाचार के अनुरूप, कोयला मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रमों ने अपने सीएसआर व्यय में 51.43% की उल्लेखनीय वृद्धि की है, जो वित्त वर्ष 2014-15 में 360.5 करोड़ रुपये की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 में 546.04 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

कोयला गैसीकरण: संधारणीय ऊर्जा के लिए एक दृष्टिकोण

ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में कदम रखते हुए, कोयला गैसीकरण एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण की पेशकश करते हुए पारंपरिक तरीकों से आगे निकल जाता है। राष्ट्र प्राकृतिक गैस, मेथनॉल, अमोनिया, यूरिया और अन्य महत्वपूर्ण उत्पादों के आयात पर निर्भरता कम करके पर्यावरणीय संधारणीयता में उल्लेखनीय प्रगति करने के लिए तैयार है। वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य कार्बन फुट प्रिंट को कम करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। गैसीकरण में उपयोग किए जाने वाले कोयले के लिए राजस्व शेयर में 50% छूट की कोयला मंत्रालय की पेशकश, एक अलग नीलामी विंडो के साथ मिलकर, कोयला क्षेत्र के ढांचे में पर्यावरणीय विचारों को एकीकृत करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। यह दृष्टिकोण स्वच्छ और हरित ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन के भारत के व्यापक लक्ष्य के साथ सहजता से मेल खाता है। हाल ही में मंत्रिमंडल की मंजूरी ने कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए 8,500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक व्यापक योजना का मार्ग प्रशस्त किया है। मंत्रिमंडल ने सीआईएल और गेल के संयुक्त उद्यम के माध्यम से ईसीएल कमांड क्षेत्र में कोयला-से-एसएनजी परियोजना और सीआईएल और बीएचईएल के संयुक्त उद्यम के माध्यम से एमसीएल कमांड क्षेत्र में कोयला-से-अमोनियम नाइट्रेट परियोजना की स्थापना के लिए इक्विटी निवेश के प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी है।

संधारणीय विकास और हरित पहलें

देश की बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को बनाए रखने के मध्य एक नाजुक संतुलन बनाते हुए, कोयला क्षेत्र संधारणीय वनीकरण और जैव-पुनर्ग्रहण के लिए प्रगतिशील कार्यनीतियों को अपनाने में अग्रणी भूमिका निभाता है। व्यापक जैव-पुनर्ग्रहण और वनीकरण प्रयासों का उद्देश्य कार्बन सिंक और हरित आवरण दोनों को मजबूत करना है। पिछले 10 वर्षों में, कोयला पीएसयू ने 42.3 मिलियन प्रभावशाली पौधे लगाकर लगभग 18,849 हेक्टेयर भूमि को हरित आवरण के अंतर्गत लाने में सफलता हासिल की है। यह अग्रणी पहल जिम्मेदार और पर्यावरण अनुकूल संधारणीय कोयला खनन प्रथाओं के प्रति कोयला क्षेत्र की अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

इको-पार्क और खान पर्यटन

खनन क्षेत्र, कोयला भंडार की समाप्ति के बाद, इको-पार्क, जल क्रीड़ा हेतु स्थल, भूमिगत पर्यटन, गोल्फ कोर्स, मनोरंजक स्थल, साहसिक गतिविधियाँ और पक्षी देखने के माध्यम से पर्यटन विकास के लिए अच्छी संभावना पेश करते है। पिछले 9 वर्षों में, कोयला/लिग्नाइट पीएसयू ने खान बंद करने की संधारणीय प्रथाओं का उपयोग करके 230 हेक्टेयर से अधिक भूमि को कवर करते हुए 25 इको-पार्क में बदल दिया है। इनमें से सात पार्कों को स्थानीय पर्यटन सर्किट में एकीकृत किया गया है। ये खनन स्थल अब स्थिर, पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय और सौंदर्यात्मक रूप से अत्यंत सुंदर स्थल प्रस्तुत करते हैं। कोयला/लिग्नाइट पीएसयू ने अब तक 30 इको-पार्कों/खान पर्यटन स्थलों का निर्माण किया है। इस वर्ष, इन पीएसयू ने 6 और इको-पार्कों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा है।

खान जल का लाभकारी उपयोग

तीव्र से शहरीकरण और औद्योगीकरण के साथ-साथ जनसंख्या में वृद्धि ने उपलब्ध जल संसाधनों पर गंभीर दबाव डाला है। कोयला/लिग्नाइट पीएसयू खनन क्षेत्रों में और उसके आसपास पानी की समस्या का समाधान करने के लिए अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने 2018 से पिछले चार वर्षों में सामुदायिक उद्देश्यों के लिए लगभग 16,012 लाख किलो लीटर (एलकेएल) अवशोधित उपचारित खान जल की आपूर्ति की है, जिससे प्रति वर्ष 9 राज्यों के 981 गांवों में 17.7 लाख से अधिक लोगों को लाभ हुआ है और प्रति वर्ष 173,000 एकड़ कृषि भूमि की सिंचाई क्षमता भी पैदा हुई है। कोल इंडिया लिमिटेड और अन्य पीएसयू ने सामुदायिक उपयोग - पीने के साथ-साथ सिंचाई प्रयोजनों के लिए खान जल के लाभकारी उपयोग के लिए 4250 एलकेएल का लक्ष्य निर्धारित किया है।

नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना

कोयला कंपनियां विशेष रूप से कुछ पुनः प्राप्त खनन क्षेत्रों में छत पर स्थापित सौर और जमीन पर स्थापित सौर परियोजनाओं दोनों पर कार्य कर रही हैं। मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार, कोयला/लिग्नाइट पीएसयू ने लगभग 1696.36 मेगावाट की सौर क्षमता और 51 मेगावाट की पवन चक्कियाँ स्थापित की हैं। वित्त वर्ष 26 तक 5560 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता स्थापित करने की योजना है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ओजस्वी नेतृत्व के मार्गदर्शन में भारत का कोयला क्षेत्र व्यापक और कार्यनीतिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। उत्पादन, पर्यावरण देखभाल, लॉजिस्टिक्स और सामाजिक उत्तरदायित्व तक फैला बहुआयामी दृष्टिकोण, आत्मनिर्भरता की दिशा में एक आदर्श बदलाव का प्रतीक है। जैसा कि भारत ने 'आत्मनिर्भर भारत' का अपना लक्ष्य जारी रखा है, कोयला क्षेत्र दक्षता, उत्तरदायित्व और लचीलेपन की दृष्टि से प्रेरित होकर देश की प्रगति में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में खड़ा है। यह परिवर्तनकारी यात्रा कोयला और खनन उद्योग में एक स्थायी और आत्मनिर्भर भविष्य के लिए मंच तैयार करती है।

इस परिवर्तनकारी यात्रा में, प्रत्येक नीति सुधार, प्रत्येक टन कोयले का उत्पादन, और प्रत्येक नवीन पहल न केवल एक उद्योग बल्कि संधारणीयता और आत्मनिर्भरता की विरासत को आकार देने में योगदान देती है। जैसे-जैसे कोयला क्षेत्र स्वच्छ, हरित और अधिक लचीले भविष्य की दृष्टि से विकसित हो रहा है, यह एक संतुलित और संधारणीय ऊर्जा परिदृश्य की दिशा में भारत की यात्रा में प्रगति का प्रतीक बना हुआ है।

प्रतिरक्षा

डीआरडीओ

डीआरडीओ के सामने वजूद का संकट

विजयराघवन समिति ने डीआरडीओ को फिर से पटरी पर लाने के लिए अपनी रिपोर्ट में संरचनात्मक, परिचालन और मानव संसाधन के स्तर पर कई सुधार सुझाए हैं. लेकिन कुछ सुझावों से असहमत वैज्ञानिकों का एक वर्ग इसके विरोध में उतर आया है

प्रदीप आर. सागर

इंजन रूम
बेंगलूरू में डीआरडीओ की यंग साइंटिस्ट्स लैब के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी

रिष्ठ रक्षा वैज्ञानिकों का एक समूह के. विजयराघवन की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की सूरत बदलने के प्रयासों से नाखुश है. इस तथ्य में कोई दोराय नहीं है कि देश में रक्षा अनुसंधान से जुड़ा प्रमुख संगठन कुछ व्यवस्थागत खामियों से घिरा है, जिसका नतीजा परियोजनाओं में अत्यधिक देरी और लागत बेतहाशा बढ़ने के तौर पर सामने आता है.

हालांकि, अग्नि तथा प्रलय मिसाइलें, हल्का लड़ाकू विमान (एलसीए) तेजस और अर्जुन टैंक के विकास जैसी महत्वपूर्ण सफलताएं हमारे सामने हैं, लेकिन विलंबित परियोजनाओं की भी सूची अच्छी-खासी लंबी है, जिसमें एलसीए मार्क-2 और एलसीए नेवी एयरक्राफ्ट, एयरो इंजन कावेरी और तापस बीएच-201 ड्रोन प्रमुख हैं. फरवरी 2023 में रक्षा मंत्रालय ने संसद में जानकारी दी कि 'मिशन मोड प्रोजेक्ट' में शुमार उच्च प्राथमिकता वाली 55 परियोजनाओं में से 23 निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं. ऐसा माना जा रहा कि करीब 50 प्रयोगशालाओं और 30,000 से ज्यादा कर्मचारी क्षमता वाले इस संगठन ने रक्षा अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करना बंद कर दिया है, और खुद को अन्य क्षेत्रों तक विस्तारित कर बहुत सारी परियोजनाएं अपने हाथ में ले ली हैं. सरकार चाहती है कि डीआरडीओ में सुधारों को लागू करके रक्षा उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहल के जरिये आयात पर देश की अत्यधिक निर्भरता घटाई जाए. सरकार रक्षा निर्यात के मोर्चे पर भी बड़ा बदलाव चाहती है जिसे 2025 तक 35,000 करोड़ रुपए पर पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है.

कमान और

मौजूदा

रक्षा मंत्रालय

डीआरडीओ चेयरमैन और सचिव, आरऐंडडी विभाग, रक्षा मंत्रालय

डीआरडीओ | आरऐंडडी, रक्षा मंत्रा.

परियोजना में बड़ी देरी और लागत में वृद्धिः क्रूज मिसाइलों, टॉरपीडो डिकॉय सिस्टम, परमाणु रक्षा प्रौद्योगिकी जैसी 55 उच्च प्राथमिकता वाली 'मिशन मोड' परियोजनाओं में 23 निर्धारित समय से पीछे हैं. मुख्य वजहः अन्य क्षेत्रों में भागीदारी, कई परियोजनाएं

पूर्व में ए.पी.जे. अब्दुल कलाम समिति (1992), पी. रामाराव समिति (2008) और वी. रामगोपाल राव समिति (2020) जैसी कई उच्चस्तरीय समितियां भी डीआरडीओ को अधिक जवाबदेह और पेशेवर बनाने के उपाय सुझाकर स्थितियां सुधारने के प्रयास कर चुकी हैं. इसी क्रम में अगस्त 2023 में नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से गठित पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार विजयराघवन की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति को भविष्य की प्रौद्योगिकी के अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करने और स्वदेशी रक्षा उत्पादन को गति देने के लिए अकादमिक/स्टार्ट-अप और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के उपाय सुझाने का जिम्मा सौंपा गया.

रिपोर्ट नवोन्वेषी अनुसंधान की मांग करती है जहां सेना को अधिक भूमिका निभानी है. डीआरडीओ पीएमओ की निगरानी में होगा

विजयराघवन समिति ने अपनी रिपोर्ट 'रिडिफाइनिंग डिफेंस रिसर्च ऐंड डेवलपमेंट' रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपी. समिति ने संरचनात्मक स्तर पर जिन बदलावों की सिफारिश की है, उनमें कुछ ने डीआरडीओ के वरिष्ठ वैज्ञानिकों के एक समूह को नाराज कर दिया. वैज्ञानिकों ने राजनाथ सिंह को भेजे जवाब में असहमति जताते हुए कुछ अनुशंसित कदमों की व्यवहार्यता पर संदेह जताया है. यही नहीं, शीर्ष रक्षा वैज्ञानिकों के एक समूह ने तो रिपोर्ट पर अपनी बात रखने के लिए कथित तौर पर प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) तक से समय मांगा है, ताकि वह एकदम शीर्ष स्तर पर यह मुद्दा उठा सके.

रिपोर्ट पर वैसे तो कोई रार नहीं है, जिसका व्यापक उद्देश्य संगठन की खामियां दूर करना और अत्याधुनिक परियोजनाओं में तेजी के साथ इसे एक कुशल और चुस्त-दुरुस्त अनुसंधान एवं विकास संगठन बनाना है. आपत्ति इन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए अपनाए जाने वाले प्रस्तावित तरीकों को लेकर जरूर है. समिति ने जो सुझाव दिए हैं, उनमें दक्षता बढ़ाने के लिए विभिन्न डीआरडीओ प्रयोगशालाओं के विलय को डीआरडीओ वैज्ञानिकों ने अपनी मंजूरी दे दी है. लेकिन कुछ अन्य सुझावों का रक्षा वैज्ञानिक बिरादरी विरोध कर रही है.

विवाद के मुद्दे

डीआरडीओ को पीएमओ के दायरे में लाने का सुझाव विवाद के प्रमुख मुद्दों में शामिल है. फिर, समिति का मानना है कि डीआरडीओ रक्षा परियोजनाओं को लंबे समय तक खींचता है जिससे इनमें देरी के अलावा संसाधनों की काफी बर्बादी होती है. इसलिए उसका मानना है कि डीआरडीओ के टेक्नोलॉजीज के विकास में सशस्त्र बलों के दखल को बढ़ाया जाए. भर्ती को लेकर भी समिति के सुझाए तरीकों पर मतभेद सामने आए हैं. समिति सीधी भर्ती की मौजूदा व्यवस्था के बजाए कैंपस साक्षात्कार के जरिये भर्ती के पक्ष में है. लेकिन जिस मुद्दे पर वैज्ञानिक सबसे ज्यादा नाखुश हैं, वह यह कि रिपोर्ट में निजी रक्षा क्षेत्र की भूमिका को बहुत ज्यादा बढ़ाने पर खास जोर दिया गया है.

रिपोर्ट के गोपनीय श्रेणी की होने के मद्देनजर रक्षा मंत्रालय ने वैज्ञानिकों का पत्र मिलने के बाद इस पर सार्वजनिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. माना जा रहा है कि मंत्रालय सभी हितधारकों के साथ बात करेगा, सभी मुद्दों के समाधान का प्रयास करेगा और फिर उन्हें पीएमओ के समक्ष रखेगा. एक बार पीएमओ से समिति की सिफारिशें मंजूर होने के बाद रक्षा मंत्रालय और डीआरडीओ के पास उन पर अमल शुरू करने के लिए 90 दिन की समयसीमा होगी. नई दिल्ली स्थित डीआरडीओ मुख्यालय के गलियारों में फिलहाल यही सुगबुगाहट चल रही है कि निश्चित

नियंत्रण में बदलाव

डीआरडीओ की भूमिका अनुसंधान एवं विकास तक सीमित रहेगी. स्टार्ट-अप, शैक्षणिक संस्थान भी यह काम करेंगे. उत्पादन/आगे का काम निजी रक्षा उद्योग/पीएसयू को दिया जाएगा

समयसीमा में बदलावों को लागू करना कैसे मुमकिन होगा. कई वैज्ञानिकों का मानना है कि 66 साल पुराने संस्थान को महीनों में बदलकर रख देना आसान काम नहीं होगा.

समिति में विजयराघवन के अलावा पूर्व सेना उपप्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सुब्रत साहा, पूर्व नौसेना उपप्रमुख वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमाडे, पूर्व चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड स्टाफ एयर मार्शल बी.आर. कृष्णा, मनोहर परींकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज ऐंड एनालिसिस के महानिदेशक सुजान आर. चिनॉय, आइआइटी कानपुर में प्रोफेसर मणींद्र अग्रवाल, सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के अध्यक्ष एस.पी. शुक्ला, लार्सन ऐंड टुब्रो डिफेंस के जे.डी. पाटिल, इसरो के जाने-माने वैज्ञानिक एस. उन्नीकृष्णन नायर और रक्षा मंत्रालय में वित्तीय सलाहकार रसिका चौबे शामिल हैं.

डीआरडीओ के पूर्व वैज्ञानिक रवि गुप्ता समिति के सुझावों पर संशय जताते हैं. उन्होंने *इंडिया टुडे* से कहा, ''डीआरडीओ के पुनर्गठन पर सुझाव देने के लिए समितियों का नेतृत्व ऐसे बाहरी लोगों ने किया, जिन्हें रक्षा अनुसंधान और डीआरडीओ के कामकाज के बारे में कोई जानकारी नहीं है. समितियों ने नतीजों का ठीक से अनुमान लगाए बिना ही सुझाव दे डाले. किसी संगठन को बनाने में दशकों लगते हैं लेकिन उसे नष्ट करने में देर नहीं लगती.'' बजट अनुमान 2023-24 में डीआरडीओ का बजट 23,264 करोड़ रुपए है, और करीब 900 परियोजनाएं विकास के विभिन्न चरणों में हैं.

समिति के सुझाव

विजयराघवन समिति ने विशिष्ट रक्षा प्रौद्योगिकियों के लिए उपयुक्त खिलाड़ी तलाशने में रक्षा प्रौद्योगिकी परिषद (डीटीसी) की प्रभावी भूमिका की वकालत की, जिसके अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री हों और सदस्यों में रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शामिल हों. डीटीसी के नजरिये में विविधता लाने के लिए इसमें शिक्षा और उद्योग जगत के दो-दो सदस्य शामिल करने का भी प्रस्ताव है. यह एक तरह से अहम रणनीतिक परियोजनाओं में सीधी भागीदारी के जरिये रक्षा अनुसंधान में पीएमओ के दखल का प्रतीक है. इसका एक मतलब यह है कि डीआरडीओ सीधे तौर पर पीएमओ की निगरानी में होगा. समिति ने शैक्षणिक और स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र में रक्षा अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय के तहत एक अलग विभाग—रक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार विभाग (डीडीएसटीआइ)—बनाने का भी सुझाव दिया है. यह डीटीसी सचिवालय के तौर पर काम करेगा. इसके अलावा, डीटीसी के तहत एक उच्चाधिकार समिति की सिफारिश की गई है, जिसकी सह-अध्यक्षता चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) और पीएम के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार करेंगे. समिति ने रक्षा मंत्रालय में सचिव, अनुसंधान और विकास का पद भी अलग करने का सुझाव दिया है. अभी डीआरडीओ के अध्यक्ष ही इस पद की जिम्मेदारी संभालते हैं. इसलिए, ये संरचनात्मक बदलाव डीआरडीओ की व्यापक रणनीतिक स्वायत्तता को खत्म होने का संकेत देते हैं.

डीआरडीओ की भूमिका अनुसंधान और विकास तक सीमित होगी, और मौजूदा स्थिति के विपरीत वह प्रोटोटाइप या प्रौद्योगिकी प्रदर्शकों को विकसित नहीं कर सकेगा. रक्षा उत्पादन और आगे उसके विकास का जिम्मा चयनित निजी उद्योग और/या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सौंपा जाना है. समिति चाहती है कि डीआरडीओ की 41 प्रयोगशालाओं का पुनर्गठन कर इन्हें 10 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में तब्दील कर दिया जाए—बेंगलूरू और हैदराबाद में दो-दो और बाकी दिल्ली, पुणे, देहरादून, चेन्नै, विशाखापत्तनम और चंडीगढ़ में.

रक्षा वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा आपत्ति निजी रक्षा उद्योग, स्टार्ट-अप और शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी को खास अहमियत दिए जाने पर है. समिति ने 10 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के अलावा पांच राष्ट्रीय परीक्षण केंद्रों की स्थापना का प्रस्ताव रखा है, जहां निजी क्षेत्र अपनी नव विकसित हथियार प्रणालियों का परीक्षण कर सकें. इस तरह सरकारी संपत्तियों के इस्तेमाल का लाइसेंस मिलने से निजी उद्योग को भूमि, मशीनरी अथवा अन्य सहायक बुनियादी ढांचे में निवेश की जरूरत नहीं पड़ेगी. समिति की रिपोर्ट में शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में रक्षा तकनीक केंद्रों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर रक्षा प्रौद्योगिकी रोडमैप स्थापित करने की भी सलाह दी गई है.

अंतरिम बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि निजी रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कोष स्थापित करने की योजना है. इसका उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में 'डीप टेक' यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स जैसी

मशीनी चिड़िया डीआरडीओ निर्मित तापस बीएच-201 ड्रोन. 13 साल और करीब 1,800 करोड़ रुपए के खर्च के बाद भी यह उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा

रक्षा अनुसंधान और विकास में भारी बदलाव

रक्षा अनुसंधान और विकास के फंड पर अभी तक इसका कब्जा है →

डीआरडीओ वैज्ञानिकों की अब तक कम जवाबदेही →

डीआरडीओ में 7,500 वैज्ञानिक हैं, करीब 10,000 अनुसंधान और तकनीकी कर्मचारी; 12,500 प्रशासनिक, सहायक कर्मचारी. डीआरडीओ स्टाफ की सीधी भर्ती. →

कुछ विशिष्ट कार्य ही निजी क्षेत्र को सौंपे जाते हैं जिनकी डीआरडीओ सख्ती से निगरानी करता है, निजी क्षेत्र की अन्य कोई भूमिका नहीं →

“डीआरडीओ के पुनर्गठन पर सुझाव देने वाली समितियों का नेतृत्व ऐसे बाहरी लोगों ने किया, जिन्हें रक्षा अनुसंधान और डीआरडीओ के कामकाज के बारे में कोई जानकारी नहीं है”

रवि गुप्ता, *पूर्व डीआरडीओ वैज्ञानिक*

के. विजयराघवन समिति की रिपोर्ट ने डीआरडीओ के संगठन और कार्यप्रणाली में व्यापक बदलावों का सुझाव दिया है. मौजूदा स्थिति की तुलना में ये व्यापक प्रस्ताव हैं

41 डीआरडीओ लैबों का 10 राष्ट्रीय लैबों में पुनर्गठन; रक्षा प्रौद्योगिकी रोडमैप तैयार करना, शैक्षणिक संस्थानों में रक्षा तकनीक केंद्र

सख्त प्रदर्शन जवाबदेही. पिछले 10 साल के काम की गहन समीक्षा, अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वालों को समयपूर्व सेवानिवृत्ति के लिए चिह्नित किया जा सकता है

3-5 वर्षों के लिए परियोजना-आधारित नियुक्ति, जिसके बाद 25 फीसद नियमित किए जाएंगे. प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए कॉलेजों/विश्वविद्यालयों से कैंपस भर्ती पर जोर

निजी उद्योग, स्टार्ट-अप, शिक्षा जगत को डीप टेक विकसित करने के लिए ब्याजमुक्त वित्तपोषण के 1 लाख करोड़ रु. की राशि के इस्तेमाल की खातिर प्रोत्साहन

उन्नत प्रौद्योगिकियों के प्रयोग को बढ़ावा देना है. इसके तहत दीर्घकालिक ब्याज-मुक्त वित्तपोषण के लिए एक लाख करोड़ रुपए का एक बड़ा कोष बनाया जाना है. इसके पीछे उद्देश्य यह है कि स्टार्ट-अप और निजी उद्योग को परीक्षण केंद्रों और सत्यापन सुविधाओं के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया जाए, उन्हें सेना का मार्गदर्शन मिल पाए और हथियार प्रणालियों के विकास के लिए ऋण मिलना सुनिश्चित हो सके.

अभी तक रक्षा अनुसंधान निधि में डीआरडीओ वैज्ञानिकों की पूरी हिस्सेदारी रहती थी, इसलिए यह समझा जा सकता है कि डीआरडीओ वैज्ञानिक इससे नाखुश क्यों हैं. डीआरडीओ के एक शीर्ष वैज्ञानिक का कहना है, ''समिति ने अनुसंधान एवं विकास की बारीकियों पर ध्यान दिए बिना बस मनमाने ढंग से सिफारिश कर दी है. डीआरडीओ ने एक विशेष प्रणाली विकसित करने में वर्षों समय लगाया है और आप इसे रातोरात किसी निजी कंपनी को नहीं सौंप सकते.''

समिति ने दूसरा बड़ा बदलाव डीआरडीओ की भर्ती रणनीति को लेकर सुझाया है. सीधी भर्ती की नीति के बजाए, समिति चाहती है कि डीआरडीओ कॉलेजों-विश्वविद्यालयों से कैंपस भर्ती की सक्रिय रणनीति अपनाए, ताकि नई और होनहार प्रतिभाओं को आकृष्ट करके निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा की जा सके. समिति का मानना है कि अभी अमूमन निजी क्षेत्र में अच्छी नौकरियां पाने में नाकाम लोग ही अंतिम उपाय के तौर पर डीआरडीओ में आने का विकल्प चुनते हैं.

ज्यादा जवाबदेही

विजयराघवन समिति का कहना है कि डीआरडीओ परियोजनाओं में करीब 60 फीसद देरी आवश्यक प्रौद्योगिकी उपलब्ध न होने जैसे आंतरिक मुद्दों के कारण होती है, जबकि 17-18 फीसद सशस्त्र बलों की खास जरूरतें और लक्ष्य लगातार बदलने की वजह से होती है. कुछ परियोजनाओं में देरी के लिए नौकरशाहों की लालफीताशाही भी जिम्मेदार होती है. अब, जब सभी मौजूदा परियोजनाओं की समीक्षा की जा रही है, केवल उन्हीं परियोजनाओं के बचे रहने की उम्मीद है जो व्यावहारिक होंगी. डीआरडीओ मुख्यालय ने भी अपनी प्रयोगशालाओं से कहा है कि उन परियोजनाओं को जल्द पूरा करें जो अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं.

डीआरडीओ की जनशक्ति का सही प्रबंधन भी एक अहम पहलू है, जिसमें करीब 7,500 वैज्ञानिक, 10,000 रक्षा अनुसंधान और तकनीकी कर्मचारी तथा 12,500 प्रशासनिक और अन्य सहायक कर्मचारी शामिल हैं. साथ ही, करीब 30,000 संविदा कर्मचारी भी हैं जो विशिष्ट परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं. समिति ने सेना की अग्निवीर योजना की तर्ज पर परियोजनाओं की जरूरत के हिसाब से 3-5 साल के लिए पीएचडी और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीधारियों की भर्ती का प्रस्ताव रखा है. इस अवधि के बाद, उनमें से करीब 25 फीसद को नियमित तौर पर डीआरडीओ का हिस्सा बना लिया जाएगा. समिति का मानना है कि इससे प्रदर्शन को लेकर जवाबदेही ज्यादा बढ़ेगी और उच्च गुणवत्ता वाली जनशक्ति को बनाए रखा जा सकेगा. प्रदर्शन न करने वालों को बाहर करने के संबंध में समिति का सुझाव है कि इससे पहले उनके पिछले दस वर्षों के कामकाज और उपलब्धियों की कड़ी समीक्षा की जाए. योगदान न देने वाले वैज्ञानिकों को समय-पूर्व सेवानिवृत्ति लेने को कहा जा सकता है. वहीं, प्रशासन और संबद्ध सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को अन्य सरकारी मंत्रालयों में स्थानांतरित किया जा सकता है. ये योजनाएं महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन क्या डीआरडीओ इसके लिए तैयार होगा? ■

खास रपटः फ्लू

यह जुकाम ठीक क्यों नहीं हो रहा

कड़ाके की ठंड, प्रदूषण और कोविड की सावधानियां घटने के साथ इन्फ्लूएंजा वायरस के आक्रामक और बार-बार धमक पड़ने वाले रूपों की चपेट में आकर भारतीय लोग बीमार पड़ रहे हैं. टीका और एहतियात से ही काबू में आ सकता है इसका जोर

सोनाली आचार्जी

अधिकतर लोगों के लिए 'फ्लू होना' सेहत का मामूली मसला है. इसमें मौसम बदलने पर बुखार, खांसी, सिरदर्द, बदनदर्द, नाक बहने और गले में तकलीफ सरीखे जाने-पहचाने लक्षण होते हैं और जिन्हें आराम करके और हल्की-फुल्की दवा लेकर ठीक कर लिया जाता है. मगर देश भर के डॉक्टर इन दिनों एक ऐसे फ्लू की इत्तिला दे रहे हैं जो न केवल लंबा चलता है बल्कि इस लिहाज से गैरमामूली भी है कि इसके लक्षण अनोखे हैं और यह ठीक होने के बाद भी दोबारा जल्द आ धमकता है.

इन्फ्लूएंजा के संक्रमणों में बढ़ोतरी को देखते हुए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) ने जनवरी 2024 में इन्फ्लूएंजा का 2024 चतुर्भुज टीका लगवाने की सिफारिश की, जो इन्फ्लूएंजा ए के दो रूपों और इन्फ्लूएंजा बी के दो रूपों से सुरक्षा प्रदान करता है. इन्फ्लूएंजा सांस का संक्रमण है जो संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने पर बहुत छोटी-छोटी बूंदों से फैलता है. इन्फ्लूएंजा वायरस चार प्रकार के होते हैं—टाइप ए, बी, सी और डी. इन्फ्लूएंजा ए और बी वायरस घूमते रहते हैं और उस इलाके में बड़े पैमाने पर स्थानीय मौसमी बीमारी पैदा करते हैं. केवल इन्फ्लूएंजा ए वायरस ही महामारियां पैदा करने के लिए जाने जाते हैं. इन्फ्लूएंजा ए वायरस को दो उपप्रकारों में बांटा जाता है—ए(एच1एन1) और ए(एच3एन2) वायरस—जो इन दिनों घूम रहे हैं. ए(एच1एन1) को ए(एच1एन1) पीडीएम09 भी लिखा जाता है क्योंकि इसने 2009 में फ्लू की महामारी पैदा की थी और पुराने ए(एच1एन1) वायरस की जगह ले ली थी. एच1एन1 को 'स्वाइन फ्लू' भी कहा जाता है, और यह सूअर व इंसान दोनों को संक्रमित कर सकता है. एनसीडीसी की एक रिपोर्ट ने ए(एच1एन1) पीडीएम09, ए(एच3एन2) और टाइप बी विक्टोरिया वंशावली के वायरसों की भारत में मौजूदगी की तरफ ध्यान दिलाया है.

बेंगलूरू के फोर्टिस सीजी रोड अस्पताल में आंतरिक चिकित्सा के डायरेक्टर डॉ. आदित्य एस. चौटी कहते हैं, ''हमने फ्लू का सामान्य से लंबा सीजन देखा, जिसमें मरीज ठीक होने के एक या दो हफ्ते बाद उन्हीं लक्षणों के साथ लौट आए.'' उनका कहना है कि ऐसा इस साल शहर में असामान्य रूप से लंबी सर्दी पड़ने और सर्द सुबह व गर्म दोपहर के साथ रोज तापमान में उतार-चढ़ावों की वजह से हुआ. डॉ. चौटी यह भी कहते हैं, ''हमारे यहां एक शब्द है जिसे बंगलौर ब्रॉंकाइटिस कहते हैं, जिसमें हवा में मौजूद एलर्जेन से लोगों में सर्दी या फ्लू सरीखे लक्षण विकसित होते हैं. दुनिया भर की यात्राएं कर रहे लोग भी वायरल स्ट्रेन ले ही आते हैं.'' उत्तर भारत में फ्लू सामान्यतः दो बार चरम पर पहुंचता है—मॉनसून के बाद (सितंबर-अक्तूबर) और सर्दियों के महीनों (दिसंबर-जनवरी) में.

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, अक्तूबर 2023 के अंत तक भारत में एच1एन1 के 5,350 मामले और 101 मौतें दर्ज की गईं. आंकड़ों से पता चलता है कि एच1एन1 के मामले और मौतें केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, सिक्किम, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में बढ़ीं. केरल में तो अच्छा-खासा इजाफा हुआ. 2022 में जहां केवल 94 मामले थे, 2023 में राज्य में 909 मामले दर्ज हुए. मौतें भी 2022 में 11 से बढ़कर 2023 में 53 हो गईं. महाराष्ट्र में 2022 में 215 मामले सामने आए, जो 2023

यह जुकाम ठीक क्यों नहीं हो रहा

कड़ाके की ठंड, प्रदूषण और कोविड की सावधानियां घटने के साथ इन्फ्लूएंजा वायरस के आक्रामक और बार-बार धमक पड़ने वाले रूपों की चपेट में आकर भारतीय लोग बीमार पड़ रहे हैं. टीका और एहतियात से ही काबू में आ सकता है इसका जोर

सोनाली आचार्जी

अधिकतर लोगों के लिए 'फ्लू होना' सेहत का मामूली मसला है. इसमें मौसम बदलने पर बुखार, खांसी, सिरदर्द, बदनदर्द, नाक बहने और गले में तकलीफ सरीखे जाने-पहचाने लक्षण होते हैं और जिन्हें आराम करके और हल्की-फुल्की दवा लेकर ठीक कर लिया जाता है. मगर देश भर के डॉक्टर इन दिनों एक ऐसे फ्लू की इत्तिला दे रहे हैं जो न केवल लंबा चलता है बल्कि इस लिहाज से गैरमामूली भी है कि इसके लक्षण अनोखे हैं और यह ठीक होने के बाद भी दोबारा जल्द आ धमकता है.

इन्फ्लूएंजा के संक्रमणों में बढ़ोतरी को देखते हुए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) ने जनवरी 2024 में इन्फ्लूएंजा का 2024 चतुर्भुज टीका लगवाने की सिफारिश की, जो इन्फ्लूएंजा ए के दो रूपों और इन्फ्लूएंजा बी के दो रूपों से सुरक्षा प्रदान करता है. इन्फ्लूएंजा सांस का संक्रमण है जो संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने पर बहुत छोटी-छोटी बूंदों से फैलता है. इन्फ्लूएंजा वायरस चार प्रकार के होते हैं—टाइप ए, बी, सी और डी. इन्फ्लूएंजा ए और बी वायरस घूमते रहते हैं और उस इलाके में बड़े पैमाने पर स्थानीय मौसमी बीमारी पैदा करते हैं. केवल इन्फ्लूएंजा ए वायरस ही महामारियां पैदा करने के लिए जाने जाते हैं. इन्फ्लूएंजा ए वायरस को दो उपप्रकारों में बांटा जाता है—ए(एच1एन1) और ए(एच3एन2) वायरस—जो इन दिनों घूम रहे हैं. ए(एच1एन1) को ए(एच1एन1) पीडीएम09 भी लिखा जाता है क्योंकि इसने 2009 में फ्लू की महामारी पैदा की थी और पुराने ए(एच1एन1) वायरस की जगह ले ली थी. एच1एन1 को 'स्वाइन फ्लू' भी कहा जाता है, और यह सूअर व इंसान दोनों को संक्रमित कर सकता है. एनसीडीसी की एक रिपोर्ट ने ए(एच1एन1) पीडीएम09, ए(एच3एन2) और टाइप बी विक्टोरिया वंशावली के वायरसों की भारत में मौजूदगी की तरफ ध्यान दिलाया है.

बेंगलूरू के फोर्टिस सीजी रोड अस्पताल में आंतरिक चिकित्सा के डायरेक्टर डॉ. आदित्य एस. चौटी कहते हैं, ''हमने फ्लू का सामान्य से लंबा सीजन देखा, जिसमें मरीज ठीक होने के एक या दो हफ्ते बाद उन्हीं लक्षणों के साथ लौट आए.'' उनका कहना है कि ऐसा इस साल शहर में असामान्य रूप से लंबी सर्दी पड़ने और सर्द सुबह व गर्म दोपहर के साथ रोज तापमान में उतार-चढ़ावों की वजह से हुआ. डॉ. चौटी यह भी कहते हैं, ''हमारे यहां एक शब्द है जिसे बंगलौर ब्रॉंकाइटिस कहते हैं, जिसमें हवा में मौजूद एलर्जेन से लोगों में सर्दी या फ्लू सरीखे लक्षण विकसित होते हैं. दुनिया भर की यात्राएं कर रहे लोग भी वायरल स्ट्रेन ले ही आते हैं.'' उत्तर भारत में फ्लू सामान्यतः दो बार चरम पर पहुंचता है—मॉनसून के बाद (सितंबर-अक्तूबर) और सर्दियों के महीनों (दिसंबर-जनवरी) में.

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, अक्तूबर 2023 के अंत तक भारत में एच1एन1 के 5,350 मामले और 101 मौतें दर्ज की गईं. आंकड़ों से पता चलता है कि एच1एन1 के मामले और मौतें केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, सिक्किम, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में बढ़ीं. केरल में तो अच्छा-खासा इजाफा हुआ. 2022 में जहां केवल 94 मामले थे, 2023 में राज्य में 909 मामले दर्ज हुए. मौतें भी 2022 में 11 से बढ़कर 2023 में 53 हो गईं. महाराष्ट्र में 2022 में 215 मामले सामने आए, जो 2023

फ्लू क्या है और उससे कैसे बचें

- इन्फ्लूएंजा वायरस चार तरह के होते हैं: टाइप ए, बी, सी और डी
- इन्फ्लूएंजा ए भारत में सबसे आम है. ये दो तरह के होते हैं: एच1एन1 और एच3एन2
- एच1एन1 की वजह से 2009 में स्वाइन फ्लू महामारी फैली. यही सबसे आम है
- देश में महामारी से पहले के मुकाबले एच3एन2 के मामले ज्यादा देखे गए हैं. इसकी वजह इस वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता कम होना, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण है
- एच3एन2 के लक्षण लंबे समय तक रहते हैं, बार-बार होते हैं. 2023 की सर्दी के फ्लू सीजन में सांस की गंभीर बीमारी वाले अस्पताल में भर्ती लोगों में से 50 फीसद में यह संक्रमण था. देशभर में एच1एन1 के मामलों में भी उछाल आया
- नए इन्फ्लूएंजा टीके दोनों तरह के स्ट्रेन से बचाते हैं और फ्लू के मौसम (जून-सितंबर, नवंबर-मार्च) से पहले इन्हें लगवाने की सलाह दी जाती है

इलस्ट्रेशनः सिद्धांत जुमडे

में बढ़कर 1,125 पर पहुंच गए.

अलबत्ता 2023 के पहले तीन महीने में एच3एन2 सबसे अधिक मामलों के साथ एच1एन1 और कोविड के मुकाबले प्रमुख उपप्रकार बना रहा. 2023 के पहले नौ हफ्तों (2 जनवरी से 5 मार्च) के दौरान भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) के निगरानी नेटवर्क ने सात मौत सहित एच3एन2 के 451 मामले दर्ज किए (एच1एन1 के 41 मामले थे).

बेहद संक्रामक एच3एन2 से ज्यादातर लोग हफ्ते भर के भीतर ठीक हो जाते हैं, कुछ मामलों में न्यूमोनिया और ब्रॉंकाइटिस सरीखी जटिलताएं पैदा हो जाती हैं जिनसे मौत तक हो सकती है. आइसीएमआर ने बताया कि 2023 में एच3एन2 के प्रकोप की चपेट में आए मरीजों में से करीब 10 फीसद गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण (एसएआरआइ) से पीड़ित थे और उन्हें ऑक्सीजन का सहारा लेना पड़ा, जबकि सात फीसद को आइसीयू की देखभाल की जरूरत पड़ी. आइसीएमआर के आंकड़ों से पता चला कि 2023 में एसएआरआइ के प्रकोप से अस्पताल में भर्ती लोगों में से 50 फीसद में एच3एन2 का संक्रमण पाया गया.

मैक्स हेल्थकेयर के मेडिकल डायरेक्टर डॉ. संदीप बुद्धिराजा कहते हैं, "इस साल और पिछले साल के आखिर में हमने बड़ी तादाद में फ्लू के मामले देखे. हम आम तौर पर फ्लू को गंभीर बीमारी से जोड़कर नहीं देखते, पर कुछ मरीजों में गंभीर लक्षण विकसित हो सकते हैं. वही लोग ज्यादा असुरक्षित हैं जो कोविड के दौरान थे—बुजुर्ग, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, अनियंत्रित डायबिटीज, हृदयरोग, लीवर के

“पिछले साल के अंत से फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं. हालिया हफ्तों में खासकर सीओपीडी, अस्थमा या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने की संख्या बढ़ गई है”

डॉ. संदीप बुद्धिराजा, *मेडिकल डायरेक्टर, मैक्स हेल्थकेयर, दिल्ली*

“इन्फ्लूएंजा वायरस अधिक आक्रामक नहीं हो रहा है. वास्तव में, खासकर एच3एन2 के प्रति हमारा जोखिम कम रहा है”

डॉ. दीपू टी.एस., *एसोसिएट प्रोफेसर, डिविजन ऑफ इंफेक्टियस डिजीजेज, अमृता हॉस्पिटल, कोच्चि*

रोग, कैंसर सरीखी सह-बीमारियों से ग्रस्त लोग, इम्यूनोसप्रेसिव दवाएं ले रहे लोग—ये सभी जोखिम से घिरे हैं.'' डॉ. बुद्धिराजा यह भी कहते हैं कि एच3एन2 सरीखे कुछ स्ट्रेन से बीमारी लंबी चलती है जिसमें मरीज लगातार सूखी या खुश्क खांसी की शिकायत करते हैं.

फ्लू से आम तौर पर पारंपरिक लक्षणों के साथ ऊपरी श्वसन संक्रमण होता है जो पांच-सात दिन रहता है. मगर ज्यादा जोखिम से घिरे लोगों में न्यूमोनिया और दूसरी जटिलताएं विकसित हो सकती हैं. डॉ. बुद्धिराजा यह भी कहते हैं, ''पिछले कुछ हफ्तों में फ्लू की जटिलताओं से ग्रस्त ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, खासकर उन्हें जिन्हें सीओपीडी (क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज), अस्थमा या बेहद गंभीर ब्रॉंकाइटिस है.''

राजधानी के एक और अस्पताल से भी ऐसी ही रिपोर्ट हैं. गुड़गांव के सी.के. बिड़ला अस्पताल में आंतरिक चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. तुषार तायल कहते हैं, ''इस साल फ्लू के संक्रमण का बार-बार होना बढ़ गया है, पर मैंने यह भी देखा है कि लक्षण ज्यादा लंबे वक्त रहते हैं. एक हफ्ते के बजाय वे करीब दो हफ्ते बने रहते हैं.'' हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा वायरस में किन्हीं बदलावों की वजह से नहीं है. कोच्चि के अमृता अस्पताल में संक्रामक रोग विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. दीपू टी.एस. कहते हैं, ''वायरस ज्यादा आक्रामक नहीं हो रहा है. असल में हमारा अनुभव और खासकर एच3एन2 का अनुभव कम है.''

मौजूदा फ्लू संक्रमण के अनोखेपन की वजह कहीं और है. सर्दियों और बढ़ते प्रदूषण की गहनता से लक्षण बिगड़ रहे हैं और संक्रमण फैल रहा है. मसलन, दिल्ली ने कम से कम 12 साल की सबसे सर्द जनवरी देखी. उत्तर के दूसरे हिस्सों ने भी शीत लहर से जंग लड़ी. जाती हुई ठंड बार-बार लौटकर आई. यही वे स्थितियां हैं जिनमें फ्लू का वायरस ज्यादा लंबे समय तक बाहर रहता है. कुछ निश्चित आंकड़ों से भी पता चलता है कि अत्यधिक सर्दी इंसान की रोगप्रतिरक्षा प्रणाली को सुस्त कर देती है.

एक और वजह कोविड-19 महामारी के बाद फिर फ्लू के संपर्क में आना है. डॉ. बुद्धिराजा कहते हैं, ''कोविड के दौरान सब मास्क लगाते और अलग-थलग रहते थे. इसने हमें फ्लू होने से रोका. फ्लू के वायरस का फैलाव कम था और इसके खिलाफ शरीर की रोग प्रतिरोधक व प्रतिरक्षक शक्ति भी कम हो गई. इसलिए उन तीन साल में दुनिया भर में फ्लू के वायरस के खिलाफ रोगप्रतिरक्षा की स्थिति में गिरावट आई हो सकती है.''

सुरक्षित कैसे रहें

इन्फ्लूएंजा के मौसमी वायरस खांसने और छींकने के जरिए तो फैलते ही हैं, फ्लू के वायरस से दूषित हाथों से भी फैलते हैं. इन्हें फैलने से रोकने के लिए लोगों को महामारी के नियम-कायदों की तरफ लौटना होगा—खांसते या छींकते वक्त अपने मुंह और नाक को रूमाल या कपड़े से ढकें और नियमित रूप से हाथ धोएं. भीड़ भरी जगहों पर जाने से बचना चाहिए और जाना ही हो तो मास्क पहनकर जाएं. संक्रमण की तीव्रता को रोकने के लिए जरूरी है कि लक्षणों की शुरुआत के पहले 48 घंटों के भीतर डॉक्टर से सलाह लें. डॉ. बुद्धिराजा कहते हैं, ''ज्यादा जोखिम वाले मरीजों के लिए ये हिदायतें जरूरी हैं. फ्लू अगर गंभीर हो जाता है तो जिंदगी के लिए खतरा हो सकता है.''

डॉ. तायल कहते हैं, ''मेरा कहना यह है कि लोग खुद अपना इलाज न करें और डॉक्टर से सलाह लिए बिना न तो पैरासिटामोल लें और न भाप लें. यह बेहद जरूरी है.'' विशेषज्ञ नुस्खे के बिना ऐंटीबायोटिक या स्टेरॉइड लेने के खिलाफ भी आगाह करते हैं. डॉ. तायल कहते हैं, ''अव्वल तो आपको कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है. फ्लू की ज्यादातर बीमारियां आराम, पौष्टिक खाने और तरल पदार्थों से खत्म हो जाती हैं.''

फ्लू के संक्रमण को रोकने का दूसरा तरीका टीका लगवाना है. इन्फ्लूएंजा का नया टीका चार स्ट्रेन से बचाता है—इन्फ्लूएंजा ए के दोनों स्ट्रेन और इन्फ्लूएंजा बी के दो स्ट्रेन. डॉ. बुद्धिराजा बताते हैं, ''हर साल नया टीका आता है जिसकी बनावट उस भूगोल में हावी वायरस के स्ट्रेन के आधार पर कुछ अलग हो सकती है. नया टीका उत्तर भारत के लिए आम तौर पर सितंबर के आसपास जारी किया जाता है. इसे लेने का सबसे अच्छा वक्त यही है.'' टीका केवल करीब एक साल की सुरक्षा देता है. डॉ. बुद्धिराजा कहते हैं, ''कोई भी टीका 100 फीसद बचाव नहीं करता. हालांकि यह गंभीर लक्षणों और मौत की संभावना को बहुत कम जरूर कर देगा.'' वे जोर देकर कहते हैं कि यह कोविड से बचाव नहीं करता.

फ्लू का टीका तो मिल रहा है, पर डॉक्टरों का कहना है कि इसकी मांग काफी कम है. डॉ. चौटी कहते हैं, ''ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बच्चों को टीके लगवाना अनिवार्य है, पर वयस्क टीके मायने नहीं रखते, लेकिन यह कतई सच नहीं है. आखिर, जिंदगी के विभिन्न चरणों में सुरक्षा की जरूरत पड़ती ही है.'' ■

थिएटर

मैं पल दो पल का शायर हूं
शायराना किस्सा

कद्दावर अभिनेता दानिश हुसैन के शांत-सात्विक अभिनय के जरिए जैसे जिंदा हुई साहिर की रूह

शिवकेश

हिर ने ही कहा था: *फन जो नादार तक नहीं पहुंचा, अभी मयार तक नहीं पहुंचा.* अल्फाज के मानी जब तक कतार में सबसे पीछे खड़े आदमी के सामने भी न खुल जाएं, कामयाब नहीं माने जा सकते. उन्हीं साहिर की फानी जिंदगी के इस इटर्नल किस्से में वे खुलते भी हैं और खिलते भी. बेरहम बाप और खुद्दार मां के दरमियान होकर गुरबत से क्रिएटिव शोहरत तक. उनके पहले ही कलेक्शन *तल्खियां* के छा जाने के बाद वे एक फिल्म प्रोड्यूसर से मिलने पहुंचते हैं. वह दराज से कलेक्शन निकालकर देखता है, सामने बैठे 24 साल के दुबले-से नौजवान की ओर बेयकीनी से घूरता है फिर चिल्ला पड़ता है: 'भाग यहां से, बहरूपिया कहीं का.' एक बार के बाद जीवन में दोबारा हवाई सफर न करना, लता मंगेशकर के सामने उनके नगमों को नीचा दिखाए जाने पर अपने गाने उनसे फिर कभी न गवाना, संगीतकारों से एक रुपया ज्यादा फीस लेना और उनके ऐंठने पर उनके असिस्टेंट्स को ही बतौर संगीतकार खड़ा कर देना...

नाटक *मैं पल दो पल का शायर हूं* ऐसी कितनी ही शर्तों के सिद्दे में बिंधी और उनके सदाबहार नगमों में गुंथी एक शायराना जिंदगी का दो घंटे का थिएट्रिकल किस्सा है. इसका गवाह बनते हुए कई बार आप भूल जाते हैं कि दरअसल आप एक नाटक देख रहे हैं. स्टेज के दाईं ओर साहिर के नग्मे गाते और स्टोरी नैरेट करते 5-6 कलाकार; बाईं ओर टेबल, लैंप आदि के बीच आराम कुर्सी पर, साहिर बने 52 वर्षीय दानिश हुसैन. गतियां ठहरी-सी. पर वाचिक और गायन इतना प्रगाढ़ कि पलक झपकना भी जैसे खटके.

साहिर लुधियानवी बतौर शायर और फिल्मी नग्मानिगार हिंदुस्तान की हवाओं में पैवस्त हैं. एक रेफरेंस पॉइंट, एक मुहावरा हैं: कोई साहिर-सा. उनका किस्सा कहने के और भी प्रयोग हुए हैं पर यह अलहदा और हटकर है. मीर हुसैन अली और हिमांशु बाजपेयी की दो अलग-अलग ट्रैक वाली स्क्रिप्ट को एक में पिरोकर यह प्ले एक ओर साहिर की जबान में खुलता है और साथ-साथ उनके कंटेंपररीज़ के हवाले से. न अभिनय में किसी शैली का साज-सिंगार न स्टेज का प्रपंच. सारा फोकस किस्से पर, आइबॉल टु आइबॉल.

दानिश, जो नाटक के निर्देशक भी हैं, साफ करते हैं: ''साहिर जो कह रहे हैं, उसमें खुद इतनी गहराई है कि कुछ और नाच-कूद करने की जरूरत ही नहीं. इकबाल का वह शेर है ना कि *दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है.* पर हां, बतौर ऐक्टर आप उन अल्फाज को अपना तभी बना सकते हैं जब उनकी गहराई में डूबें. शांतनु हार्लेकर और सृजनी भट्टाचार्य की गायिकी गानों को ढंग से संभालती है. कद्दावर अभिनेता, गायक और लाइव म्यूजिक की वजह से यह महंगा प्रोडक्शन है. इसीलिए छह महीने पहले मुंबई के पृथ्वी थिएटर में प्रीमियर के बाद इस हफ्ते दिल्ली में भारत रंग महोत्सव के तहत इसका चौथा शो था. अगला शो 24 फरवरी को हैदराबाद के शिल्पकला वेदिका में है.

दिल्ली में महमूद फारुकी के साथ दास्तानगोई का हिस्सा रहे दानिश बाद में अभिनय पर फोकस करने मुंबई कूच कर गए. फिल्में तो कर ही रहे हैं पर वे कहते हैं, ''ऑडियंस की आंखों में देखते हुए अभिनय का जो सुख है उसका कोई मोल नहीं.''■

मानसी जी. फोटोग्राफी

''साहिर के कहे हुए में ही इतनी गहराई है कि किसी और नाच-कूद की जरूरत नहीं. पर बतौर ऐक्टर उन अल्फाज में डूबकर ही आप उसे अपना बना सकते हैं''

दानिश हुसैन, *अभिनेता-निर्देशक*

राज जिसे ट्रस्टियों ने ही किया तबाह

कभी अरबों की संपत्ति, जबरदस्त सामाजिक और सियासी रसूख. अब भांय-भांय करते महलों की गिरतीं-दरकतीं दीवारें. भग्नछवि. भीतर दुरभिसंधियां और बाहर दर्ज होतीं चोरी-चकारी की रपटें. राज दरभंगा के सुनहरे अतीत से अंगभंग वर्तमान तक एक नजर

पुष्यमित्र

पल भर का साथ
दरभंगा की आखिरी रानी 96 वर्षीया कामसुंदरी के साथ राज के एक वारिस कपिलेश्वर सिंह. दादी से उनका मिलना दुश्वार

अप्रैल 17, 1947. राज दरभंगा के अंतिम राजा कामेश्वर सिंह महात्मा गांधी से मिलने पटना स्थित उनके कैंप में पहुंचे थे. उन्होंने गांधी से पूछा, ''अब हमारे लिए क्या संदेश है?'' गांधी ने कहा, ''प्रजा के सेवक बनिए. आप अपनी संपत्ति के ट्रस्टी हैं, ऐसा मानकर उस संपत्ति से अपनी जरूरत पूरी करने जितना ही खर्च करें. फिजूल का सब खर्च बंद कर दीजिए.'' कामेश्वर सिंह ने संदेश सुना और 5,000 रु. का चंदा देकर लौट आए. गांधी का यह संदेश सुनकर उन्हें वह बात याद आ गई होगी, जो उनके पुरखे अक्सर कहा करते थे, ''दरभंगा का पूरा राज हमारी कुलदेवी कंकाली का है, हम तो बस उसके ट्रस्टी हैं.'' बहरहाल, 1961 में जब उन्होंने अपनी वसीयत तैयार कराई तो पूरी संपत्ति का एक ट्रस्ट बनाकर तीन लोगों को उसकी देखरेख की जिम्मेदारी सौंप दी. इनमें दो परिवार से बाहर के लोग थे. एक उनके बहनोई थे. ऐशोआराम की जिंदगी जीने वाली अपनी दो रानियों के लिए उन्होंने सिर्फ प्रति माह पेंशन की व्यवस्था छोड़ी थी. वह भी कभी 3,000 रु. प्रति माह कही जाती है तो कभी 5,000 रुपए.

अब सीधे 30 जनवरी, 2024. ऐन गांधी जी की शहादत दिवस पर राज दरभंगा के वारिसों में से एक कामेश्वर सिंह के भाई के पोते कपिलेश्वर सिंह ने दरभंगा के यूनिवर्सिटी थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उनके परिवार से जुड़े ट्रस्ट कामेश्वर रिलीजियस ट्रस्ट के बहुमूल्य गहनों को उदयनाथ झा नाम के व्यक्ति ने बेच दिया है. वह कामेश्वर सिंह की दूसरी पत्नी कामसुंदरी देवी का एटॉर्नी है. कपिलेश्वर सिंह बताते हैं कि 108 मंदिरों की व्यवस्था देखने वाले इस ट्रस्ट के पास जितने गहने-जवाहरात थे, उनकी इस वक्त बाजार में कीमत करीब दो सौ करोड़ रु. होगी. दरभंगा पुलिस के सिटी एसपी ने इसे चार किलो सोना और 30 किलो चांदी बताया. एक ज्वेलर ने भी सोना खरीदने की बात कुबूल की और कहा कि कुल गहने 86 लाख रु. के थे. गहने गला दिए गए थे और पेमेंट चेक से होने वाली थी. पुलिस ने झा, ट्रस्ट के मैनेजर और ज्वेलर को हिरासत में लिया, फिर पीआर बॉन्ड पर छोड़ दिया.

दरभंगा राज के इतिहास से वाकिफ और आम लोगों का भी कहना है कि यह 1962 में राज के ट्रस्ट बनने के बाद शुरू हुई लूट के सिलसिले का ही हिस्सा है. दरभंगा राज को उन ट्रस्टियों ने ही लूट लिया, जिन पर भरोसा करके कामेश्वर सिंह ने खरबों की संपत्ति छोड़ दी थी. अक्तूबर, 1962 में उनके निधन के वक्त राज की संपत्ति 2,000 करोड़ रु. के करीब बताई गई थी, जो आज के बाजार मूल्य के हिसाब से चार लाख करोड़ रु. रही होगी. इसमें 14 बड़ी कंपनियां, देश-दुनिया के कई शहरों में बंगले, अरबों के जेवरात, जमीन और शेयर बाजार में उनके नाम पर भारी निवेश था (देखें बॉक्स: खरबों की वह संपत्ति). आज उसका दो फीसद भी नहीं बचा है. कपिलेश्वर तंज कसते हैं, ''एक पूरी नदी थी, अब छोटा-सा गड्ढा बच गया है. इसे भी लूटने की कोशिश चल रही है.''

कामेश्वर सिंह की मौत के बाद की घटनाओं पर लिखी गई किताब *द क्राइसिस ऑफ सक्सेशन* के लेखक तेजकर झा कहते हैं, ''लोगों का शुब्हा वाजिब है क्योंकि दरभंगा राज को लूटने का यह सेट पैटर्न रहा है. इसी तरह एंटीक ज्वेलरी को बेचा गया था. उसकी कीमत एक यूरोपियन फर्म ने उसी जमाने में 2 करोड़ पाउंड आंकी थी. मगर महाराजा की मौत के बाद उनकी डेथ ड्यूटी (धनी व्यक्तियों की मौत के बाद उस जमाने में सरकार टैक्स लगाती थी) चुकाने के नाम पर ट्रस्टियों ने उन तमाम गहनों को मुंबई के मशहूर ज्वेलर नानू भाई को महज 70-75 लाख रु. में बेच

खरबों की वह संपत्ति

अपनी शानदार एयरलाइन, एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल, चीनी और जूट मिलें, खुद के दो-दो अखबार और शेयर का कारोबार. साठ के दशक तक भी क्या जलवे हुआ करते थे राज दरभंगा के

राज दरभंगा की जमींदारी

कुल गांव	कुल स्टाफ	हेडक्वार्टर में स्टाफ
4,497 इनमें से 310 गांव संताल के	**7,110**	**341**

राज दरभंगा की प्रोमोटेड कंपनियां

1. न्यूजपेपर ऐंड पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेडः दो पॉपुलर अखबार *आर्यावर्त* और *इंडियन नेशन* का प्रकाशन. इसके अलावा *मिथिला मिहिर*, मैथिली और *द डव* अंग्रेजी पत्रिका का प्रकाशन.

2. वालफोर्डः रॉल्स रॉयस कारों की डीलरशिप. इनके तीन शोरूम कलकत्ता, गुवाहाटी और इंफाल में थे.

3. दरभंगा एविएशनः राज दरभंगा ने 1950 में दरभंगा एविएशन के नाम से एक विमान सेवा शुरू की थी. पांच एयरक्राफ्ट से शुरू हुई इस कंपनी के जहाज 1962 तक उड़ान भरते रहे.

4. अशोक पेपर मिलः राज दरभंगा का यह कारखाना न्यूजप्रिंट का उत्पादन करता था. उस जमाने में इसे एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल कहा जाता था. बाद में बिहार सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया और फिर यह मिल बंद हो गई.

5. सकरी चीनी मिलः 1933 में स्थापित इस शुगर मिल का भी बाद में बिहार सरकार ने अधिग्रहण कर लिया और 1996-97 में यह बंद हो गई.

6. पंडौल शुगर मिलः इसका भी राष्ट्रीयकरण हो गया और फिर यह भी बंद हो गई.

7. रामेश्वर जूट मिल, बलियाघाट, कलकत्ताः 1935 में स्थापित यह जूट मिल बाद में बिक गई. इसे बिरला ने खरीद लिया.

8. रामेश्वर जूट मिल, मुक्तापुर, समस्तीपुरः यह मिल सरकार के नियंत्रण में है

9. ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशनः एक बड़ा बिजनेस हाउस जिसकी कानपुर और उत्तर भारत के दूसरे इलाकों में कई मिल और फैक्टरियां थीं. राज दरभंगा की इस कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी थी.

10. ओक्टावियस स्टीलः कलकत्ता की एक बड़ी प्रबंधन एजेंसी जिसका इंजीनियरिंग, चाय, चीनी आदि उद्योगों में निवेश था. इसमें भी राज दरभंगा की बड़ी हिस्सेदारी थी.

11. विलियर्स लिमिटेडः एक कंपनी जो शेयर्स का कारोबार करती थी.

12. दरभंगा इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेडः मेलिएबल स्टील उत्पादन की एक इकाई.

13. थैकर्स स्पिंक ऐंड कंपनी(1933) लिमिटेडः स्टेशनरी और किताबों की उत्पादक कंपनी

14. थैकर्स प्रेस ऐंड डी लिमिटेड

राज दरभंगा के पास गहने

राज दरभंगा के पास कुल कितने गहने थे, इसका सटीक ब्योरा तो अभी उपलब्ध नहीं है. मगर विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी के मुताबिक एक विदेशी फर्म ने इसके एंटीक गहनों की कीमत 1950-60 के दशक में 20 मिलियन पाउंड लगाई थी. 1963 में राज के ट्रस्टियों ने तत्कालीन वित्त मंत्री मोरारजी देसाई को 15 मन (600 किलो) सोने से तौला था. इसके बाद भी गहने बिकते रहे.

Fifteen Maunds Of Gold For Defence Fund

The Times of India, 6th December

DARBHANGA RAJ OFFER

To meet the expenses of countering Chinese incursion in 1962

1987 में राज के पारिवारिक समझौते में पाया गया कि राज के पास तकरीबन 11 लाख रु. के सोने के सिक्के, 5.33 लाख रु. के तीन हीरे के बटन बचे हुए थे. कपिलेश्वर सिंह के मुताबिक, कामेश्वर रिलीजियस ट्रस्ट के पास दो सौ करोड़ रु. के गहने थे. पुलिस के मुताबिक, हाल के दिनों में इस ट्रस्ट ने चार किलो सोना और 30 किलो चांदी बेची है.

कहां-कहां कोठियां थीं राज दरभंगा की*

*1987 में कीमत

रामबाग पैलेस की 54 बीघा जमीन, दरभंगा 1 लाख रुपए

- अस्पताल, दरभंगा **6 लाख रुपए**
- नौ ए-टाइप स्टाफ बंगले **19.40 लाख रुपए**
- चार बी टाइप क्वार्टर **3 लाख रुपए**
- छह सी टाइप क्वार्टर **3.17 लाख रुपए**
- आठ डी टाइप क्वार्टर **3.20 लाख रुपए**
- 14 ई टाइप क्वार्टर **3.30 लाख रुपए**
- 15 एफ टाइप क्वार्टर **2.52 लाख रुपए**
- 8 जी टाइप क्वार्टर **1.56 लाख रुपए**
- अन्य अधिकारियों के 14 आवास **15 लाख रुपए**

1987 का पारिवारिक समझौता

महारानी राजलक्ष्मी के निधन, ट्रस्टियों की ओर से संपत्ति की खुलेआम बिक्री, इमरजेंसी में कारखानों, महलों और जमीनों का सरकारी अधिग्रहण और दूसरी विभिन्न वजहों से राज दरभंगा की संपत्ति विनाश के कगार पर पहुंचने लगी. इस पर परिवार के लोगों ने अदालत में जाकर समझौता किया. इसके बाद संपत्ति चार हिस्सों में बंटी. पहला हिस्सा रानी कामसुंदरी देवी को गया. दूसरा शुभेश्वर सिंह के दोनों बेटों राजेश्वर सिंह और कपिलेश्वर सिंह के नाम, तीसरा महाराजा के अन्य भतीजों के परिजनों के नाम और चौथा कामेश्वर सिंह पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए छोड़ दिया गया. समझौते में कुछ संपत्ति का बेचा जाना भी तय हुआ, जिसे बेचकर राज का उधार चुकाया जाना था.

महाराजा कामेश्वर सिंह की 1961 की वसीयत

- मेरी बड़ी पत्नी महारानी राजलक्ष्मी को रहने के लिए रामबाग पैलेस के भवन दिए जाएंगे, सिर्फ रहने के उद्देश्य से. उनके निधन के बाद ये भवन मेरे भतीजे राजकुमार शुभेश्वर सिंह को मिलेंगे.
- मेरी छोटी पत्नी महारानी कामसुंदरी को नरगौना पैलेस रहने के लिए दिया जाएगा. उनके निधन के बाद यह मेरे भतीजे राजकुमार शुभेश्वर सिंह को मिलेगा.
- इन दोनों रानियों को मैं 15-15 लाख रु. के एसेट देता हूं.
- इसके बाद मैं अपना सारा एस्टेट बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में शामिल करा देना चाहता हूं. ये ट्रस्टी मेरी संपत्ति की देखरेख करेंगे. मेरी दोनों रानियों के निधन के बाद मेरी एक-तिहाई संपत्ति मेरे भतीजे राजकुमार शुभेश्वर सिंह की होगी. एक-तिहाई दूसरे भतीजों राजकुमार जीवेश्वर सिंह और यज्ञेश्वर सिंह के बीच बांटी जाएगी. शेष एक-तिहाई संपत्ति का इस्तेमाल पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पर होगा.
- ट्रस्टी होंगे—गिरींद्र मोहन मिश्र, लक्ष्मीकांत झा और मुकुंद झा.उ

लॉर्ड माउंटबेटन और एडविना के साथ कामेश्वर सिंह
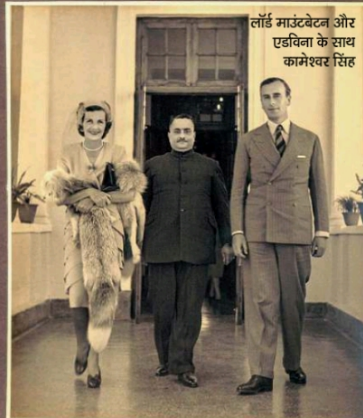
वे लाखों के शेयर

राज दरभंगा का पैसा बड़े पैमाने पर दुनिया भर के शेयर बाजारों में भी निवेश किया गया था. 1987 में पारिवारिक समझौते के वक्त भी इनमें से **63 लाख** रुपए के शेयर बचे हुए थे.

ग्राफिकः असित रॉय

दिया था. बाद में नानू भाई ने उन गहनों को ओवरसीज मार्केट में ऊंची कीमत में बेचा. मुनाफे में ट्रस्टियों को भी अच्छा खासा हिस्सा मिला. इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ बताया जा रहा है.'' एंटीक ज्वेलरी बेचे जाने का जिक्र कामेश्वर सिंह की बड़ी पत्नी राजलक्ष्मी की डायरी में भी मिलता है. 30 मार्च, 1967 को वे लिखती हैं, ''ज्वेलर आए. ट्रस्ट के एग्जीक्यूटर ने सारा गहना उसे बेच दिया. मुझसे किसी ने एक दफा भी नहीं पूछा.''

दरअसल, ट्रस्टियों ने कामेश्वर सिंह की मौत के ठीक बाद ही लूट शुरू कर दी थी. मौत के एक महीने बाद ही 3 नवंबर, 1962 को ट्रस्टियों ने दो हवाई जहाज और 60,000 रुपए भारत सरकार को दान कर दिए. 10 जनवरी, 1963 को तत्कालीन वित्त मंत्री मोरारजी देसाई दरभंगा आए और उन्हें ट्रस्टियों ने 15 मन (600 किलो) सोने से तौल दिया और सारा खजाना भारत सरकार के डिफेंस फंड में दे दिया गया. उस वक्त देश चीन के साथ युद्ध लड़ रहा था. तेजकर झा कहते हैं, ''जो ट्रस्ट बना था, उसके एग्जीक्यूटर पटना हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे लक्ष्मीकांत झा थे और वे भारत सरकार के लॉ कमिशन के अध्यक्ष बनना चाहते थे. यह दरियादिली इसी काम के लिए दी गई रिश्वत थी. हालांकि वे कभी लॉ कमिशन के अध्यक्ष बन नहीं पाए. हां, खजाना कुछ ही सालों में खाली हो गया. उसके बाद जो थोड़ा-बहुत सोना और गहने बचे थे, वह कामेश्वर रिलीजियस ट्रस्ट के खजाने में बचे थे, जिस पर इन ट्रस्टियों का कोई जोर नहीं था. इसलिए अब उस खजाने पर ही सबकी नजर है.''

कामेश्वर रिलीजियस ट्रस्ट का गठन 16 मार्च, 1949 में कामेश्वर सिंह के जीवित रहते ही हुआ था. नियमानुसार इस ट्रस्ट का प्रमुख राज दरभंगा का ही प्रमुख हो सकता था. सो उनके निधन के बाद बड़ी रानी राजलक्ष्मी ट्रस्टी बनीं. उनके भी निधन के बाद से छोटी रानी कामसुंदरी इसकी ट्रस्टी हैं, जो अभी 96 साल की हैं. 2003 में उन्होंने अपनी पावर ऑफ एटॉर्नी उदयनाथ झा को दी, जो उनकी बड़ी बहन के बेटे हैं. उनके निधन के बाद इस ट्रस्ट की जिम्मेदारी कपिलेश्वर सिंह के परिवार में जानी है.

कपिलेश्वर आरोप लगाते हैं, ''उदयनाथ झा को मालूम है कि मेरी दादी छोटी रानी के बाद ट्रस्ट हमारे पास आना है. उसके बाद इस ट्रस्ट की आमदनी और संपत्ति से उन्हें हाथ धोना पड़ेगा. शायद इसीलिए अब वे इस ट्रस्ट की संपत्ति बेचने में जुट गए हैं. इससे पहले भी वे रानी कामसुंदरी के आवास को रानी के जरिए अपने नाम दान करवा चुके थे. हमने एसडीएम कोर्ट जाकर इसे कैंसिल करवाया.''

अपने एटॉर्नी उदयनाथ झा के प्रति रानी कामसुंदरी की उदारता की वजह यह बताई जाती है कि रानी की शादी की हड़बड़ी की वजह से उदयनाथ झा की मां रोहिणी की शादी किसी गलत परिवार में हो गई थी, जहां उनका जीवन दुखमय गुजरा. रानी इस अन्याय की वजह खुद को मानकर इसकी कीमत चुकाना चाहती हैं.

इस प्रकरण में संपर्क किए जाने पर झा ने किसी भी तरह की टिप्पणी करने से साफ मना कर दिया. फोन पर इतना ही कहा कि ''अभी एसआइटी की जांच चल रही है, इसलिए मेरा कुछ भी कहना उचित न होगा.'' रानी ने भी बात करने से इनकार किया. कपिलेश्वर कहते हैं, ''रानी कामसुंदरी मेरी दादी हैं पर मेरे लिए भी उनसे मिलना मुश्किल है. राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण मिलने पर मैं दादी से आशीर्वाद लेने गया. उस वक्त भी झा मिलने से रोक रहे थे पर संयोग से दादी ने देख लिया और मुझे बुला लिया. मैंने आशीर्वाद लिया. उनके साथ एक फोटो लेना चाहता था. झा इससे भी रोक रहे थे. मगर दादी की अनुमति से मैंने तस्वीरें लीं.'' कपिलेश्वर का कहना है, ''इसी के बाद झा सक्रिय हुए और उन्होंने कामेश्वर रिलीजियस ट्रस्ट के सारे गहने बेच डाले. उन्हें लगा कि अगर दादी से मेरी निकटता हो गई तो उन्हें आगे दिक्कत होगी.''

''रानी कामसुंदरी मेरी दादी हैं पर मेरे लिए भी उनसे मिलना, उनके साथ खड़े होकर एक फोटो तक लेना मुश्किल है. उदयनाथ झा मुझे रोक देते हैं''

कपिलेश्वर सिंह, राजा कामेश्वर सिंह के भाई का पोता

महाराजा कामेश्वर सिंह के निधन के बाद सोना ही नहीं, अलग-अलग शहरों में उनकी कोठियां भी बिकने लगीं. बड़ी रानी राजलक्ष्मी की डायरी में जिक्र है कि 14 दिसंबर, 1963 को सौराठ की जमीन बिक गई. 15 फरवरी, 1964 को कलकत्ता का दरभंगा हाउस डेथ ड्यूटी चुकाने के लिए बेच दिया गया. यह ड्यूटी चुकाने के लिए एंटीक ज्वेलरी बेचे जाने का भी जिक्र मिलता है. पर डेथ ड्यूटी इसके बाद भी चुकाई नहीं जा सकी. यह जिक्र भी है कि संपत्ति के एक अन्य ट्रस्टी मुकुंद झा, जो कामेश्वर सिंह के बड़े बहनोई थे, ने इलाहाबाद की कोठियां अपने बेटे के नाम ट्रांसफर करा लीं.

तेजकर झा कहते हैं, ''रानी की डायरी में सिर्फ गहनों और कोठियों के बिकने की बातें दर्ज हैं. मगर राज दरभंगा की संपत्ति सिर्फ इतनी ही नहीं थी. कई बड़ी कंपनियां थीं. महाराजा कामेश्वर सिंह ने देश-दुनिया के शेयर बाजारों में भी पैसा लगा रखा था. इन शेयरों का क्या हुआ, किसी को नहीं मालूम.'' गौरतलब है कि 1987 में पारिवारिक समझौते के तहत राज दरभंगा की संपत्ति का बंटवारा होने पर पता चला था कि उस संपत्ति

राज और रिश्ते महाराजा कामेश्वर सिंह की बड़ी रानी राजलक्ष्मी (एकदम बाएं); कामेश्वर सिंह छोटी रानी कामसुंदरी के साथ. दोनों के लिए उन्होंने वसीयत में मासिक पेंशन की व्यवस्था कराई थी

में तकरीबन 63 लाख रुपए के शेयर थे. तेजकर झा इस समझौते पर भी सवाल उठाते हैं, ''पहली बात तो जिसे 1961 की महाराजा की वसीयत कहा जाता है, उसमें कहीं भी यह जिक्र नहीं कि महाराजा के पास कुल कितनी संपत्ति थी. बस इतना कहा गया कि संपत्ति के तीन ट्रस्टी होंगे: जस्टिस लक्ष्मीकांत झा, गिरींद्र मोहन मिश्र और उनके बहनोई मुकुंद झा. लक्ष्मीकांत झा एग्जीक्यूटर होंगे. दोनों रानियों को रहने के लिए एक-एक महल और महीने के 5,000-5,000 रुपए मिलेंगे. दोनों रानियों के निधन के बाद संपत्ति भतीजों की हो जाएगी. साथ ही संपत्ति का एक-तिहाई हिस्सा लोकहित के लिए रहेगा. कामेश्वर सिंह जो इस तरह के मामले के अच्छे जानकार थे, वे वसीयत में अपनी तमाम चल-अचल संपत्ति का जिक्र करना कैसे भूल गए! दूसरी बात, साल भर पहले ही उन्होंने लंदन के लॉएड्स बैंक को चिट्ठी लिखी थी कि वह उनकी 1958 की वसीयत को सुरक्षित रखे. इसलिए यह मामला संदिग्ध लगता है.''

उनके शब्दों में, ''अगर यह वसीयत सच भी थी तो उसको खारिज कर अदालत ने कैसे फैमिली सेटलमेंट करा दिया.'' सेटलमेंट के तहत संपत्ति छोटी रानी और उनके भतीजों के बीच बांटी गई. अब एक-तिहाई के बदले एक-चौथाई संपत्ति लोकहित के लिए छोड़ी गई थी. बड़ी रानी का निधन 1976 में ही हो गया था. हालांकि बड़ी रानी की डायरी के आखिरी दिनों के पन्ने इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इमरजेंसी के दौरान राज दरभंगा की संपत्ति का तेजी से सरकारीकरण हुआ. वे लिखती हैं, ''26 अगस्त, 1975 को बिहार सरकार ने अपने मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र की अगुआई में दरभंगा राज का मुख्य कार्यालय ले लिया. 3 सितंबर, 1976 को जगन्नाथ मिश्र ने दरभंगा शहर में राज की 300 बीघा जमीन के लिए 70,000 रुपए के मुआवजे की पेशकश की, जिसे ट्रस्टियों ने स्वीकार कर लिया.'' वे आरोप लगाती हैं कि ट्रस्टियों ने ऐसा करने के लिए सरकार से रिश्वत ली. वहां जो विश्वविद्यालय बना वह ललित नारायण मिश्र के नाम से बना. 10 अक्तूबर को वे राज के महल नरगौना पैलेस के सरकारी अधिग्रहण की सूचना भी देती हैं.

बड़ी रानी जो सूचना नहीं दे पातीं, वह उन फैक्टरियों के अधिग्रहण के बारे में है, जिसे बिहार सरकार ने निगम बनाकर अपने कब्जे में ले लिया था. मगर ऐसा माना जाता है कि इमरजेंसी और उसके बाद के वर्षों में राज दरभंगा के स्वामित्व वाली ज्यादातर फैक्ट्रियों का अधिग्रहण कर लिया गया. राज दरभंगा के मामलों पर लगातार शोध करने और सोशल मीडिया पर मुखर लेखन करने वालीं कुमुद सिंह कहती हैं, ''इन अधिग्रहणों के पीछे एक पैटर्न है. ज्यादातार अधिग्रहण कंपनी को बंद करने के इरादे से किए गए लगते हैं. जिन कंपनियों का अधिग्रहण हुआ वे एक दशक के अंदर बंद हो गईं.'' चीनी मिलों के अधिग्रहण की कथा बताते हुए कुमुद कहती हैं, ''बिहार विधान परिषद में दरभंगा स्नातक क्षेत्र से विधान पार्षद और जगन्नाथ मिश्र के करीबी कमलनाथ सिंह ठाकुर ने लोहट समेत तमाम चीनी मिलों में अस्थायी कर्मचारियों के आंदोलन को आधार बनाकर प्रस्ताव दिया कि सरकार को इलाके में रोजगार के संरक्षण के लिए अधिग्रहण कर लेना चाहिए. अस्सी के दशक में इन मिलों का अधिग्रहण हुआ और नब्बे के दशक में वे बंद हो गईं. इसके पीछे कहीं न कहीं दरभंगा राज के प्रति संजय गांधी की नाराजगी भी थी. अस्सी के दशक में मारुति उद्योग में दरभंगा राज के शेयरों को भी ट्रस्टियों पर दबाव बनाकर औने-पौने बिकवा दिया गया. समस्तीपुर की जूट मिल भी अधिग्रहीत हो गई और अब जैसे-तैसे चल रही है.''

कुछ ऐसी ही कहानी अपने जमाने की एशिया की सबसे बड़ी अशोक पेपर मिल की है. इसकी इकाई बिहार और असम दोनों राज्यों में थी. राज दरभंगा की कंपनियों के लेबर अफसर विश्वबंधु बिनोदानंद झा अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, ''पहले तो इस पेपर मिल की असम इकाई को राज दरभंगा के ट्रस्ट एग्जीक्यूटर लक्ष्मीकांत झा बेचना चाहते थे मगर उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के प्रयासों से इसे बेचा नहीं जा सका. बाद के राजनेताओं ने खास तौर पर मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र ने अपने राजनैतिक हस्तक्षेप के जरिए इसे ठीक से चलने नहीं दिया. यह भ्रष्ट राजनेताओं का चारागाह बन गया.''

इस पूरे प्रकरण में यह जानकारी नहीं मिलती कि उस पब्लिक ट्रस्ट का क्या हुआ जिसकी वसीयत महाराजा कामेश्वर सिंह ने लोकोपकारी कार्यों के लिए की थी. इसके लिए पहले उनकी एक तिहाई संपत्ति तय की गई थी, बाद में फैमिली सेटलमेंट के जरिए उसे एक-चौथाई कर दिया गया. कुमुद सिंह कहती हैं, ''उस ट्रस्ट में अभी भी काफी पैसा होना चाहिए, क्योंकि उसकी लूट इतनी आसानी से नहीं हो सकती. पर मेरी जानकारी में उस पैसे से बस एक अस्पताल चल रहा है.'' उसके ट्रस्टियों में से एक कपिलेश्वर सिंह कहते हैं, ''मैं और मेरे बड़े भाई ट्रस्ट के पैसों से नियमित हेल्थ कैंप लगाते हैं और दिव्यांगों को ट्राइसाइकिल और दूसरे उपकरण बांटते हैं.'' अपनी किताब *क्राइसिस ऑफ सक्सेशन* के हवाले से तेजकर झा बताते हैं, ''1951 में एक बार वे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति रहे डॉ. अमरनाथ झा के साथ पूर्णिया सोरैया राज की पुरानी कोठियों को देखने गए. उन्हें देख कामेश्वर सिंह भावुक हो गए और रोने लगे. अमरनाथ झा ने कारण पूछा तो बोले, मैं इनमें अपने घर, परिवार और राज दरभंगा का भविष्य देख रहा हूं.'' सच! ■

(बाएं से) **राज चेंगप्पा,** एडिटोरियल डायरेक्टर, इंडिया टुडे ग्रुप; **निगार शाजी,** परियोजना निदेशक, आदित्य एल1 सौर मिशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन; **प्रोफेसर अन्नपूर्णी सुब्रह्मण्यम,** निदेशक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऐस्ट्रोफिजिक्स

बराबरी पर बात

इंडिया टुडे वुमन समिट में विभिन्न क्षेत्रों की नायिकाओं ने एक मंच पर आकर महिलाओं की सफलता का जश्न मनाने के साथ ही लैंगिक समानता और सशक्तीकरण पर मंथन किया

सुहानी सिंह

चेन्नै में 9 फरवरी को संपन्न इंडिया टुडे वुमन समिट-जेंडर इक्विटी में किसी ऐसे पुरुष के लिए जगह नहीं थी जो महिलाओं पर अपनी बिन मांगी सलाह थोपते हैं. यह एक ऐसा मंच था जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी महिलाओं के अपने मुकाम तक पहुंचने के दौरान आई चुनौतियों और अनुभवों को साझा किया गया. बतौर दर्शक मौजूद युवाओं और खासकर महिलाओं ने कला क्षेत्र की दिग्गजों (कर्नाटक संगीत गायिका अरुणा साईराम, भरतनाट्यम नृत्यांगना नर्तकी नटराज और अभिनेत्री पूजा हेगड़े) के अलावा विज्ञान एवं चिकित्सा (भारत बायोटेक की सुचित्रा एला, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की निगार शाजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऐस्ट्रोफिजिक्स की निदेशक प्रो. अन्नपूर्णी सुब्रह्मण्यम और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान की निदेशक डॉ. प्रतिमा मूर्ति) और उद्योग क्षेत्र में अपना परचम लहराने वाली विभिन्न हस्तियों (अवतार ग्रुप की फाउंडर-प्रेसिडेंट सौंदर्या राजेश, नल्ली ग्रुप ऑफ कंपनीज की उपाध्यक्ष लावण्या नल्ली, एमजीएम हेल्थकेयर की निदेशक डॉ. उर्जिता राजगोपालन, ब्यूटी लेबल जूसी केमिस्ट्री की को-फाउंडर मेघा आशर और स्वीट करम कॉफी की को-फाउंडर नलिनी पार्थिबन) की जुबानी उनके अपने जीवन के अनुभवों को जाना.

इंडिया टुडे ग्रुप के एडिटोरियल डायरेक्टर राज

▼ अंतरिक्ष क्षेत्र में महिलाएं: नई उड़ान, नया मुकाम

सबक

» "कड़ी मेहनत से ज्यादा जरूरी है, काम करने का स्मार्ट तरीका. सबसे महत्वपूर्ण है कि आप कहां फोकस करना चाहते हैं, किस टैलेंट को निखारना चाहते हैं. बेहतर होगा कि उस पर ध्यान केंद्रित करें और उसमें दक्षता हासिल करें"
प्रोफेसर अन्नपूर्णी सुब्रह्मण्यम

» "सामाजिक स्तर पर तो हमेशा यह महसूस कराया जाता रहेगा कि तमाम काम हमारी क्षमता से बाहर हैं. आप अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा रखें, और पूरी दृढ़ता के साथ कड़ी मेहनत करें. फिर आप कुछ भी करने में सक्षम होंगे"
निगार शाजी

चेंगप्पा ने कहा कि भारत की प्रगति के लिए जरूरी है कि वह ''लैंगिक समानता मिटाने में अग्रणी'' बने और इसके लिए पांच क्षेत्रों पर खास ध्यान देने की जरूरत है—कार्यबल भागीदारी और वेतन समानता; शिक्षा और सशक्तीकरण; स्वास्थ्य देखभाल संबंधी असमानताएं दूर करना; कानूनी और सामाजिक अधिकार सुनिश्चित करना और नेतृत्व में प्रतिनिधित्व.

विविधतापूर्ण संगठन के निर्माण पर सौंदर्या राजेश ने कहा, ''समानता ही बराबरी का दर्जा देने का रास्ता है.'' अध्ययन सौंदर्या राजेश के इस तर्क की पुष्टि करते हैं कि विविध कार्यबल वाले संगठन ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हैं. उनका कहना है कि 'सही मायने में बदलाव' तभी आता है ''जब आपके पास शीर्ष नेतृत्व पर महिलाएं हों.''

सुचित्रा एला सही मायने में महिलाओं की शक्ति से वाकिफ हैं. जब उनसे उन विशेष नेतृत्व गुणों के बारे में पूछा गया, जो प्रबंधन में महिलाओं की बदौलत आते हैं, और जिनमें पुरुषों का दखल नहीं होता तो एली ने लैंगिक-आलोचना की बात न करके कहा, ''मुझे लगता है कि महिलाएं स्वाभाविक तौर पर मल्टी-टास्कर होती हैं...यह गुण इस हद तक समाया होता है कि आप घर या दफ्तर की चिंता को लेकर विचलित नहीं होतीं.'' दो बच्चों की मां एला ने आगे विस्तार से बताया कि कैसे कामकाजी मांएं अक्सर दफ्तर में लंबे समय तक रहने पर अपराधबोध का अनुभव करती हैं. उन्होंने बताया कि कभी बच्चों को जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपने दफ्तर में ही कैसे उनका होमवर्क करवाया.

एला और अरुणा साईराम दोनों ने इस बात पर जोर दिया कि पति का सहयोग बहुत ज्यादा मायने रखता है. साईराम तो इस मौके पर दर्शकों के बीच मौजूद अपने पति को धन्यवाद देना नहीं भूलीं, जिन्होंने मुंबई में अपनी नौकरी छोड़ दी और 2002 में चेन्नै जाकर बस गए ताकि उनकी पत्नी का म्यूजिक करियर फल-फूल सके. साईराम ने कहा, ''उन महिलाओं ध्यान रखें जो आपके जीवन का हिस्सा हैं. हो सकता है, उनमें कोई खास गुण हो लेकिन विभिन्न कारणों या हिचक की वजह से वे कुछ न कह पा रही हों...देखिए वे कहां से कहां पहुंच जाएंगी.''

लेकिन हर किसी को अपने परिवार का समर्थन नहीं मिलता. नर्तकी नटराज के मामले में यही हुआ, 10 साल की उम्र में पता चला कि व एक ट्रांसजेंडर हैं. नटराज ने बताया कि कैसे उन्हें अपने गांववालों के ताने और बहिष्कार झेलना पड़ा. वे बताती हैं, ''मुझे

सभी फोटो: चंद्रदीप कुमार

(बाएं से) **सौंदर्या राजेश,** *संस्थापक-अध्यक्ष, अवतार ग्रुप;* **लावण्या नल्ली,** *उपाध्यक्ष, नल्ली ग्रुप ऑफ कंपनीज;* **डॉ. उर्जिता राजगोपालन,** *निदेशक, एमजीएम हेल्थकेयर*

▲ परिचर्चा: विविधतापूर्ण संस्थानों का निर्माण

सबक

"खुद पर पूरा भरोसा करें, संकल्प करें कि स्थितियां चाहे जो भी हों, आपको कार्यबल का हिस्सा बने रहना है. रास्ते में थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं लेकिन आप खुद से वादा करें कि आप सारी बाधाएं पार कर लेंगी क्योंकि आपकी आर्थिक आत्मनिर्भरता में ही आपकी स्वतंत्रता है. यही आपके सशक्तीकरण का आधार है"
सौंदर्या राजेश

एक कहावत है कि कड़ी मेहनत को चुनें, जीवन अपने-आप आसान हो जाएगा. शादी कठिन है, अकेला रहना कठिन है, तलाक लेना कठिन है, काम करना कठिन है, मां बनकर घर संभलाना कठिन है. मैं तो यहीं कहूंगी, आप आर्थिक स्वतंत्रता को चुनें. विश्वास कीजिए इसका अवसर मिलना आपको सशक्त बनाएगा"
लावण्या नल्ली

"आप जीवन के किसी भी दौर में हों, अपने बारे में सोचना और खुद पर मेहनत करना बेहद जरूरी है"
डॉ. उर्जिता राजगोपालन

डॉ. प्रतिमा मूर्ति, *निदेशक, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान*

▲ सवाल-जवाबः महिलाएं और मानसिक स्वास्थ्य—कैसे रखें मन का ख्याल

सबक

''स्वीकार करें कि उतार-चढ़ाव हमारे अस्तित्व का हिस्सा हैं. अपना ख्याल रखना सीखें. मानसिक स्वास्थ्य के मामले में सेल्फ-केयर सबसे महत्वपूर्ण है. इसका मतलब है कि आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपका व्यवहार, इसके बारे में आत्मनिरीक्षण करना और उन चीजों को बदलना जिन्हें आप उचित रूप से बदल सकते हैं, सब बहुत महत्वपूर्ण हैं. शारीरिक व्यायाम की तरह ही मन को आराम देना भी महत्वपूर्ण है. तनाव दूर करने के लिए किसी प्रकार का उपाय करें—चाहे वह माइंडफुलनेस हो, योग हो, सैर करना हो या संगीत सीखना हो''

▼ सवाल-जवाबः बने-बनाए ढांचे को तोड़ना

सबक

''कड़ी मेहनत करें, हार मत मानें और आकाश को अपनी सीमा मानें. उद्यमिता बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है. इसमें कदम रखने के लिए व्यक्ति को बड़ा सोचना होगा और उसे पूरा करने का सपना देखना होगा. छोटी शुरुआत करें, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि आपका ध्यान केंद्रित रहे और पथ पर बने रहें. फिर इसे बेहतर, सर्वश्रेष्ठ और बड़ा बनाने के लिए आगे बढ़ें''

सुचित्रा एला, *सह-संस्थापक और मैनेजिंग डायरेक्टर, भारत बायोटेक*

पूजा हेगड़े, *अभिनेत्री*

◀ सवाल-जवाबः एकाधिक भाषाओं में अपना लोहा मनवाया

सबक

''बाधाओं के बारे में मत सोचें. मुझे बाधाओं को हराना पसंद है. बस अपने आप से बात करें और खुद को उत्साहित करें. अगर आप इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं और खुद पर निवेश करते हैं, तो आप वास्तव में हर बाधा को पार कर सकते हैं. और प्रसिद्धि के पीछे मत भागें''

(बाएं से) **नर्तकी नटराज,** भरतनाट्यम नर्तकी और योजना आयोग की सदस्य, तमिलनाडु; **अरुणा साईराम,** कर्नाटक संगीत विशेषज्ञ और संगीतकार

▲ महिलाओं की नजर से: कला क्षेत्र में क्रांति

सबक

''स्वयं को सम्मान दें. चीजों के साथ आगे बढ़ें. अपनी वास्तविक क्षमता तक पहुंचने के लिए समर्थन की अपेक्षा न करें. बस अपने आप से प्यार करें. यह आपके करियर की उपलब्धि के लिए पर्याप्त है''

नर्तकी नटराज

''श्रद्धा और सबुरी. इसका मतलब है एक ओर दृढ़ विश्वास और निरंतर प्रयास और दूसरी ओर धैर्य. ये दो गुण आपको वहां ले जाएंगे जहां आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं''

अरुणा साईराम

कभी अपने घर का दरवाजा खोलने पर आजादी का सुखद एहसास नहीं हुआ. मुझे पता होता था कि मुझे झिझक और अपमान का सामना करना पड़ेगा.'' बहरहाल, समय बीतने के साथ नटराज इस सबको अनदेखा करने की आदी हो गईं और समाज में अपने लिए सम्मान कमाया. वे कहती हैं, ''समाज ने हमारे लिए कभी कोई सम्मानजनक नाम नहीं गढ़ा. मैं समाज के लिए कोई दर्शनीय वस्तु नहीं हूं. मैंने हमेशा खुद को एक क्वीन माना.'' नटराज ने 'थिरुनांगई' शब्द गढ़ा है, जिसका इस्तेमाल तमिलनाडु में इस समुदाय के सदस्यों के लिए किया जाता है.

नटराज की इस दृढ़ता को लावण्या नल्ली काफी सराहती हैं और कहती हैं महिलाओं के लिए किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए यह गुण बेहद जरूरी है. पारिवारिक व्यवसाय में कदम रखने के साथ लावण्या को भी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा. वे कहती हैं, ''मुझे काम करने दिया गया तो इसके पीछे मानसिकता यही थी कि शादी होने तक नौकरी कर लेने दो.'' अमेरिका में मैकेंजी के साथ काम करके अपनी साख बनाने के बाद नल्ली को लगा कि फिर अपनी कंपनी में लौटने पर उन्हें 'अधिक गंभीरता' से लिया गया. उन्होंने बताया कि विवाहित कामकाजी महिलाओं के लिए ''सपोर्ट सिस्टम'' इस वक्त की महती जरूरत है.

मेघा आशर के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता और वित्तीय स्थिरता सबसे ज्यादा मायने रखती है. महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन पर एक सत्र में, उन्होंने सोशल मीडिया को उद्यमशीलता की भावना बढ़ाने में सबसे आगे बताया और कहा, ''यह असीमित संभावनाओं से भरा आकाश है.'' उनका मानना है कि महिलाओं को शहीद बनने की मानसिकता से बाहर आने की जरूरत है. नलिनी पार्थिबन ने पाया कि स्वीट करम कॉफी के साथ एक डिजिटल-फर्स्ट ब्रांड चलाना संभव हो सकता है और साथ ही यह जाना कि नेटवर्किंग एक ब्रांड की प्रोफाइल को कैसे मजबूत कर सकती है. उनके मुताबिक, स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को लेकर जागरूकता और समर्थन में महिला उद्यमी पीछे नहीं हैं. वे कहती हैं, ''अगर कोई अन्य महिला सामने है तो उसके प्रति रवैया नरम होता है.'' उनकी सलाह है, ''हर दिन की असहजता को लेकर बेपरवाह रहें... समाधान खोजने वाले बनें, समस्या खोजने वाले नहीं.''

डेलॉइट की 2023 की रिपोर्ट दर्शाती है कि भारत में कामकाजी महिलाओं में तनाव उच्च स्तर पर होता है. डॉ. प्रतिमा मूर्ति का कहना है कि सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश के दबाव और कमतर आंके जाने

सतीश कुमार

(बाएं से) **मेघा आशर,** *सह-संस्थापक और सीओओ, जूसी केमिस्ट्री;* **नलिनी पार्थिबन**, *सह-संस्थापक और सीईओ, स्वीट करम कॉफी*

की वजह से महिलाओं में अवसाद और चिंता जैसे सामान्य मानसिक विकार होने की संभावना अधिक होती है. मूर्ति के मुताबिक, ''अक्सर माहौल की बात की जाती है जिसका दायरा वास्तव में काफी बड़ा होता है, और यहीं पर हमें उन नीतियों, कार्यक्रमों पर ध्यान देने की जरूरत है जो वास्तव में महिलाओं को निष्पक्ष ढंग से और न्यायसंगत मौका मुहैया कराने में मददगार साबित हों.'' उन्होंने कहा कि महिलाएं काफी 'सहनशील' होती हैं, और इस वजह से ज्यादातर चीजों को खुद तक सीमित रखती हैं. यही वजह है कि उन्हें यह सिखाना जरूरी होता है कि वे अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें.

आदित्य एल-1 सौर मिशन की निदेशक रहीं निगार शाजी कहती हैं, आपको हर कदम पर ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको कमजोर साबित करने की कोशिश करेंगे. ''...अपनी योग्यता और अपने ज्ञान के बल पर उन्हें दिखा दीजिए कि आप भी सम्मान की हकदार हैं.'' प्रोफेसर अन्नपूर्णी सुब्रह्मण्यम ने कहा, विज्ञान के क्षेत्र में उन महिलाओं के लिए उच्च डिग्री हासिल करना और पब्लिकेशन में काम करना दोगुना कठिन है, जिनके पास अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में काफी कम समय होता है, क्योंकि उन्हें 'पारिवारिक जिम्मेदारियों' से भी जूझना पड़ता है. मातृत्व के बाद महिलाओं को फिर कार्यबल का हिस्सा बनाने के बारे में संगठनों को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है. उन्हें महिलाओं को अपने बच्चे को कार्यालय लाने या फिर घर से काम करने की अनुमति देने पर सोचना चाहिए.

एक के बाद एक छह ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाली और तमिल, तेलुगु और हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सितारों के साथ काम कर चुकीं अभिनेत्री पूजा हेगड़े कहती हैं, महिलाओं के लिए और अधिक फिल्में लिखे जाने की जरूरत है. वे कहती हैं, ''जब तक आप ऐसी फिल्में नहीं बनाएंगे तब तक ऐसे दर्शक कहां से आएंगे?''

आयोजन के दौरान सिर्फ गंभीर बातें ही नहीं हुईं, बल्कि साईराम और नटराज ने साथ मिलकर 'कृष्णा नी बेगाने बारो' भजन गाया और दर्शकों को भक्तिमय माहौल में सराबोर कर दिया. लोगों ने उनके प्रदर्शन पर खड़े होकर तालियां बजाईं. हेगड़े ने एक बार नहीं बल्कि तीन बार अपने नृत्य कौशल से दर्शकों को 'अरेबिक कुथु' और 'बुट्टा बोम्मा' पर थिरकने को बाध्य कर दिया. कुल मिलाकर, आयोजन में नारी शक्ति का बोलबाला रहा. ■

▲ महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए क्या करना होगा?

सबक

''यह सुनने में भले ही घिसा-पिटा लगे, मगर कोई शॉर्टकट नहीं है. आपको कीचड़ में उतरना होगा, और अपने व्यवसाय के हर एक पहलू को सीखना होगा. हर छोटे विवरण को जानना महत्वपूर्ण है, अन्यथा, आपका व्यवसाय आपकी अपेक्षा के अनुरूप सफल नहीं होगा''

मेघा आशर

''उद्यमिता कभी भी आरामदायक यात्रा नहीं होती. इसलिए, हर दिन असहज होने से सहज हो जाएं. हर तरफ से समस्याएं पैदा होंगी. हालांकि, उन्हें सभी दिशाओं से आने वाली चुनौतियों के रूप में देखें. आपको समस्या बताने वाला नहीं, बल्कि समाधान खोजने वाला बनने की आवश्यकता है''

नलिनी पार्थिबन

स्मृतिः उषाकिरण खान (1945-2024)

अपने ही पंथ की अनूठी उषा

कोसी की आंचलिक संवेदनाएं लेकर निकली यह सहज-सरल लेखिका कभी किसी खास विचारधारा में नहीं बंधी

पुष्यमित्र

उषाजी नहीं रहीं. भले ही वे 78 साल की हो गई थीं, कई दफा सार्वजनिक आयोजनों में व्हीलचेयर पर नजर आती थीं, कभी-कभी बीमार होने के चलते किसी जलसे में नहीं भी पहुच पातीं. फिर भी बिहार, खासकर पटना के साहित्यिक-सांस्कृतिक-सामाजिक हलकों में उनकी लगभग सतत मौजूदगी रहती. तभी तो इतवार 11 फरवरी की दोपहर उनके निधन की खबर पर उन्हें जानने-चाहने वालों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी: अरे! हम जैसे पत्रकारों को लगता था कि मिथिला, बिहार, साहित्य, स्त्री, इतिहास, संस्कृति किसी भी मसले पर उनसे कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है.

सात साल पहले दिल्ली के विश्व पुस्तक मेले में उन्होंने मेरी पहली किताब *रेडियो कोसी* का विमोचन किया था. कुछ दिनों बाद उन्होंने फोन करके बताया कि किताब उन्होंने पूरी पढ़ ली है और इसमें एक-एक अक्षर सही लिखा है. वे कोसी के इलाके की थीं. उनकी कहानियों में कोसी के पेट में उगने वाले पटेर के रंग हैं, वहां के जीवन का संघर्ष और वहां की औरतों की कहानियां हैं. उसके बाद मेरा उनसे सहज रिश्ता बनता चला गया. पर उनके जाने के बाद सोशल मीडिया पर सैकड़ों लोगों के संस्मरणों से पता चला कि हर पीढ़ी के अनुभवी और नए लेखकों के साथ उनके रिश्ते थे. हिंदी में भी और मैथिली में भी. कोई उन्हें अम्मा बुला रहा था, कोई दीदी, कोई मां. सबके लिए वे उतनी ही सहजता से उपलब्ध रहतीं. वह लेखक हो, पत्रकार, आयोजक या पाठक.

दरभंगा में एक सामाजिक अभियानी जगदीश चौधरी के घर जन्मी उषाकिरण खान को बचपन से कोसी के पेट पकड़िया गांव में उस समाज के बीच रहने का मौका मिला जो सबसे अधिक वंचित था. पिता वहां लोगों की मदद करने गए थे और आश्रम भी खोला था. उनके जीवन में भीषण पढ़ाकू रामचंद्र खान जैसे पति का लंबा साथ रहा. हाल के वर्षों में ही उन्होंने विवाह की पचासवीं वर्षगांठ का आयोजन किया था, जो एक साहित्यिक आयोजन सरीखा ही हो गया था. रामचंद्र खान की चर्चा एक सख्त पुलिस अधिकारी के तौर पर भी रहती थी. इलाके के अपराधी उनके नाम से कांपते, ऐसी कथाएं हमने सुनीं. हिंदी के जन कवि बाबा नागार्जुन जो मैथिली में वैद्यनाथ मिश्र यात्री के नाम से जाने जाते थे, उनके लिए पिता तुल्य थे. वे उनकी कहानियां अक्सर सुनातीं. नागर्जुन और पति के बीच हुए झगड़े के बारे में भी बतातीं. इस विरासत ने उनके लेखन को अत्यंत समृद्ध किया और वे लगातार कोसी के दर्द और इतिहास के किरदारों की कहानियां हिंदी/मैथिली दोनों में उकेरती रहीं. ग्रामीण जीवन पर उनके प्रामाणिक लेखन को देखकर ही *हंस* के संपादक राजेंद्र यादव ने कहा था, ''फणीश्वरनाथ रेणु के बाद उषाकिरण खान की रचनाओं में ही गांव के मिट्टी की खुशबू मिलती है.''

उन्होंने इतिहास और पुरातत्व की पढ़ाई की और इसी विषय को अरसे तक पढ़ाया भी. उनके कई उपन्यास ऐतिहासिक किरदारों पर केंद्रित हैं. चाहे कवि विद्यापति के जीवन पर आधारित पुस्तक *सिरजनहार* हो, या शेरशाह सूरी पर लिखी गई किताब *अगन हिंडोला* या फिर मिथिला के रहने वाले टीकाकार वाचस्पति मिश्र की पत्नी की कहानी पर मैथिली उपन्यास *भामती.* उनके जीवन और लेखन पर पुस्तक लिखने वाले वरुण कहते हैं, ''उन्होंने इतिहास की किताबें तो लिखीं पर जेपी आंदोलन के बाद के दिनों को लेकर उन्होंने जो कहानियां और उपन्यास लिखे, वे भी किसी इतिहास से कम नहीं.'' 1977 से शुरू कर उन्होंने 46 किताबें लिखीं. इन दिनों वे बहादुरशाह जफर के पोते गोरगन के जीवन पर उपन्यास लिख रही थीं, जिन्हें आखिरी दिनों में राज दरभंगा ने शरण दी थी और दरभंगा में ही जिनकी कब्र है.

स्त्री रचनाकारों पर आलोचकों की निगाह न जाने पर वे कहती थीं कि हमें अपने बीच से समीक्षक तैयार करने होंगे. उन्होंने महिला संगठन भी बनाए पर नारीवादी कभी नहीं रहीं

उन्होंने हिंदी और मैथिली की महिलाओं के संगठन बनाए और कई अभियान चलाए. आखिरी दिनों में उन्होंने पटना में आयाम संस्था बनाकर बिहार की स्त्री रचनाकारों को उससे जोड़ा. 2022 में पति रामचंद्र खान गुजर गए तो अगले साल उनकी याद में उन्होंने पटना में बड़ा साहित्यिक उत्सव किया, जो आज भी लोगों के जेहन में है. वे स्त्री रचनाकारों पर आलोचकों की निगाह न जाने को लेकर दुखी रहती थीं और अक्सर कहतीं कि हमें अपने बीच से समीक्षक तैयार करने होंगे. वे महिलाओं की आजादी की पक्षधर थीं. कुछ साल पहले एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया था कि कई लेखिकाओं की रचनाएं छपने से पहले उनके पति सेंसर करते हैं. यह स्थिति अब बदलनी चाहिए.

पर वे खुद को नारीवादी नहीं कहतीं. न वे वामपंथी थीं, न दक्षिणपंथी. वे बीच में कहीं थीं. वे राजनैतिक मुद्दों पर बहुत टिप्पणियां नहीं करती थीं मगर जो बातें उन्हें गलत लगतीं, उस पर टिप्पणी करने से खुद को रोकती नहीं, भले उनके रिश्ते खराब हो जाएं. मैथिली लेखक और रंगकर्मी कुणाल कहते हैं, ''कई मामलों में मैं उन्हें अग्रज मानता था क्योंकि उन्होंने उन संस्थाओं के खिलाफ खुला स्टैंड लिया जो धनबल के बूते रचनाकारों को अक्सर लाभ पहुंचातीं. ज्यादातर रचनाकार ऐसी संस्थाओं के मसले पर चुप्पी साध लेते. मगर वे लगातार विरोध करती रहीं.''■

फाइटर सदाबहार

अभिनेता ***ऋतिक रोशन*** *अपनी हालिया रिलीज ऐक्शन फिल्म फाइटर और आगे के प्रोजेक्ट्स के बारे में*

● *फाइटर* की कामयाबी पर लोगों की राय अलग-अलग है, आप क्या मानते हैं?

फाइटर ने एक हफ्ते में दुनिया भर में 250 करोड़ रु. कमाई का आंकड़ा पार किया. दर्शकों की बात करें, तो सभी ने इसे प्यार दिया. नाक-भौं सिकोड़ने वालों की मानें तो थिएटर में कौवे बोल रहे थे. एक ऐक्टर और कड़ी मेहनत से काम करने वाली टीम के सदस्य के नाते मैं यही कहूंगा कि फिल्म बहुत सराही गई. दुनिया भर के दर्शक इसे देखने को अगर लाइन लगाए हुए हैं तो मेरे ख्याल से यह इसकी कामयाबी है.

● खालिस ऐक्शन से लेकर चॉकलेटी रोल तक आप सब कुछ कर रहे हैं. आपकी अपनी पसंद क्या है?

बस अपने हिस्से का काम करना चाहता हूं, उसमें जो भी आए. ऐक्शन तभी किया जा सकता है जब ऐक्टर पूरी तरह फिट हो. ऊपर वाले की दुआ है कि मैं अब तक ऐक्शन सीक्वेंस कर रहा हूं. चाहता हूं कि खुद को लगातार बेहतर करता रहूं और दिमाग की बनाई हदों से लड़कर उनके पार जा सकूं.

● कौन-सी एक चीज है जिसे आप बेहतर करना चाहते हैं?

काम से पहले होने वाली घबराहट. खासतौर से किसी इंटेंस सीन से पहले. मसलन अगर कोई इमोशनल सीन है तो उससे पहले मैं कुछ देर अकेले बैठना चाहता हूं ताकि उस जोन में जा सकूं. डायरेक्टर और बाकी लोगों से कहता हूं कि उस सीन के ज्यादा टेक लें. जितने ज्यादा टेक होंगे वह उतना ही स्वाभाविक होगा.

● इस साल और किन प्रोजेक्ट्स में आप दिखाई देंगे?

फरवरी के अंत में हम *वॉर 2* शुरू करने जा रहे हैं. मैं जूनियर एनटीआर के साथ काम करने को लेकर उत्साहित हूं. *क्रिश 4* की स्क्रिप्ट पर काम खत्म हो चुका है और इस पर मेरा पूरा फोकस रहेगा. ये फिल्में खत्म हो जाएं तो मैं सिचुएशनल कॉमेडी जैसा कुछ करना चाहता हूं. शायद इससे मुझे थोड़ा आराम मिल जाए.

– आरती कपूर सिंह